20 मई, 2026 ✯ वर्ष 35, पृष्ठ संख्या 80, अंक 05

राजस्थान सुजस

सुनहरा आज, सुरक्षित कल
अन्नदाता
की हर समस्या का हल

शब्द भावना

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र हित में विभिन्न विषयों पर की गई अपील का देशभर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी पेट्रोल एवं डीजल की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।"

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के अनुरूप राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए समर्पण भाव के साथ कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार पिछले सवा दो साल में प्रदेश के विकास का रोडमैप बनाकर काम कर रही है।
- राज्य सरकार सैनिक कल्याण के लिए सजग होकर निरन्तर कार्य कर रही है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्राम और वार्ड के सुनियोजित विकास के लिए विकसित ग्राम-वार्ड अभियान की दूरगामी पहल की है।
- विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्य के क्रम में युवा, महिला, किसान और मजदूर का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार उद्यमियों को निवेश अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
- राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए समर्पण के साथ कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
- गांव की महिलाओं का आर्थिक विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
- राज्य सरकार प्रदेश को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
- राइजिंग राजस्थान ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है।
- राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी के भरपूर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- राज्य सरकार विमुक्त, घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू समुदायों के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है।
- महिला सशक्तीकरण और युवाओं के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए भी राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार गांव और किसान को सशक्त करने का कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें रोजगार प्रदाता बनाने के लक्ष्य पर कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं को धरातल पर उतार रही है।
- राज्य सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में 6 लाख एवं सरकारी क्षेत्र में 4 लाख रोजगार के लक्ष्य पर कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ा और अब डिग्री से युवाओं के जीवन को नई दिशा मिल रही है।

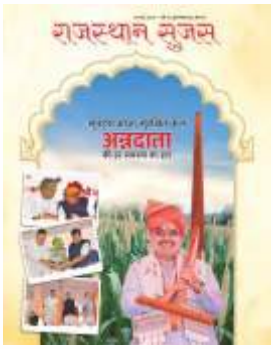

प्रधान संपादक
राकेश शर्मा

वरिष्ठ संपादक
डॉ. गोरधन लाल शर्मा

संपादक
अजय कुमार

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी
मोहित जैन

आवरण छाया
हरिशंकर शर्मा
पदम सैनी

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड
लागत मूल्य 43.00 रुपये

आमंत्रण

'राजस्थान सुजस' पत्रिका के लिए राज्य सरकार की योजनाओं, नवाचार, राजस्थान की संस्कृति व धरोहर आदि विषयों पर आधारित लेख आप editorsujas@gmail.com पर भिजवा सकते हैं। चयनित लेख सुजस में प्रकाशित किए जाएंगे।

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

राजस्थान सुजस की ई-कॉपी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर "SUJAS" लिखकर व्हाट्सऐप करें। मो. 80581-15790

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80581 15790
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 35 अंक 05 | मई, 2026

इस अंक में

किसान हित सर्वोपरि **09**

ग्राम रथ अभियान **14**

ग्राम विकास चौपाल **40**

सम्पादकीय	04
प्रधानमंत्री जी के नाम मुख्यमंत्री जी का पत्र	05
मोबाइल वेटरिनरी यूनिट	13
राजस्थान की बाजरा क्रांति	16
ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026	18
राजस्थान में श्रम कल्याण योजनाएं	20
मधुनेत्र AI अभियान	23
जनगणना 2027	24
हाइटेक वाचनालय	28
भरतपुर के ऐतिहासिक मन्दिरों का कायाकल्प	30
पीएम कुसुम योजना	32
राजस्थान महिला निधि	34
विधानसभा के नवाचार	36
चौपाल से सशक्तीकरण	38
ब्रह्मगुप्त ने विश्व-गणित को दी नई दिशा	42
Anti-Drug Mission	45
लोक रौ सरूप अर लोक साहित्य	46
पोषण पखवाड़ा	49
श्री जगदंबा अंधविद्यालय	50
ब्यावर रो खास ठिकाणो	53
श्याम पांडिया मंदिर	54
भारत की ज्ञान विरासत का पुनरुद्धार	56
राजस्थान का डिजिटल सफर	58
आत्मनिर्भर बनता किसान	60
नवाचार और मेहनत से खेती में समृद्धि	63
स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट	68
नवाचारों से सशक्त होती शिक्षा व्यवस्था	70
कालिका पेट्रोलिंग यूनिट	72
नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका	74
सामयिकी	75
सुजस प्रश्नोत्तरी	78
धरोहर	79

बूंदी जिले का गुढ़ा बांध **52**

झालरापाटन का सूर्य मंदिर **64**

The Amber Fort **66**

संपादकीय

ग्राम प्रगति से कृषि समृद्धि तक
राजस्थान का विकास पथ

"जब किसान सशक्त होगा, तभी राष्ट्र सशक्त होगा" प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह कथन भारतीय कृषि व्यवस्था की उस मूल आत्मा को अभिव्यक्त करता है, जिसमें किसान को केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में कृषि एवं ग्रामीण विकास को एक नई दिशा और गति प्राप्त हो रही है।

राज्य सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि किसान केवल उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि आधुनिक तकनीक, नवाचार और वैश्विक अवसरों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें। इसी क्रम में "ग्राम विकास रथ अभियान" ग्रामीण विकास और जनभागीदारी का एक प्रभावी एवं अभिनव माध्यम बनकर उभरा है। इन रथों के माध्यम से राज्य की सभी विधानसभाओं में ग्राम पंचायत स्तर तक योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

इस अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता 'सुझाव पेटिका' रही, जिसके माध्यम से किसानों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव सीधे जिम्मेदारों तक पहुंचाए। यह व्यवस्था शासन और जनता के बीच संवाद को सुदृढ़ करती है तथा नीतियों को जमीनी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा अजमेर, सीकर, प्रतापगढ़, जालोर, जयपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 'ग्राम विकास चौपालों' का आयोजन और गांवो में आमजन से सीधा संवाद स्थापित करना इस बात का प्रतीक है कि शासन व्यवस्था अब केवल नीतिगत प्रारूप के कार्यालयी निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ग्राम स्तर की वास्तविकताओं को समझने व समस्याओं के निराकरण हेतु सीधे जनता के बीच पहुंच रही है।

राजस्थान में कृषि एवं ग्रामीण विकास का यह उभरता हुआ मॉडल 'तकनीक, परंपरा और जनभागीदारी' का एक संतुलित एवं दूरदर्शी संगम है। यह समन्वित प्रयास न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा, बल्कि राज्य को समग्र विकास की दिशा में एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। ग्रामीण विकास, कृषि, श्रमिक कल्याण तथा पंचायती राज और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों को समाहित करता हुआ मई माह का यह अंक आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

वन्दे मातरम्!

(राकेश शर्मा)
प्रधान सम्पादक

आपणो अग्रणी राजस्थान

राजस्थान दिवस

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (नवसंवत्सर)

के अवसर पर

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी

की ओर से भेजे गए

शुभकामना सन्देश

के लिए

मुख्यमंत्री
श्री भजनलाल शर्मा
का आभार पत्र

भजन लाल शर्मा
मुख्य मंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते

शासन सचिवालय, जयपुर-302005
दूरभाष नं. (का.) - 0141-2227686, 2227647
फैक्स : 2227687

परम आदरणीय,
यशस्वी प्रधानमंत्री जी,
सादर प्रणाम।

राजस्थान दिवस के पावन अवसर पर प्रेषित आपके भावसमृद्ध शुभकामना संदेश एवं प्रेरणाप्रद आशीर्वचन के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। देश के लिए समर्पित आपके विराट व्यक्तित्व को मैंने सदा अपने हृदय में एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में संजोए रखा है।

इस शुभकामना संदेश के रूप में उद्घाटित आपके स्नेहिल शब्द मेरे लिए नई प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत हैं। राजस्थान के गौरवमयी इतिहास का पुनः स्मरण कराने वाला एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए दिशा-सूचक आपका यह शुभ संदेश हमें अपने सांस्कृतिक गौरव एवं राष्ट्र-चेतना का बोध कराता है। साथ ही साथ यह निरंतर सेवाभाव और सुशासन के माध्यम से हमारे कर्तव्य-पथ को भी आलोकित करता है। निःसंदेह इसमें दीपशिखा की भांति प्रकाशमान आपका व्यक्तित्व निहित है।

माननीय, **चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (नवसंवत्सर)** के शुभ अवसर पर राजस्थान दिवस के आयोजन का यह निर्णय हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्स्थापित करने वाले आपके अभियान से ही प्रेरित है। आपके प्रेरणादायी नेतृत्व के परिणामस्वरूप हमारी प्राचीन भारतीय कालगणना, समृद्ध पंचांग परंपरा और वैज्ञानिक जीवन दृष्टि के अनुरूप विभिन्न उत्सवों की पुनःप्रतिष्ठा एवं राष्ट्रीय गौरव में अभिवृद्धि हुई है।

महोदय, आपके हृदयस्पर्शी शब्दों में लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का राष्ट्र की एकता और अखण्डता के प्रतीक स्वरूप किया गया उल्लेख तथा उनकी स्मृति में विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा **'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी'** का निर्माण हमें अपने राष्ट्रीय वैभव एवं आत्म गौरव की याद दिलाता है। राजपूताना के विस्तृत भू-भाग पर अवस्थित विभिन्न रियासतों का आधुनिक राजस्थान के रूप में एकीकरण सरदार पटेल की दूरदृष्टि तथा मजबूत एवं अखण्ड भारत की उनकी परिकल्पना का परिणाम था। मैं ऐसे इतिहास पुरुष को शत-शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।

यह ऐतिहासिक तिथि **चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र एवं इन्द्र योग** का दुर्लभ संयोग था। सरदार पटेल ने इसी यादगार दिन को **'राजस्थान स्थापना दिवस'** और **'राजस्थान निर्माण दिवस'** के रूप में मनाये जाने की घोषणा की। महोदय, लौहपुरुष की इसी लोकतांत्रिक भावना का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार ने **चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (नवसंवत्सर)** के इस दिन को **राजस्थान दिवस** के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

माननीय, आपके संदेश में राजस्थान की विशाल भौगोलिक परिधि के साथ-साथ यहां के जनमानस की आशा-आकांक्षाएं, स्वाभिमान और अदम्य जिजीविषा का भावविह्वल कर देने वाला सजीव चित्रण आपके अनुराग को दर्शाता है। यह वही धरा है, जहां पीढ़ियों ने पराधीनता की अपेक्षा स्वाभिमानपूर्ण बलिदान को वरण किया और अपने त्याग से इतिहास की अमर गाथाएं लिखीं। भारतीय सशस्त्र बलों में आज यहां के युवाओं की उल्लेखनीय सहभागिता राष्ट्ररक्षा के प्रति उनके उसी अटूट समर्पण को दर्शाती है। आपके द्वारा देश की सेना में प्रदेश की उल्लेखनीय भागीदारी को इंगित करना निःसंदेह इन रणबांकुरों के मनोबल को बढ़ाने वाला है।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान हाइफा के युद्ध में भारतीय, विशेषतः मारवाड़ के वीर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय साहस का आपके द्वारा किया गया उल्लेख, उस गौरवगाथा का पुनः स्मरण कराता है, जिसने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के शौर्य को स्थापित कर समूचे हिन्दुस्तान के सम्मान को बढ़ाया।

आदरणीय, आपने राइजिंग राजस्थान का शुभारम्भ करते समय 09 दिसम्बर, 2024 को जयपुर में कहा था कि-**"चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान और नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान"**। आपके ये शब्द हमारे लिए प्रेरणापुंज सिद्ध हुए हैं, जो अब हमारी कार्य-संस्कृति का आधार बन चुके हैं। **"आपदाओं को अवसर में परिवर्तित करने की आपकी प्रेरणा"** राजस्थान वासियों की दूरदर्शिता का मूलाधार है।

वीर भूमि राजस्थान के प्रति आपका स्नेह और आत्मीय लगाव सदैव हमारा संबल रहा है। प्रदेश को भावनात्मक समर्थन देते हुए आपने जब कहा कि **"राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है।"** तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आपके ये शब्द हमारे प्रदेश की विकास यात्रा के मूलमंत्र बन गए हैं।

राजस्थानियों की अथक उद्यमशीलता सर्वज्ञात है। मारवाड़ियों की जीवटता ने इस कहावत को भी चरितार्थ किया है **"जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी"**। इसी भावना के कारण यहां के लोगों ने देश-विदेश में अपनी मेहनत, कौशल और दूरदर्शिता के बल पर एक लोकमंगलकारी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े सृजनशील समाज के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसी भावना से प्रेरित होकर आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने 10 दिसम्बर, 2025 को **पहले प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन** का सफल आयोजन किया।

प्रदेश की समृद्ध जनजातीय परंपरा के प्रति आपका आत्मीय लगाव तथा **मानगढ़ धाम** में स्वयं पहुंचकर गोविन्द गुरु जी को अर्पित की गई आपकी श्रद्धांजलि, हमारे लिए सामाजिक समरसता की प्रेरणा है। मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, जल प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार तथा महिलाओं व युवाओं के सशक्तीकरण हेतु किए जा रहे प्रयास आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही सफल हो पा रहे हैं, जो भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे।

आपके कुशल नेतृत्व में नारी शक्ति की सुरक्षा, गरिमा, मान-सम्मान एवं स्वाभिमान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश की **16 लाख** से अधिक महिलाओं को **लखपति दीदी योजना** के तहत आत्मनिर्भर बनाया है। साथ ही **20 लाख** से अधिक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं डिजिटल तकनीक से जोड़कर स्वरोजगार की ओर उन्मुख किया गया है। आपकी अभिप्रेरणा से प्रदेश में हो रहे महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के प्रयासों के परिणामस्वरूप एन.सी.आर.बी. के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले दो वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है।

पिछले सवा दो वर्षों में **"डबल इंजन सरकार"** के माध्यम से सुशासन की दिशा में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, वो आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा सतत सहयोग का ही सुफल है। राज्य में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, आधारभूत संरचना का विकास तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज तीव्र गति से कार्य संपादित हो रहे हैं। आपके प्रोत्साहन से पिछले दो वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसतन करीब 12 प्रतिशत (वार्षिक) की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राजस्थान की जनता को समय-समय पर मिले आपके सान्निध्य और उत्साहपूर्ण उद्धबोधनों ने समूचे प्रदेश को विकास के लिए समर्पित एवं एकजुट कर दिया है।

महनीय, आपके निर्देशन में विकसित कोटपूतली-आगरा ग्रीनफील्ड हाइवे, जयपुर-किशनगढ़-जोधपुर-अमृतसर कॉरिडोर, जयपुर रिंग रोड विस्तार तथा **जयपुर मेट्रो** जैसी परियोजनाएं प्रदेश के चहुंमुखी विकास, गतिशीलता और बढ़ती लॉजिस्टिक्स क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। इसी क्रम में आपके द्वारा कोटा-बूंदी एयरपोर्ट का किया गया शिलान्यास क्षेत्रीय विकास और निवेश के नए द्वार खोलेगा, वहीं **भारतमाला परियोजना** का दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर आपके विज़न को पूरा करते हुए राज्य को **'आपणो अग्रणी राजस्थान'** बनाने में महत्ती भूमिका निभायेगा।

आपके कर कमलों से शुरू हुई **रामजल सेतु परियोजना** में शामिल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट तथा पार्वती-कालीसिंध-चंबल प्रोजेक्ट एवं यमुना जल समझौता जैसी परियोजनाएं प्रदेश के लिए दीर्घकालिक जल-सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में **मील का पत्थर** साबित होंगी। एक सदी पुरानी गंगनहर और आई.जी.एन.पी. का सुधार एवं पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। यहां मुझे माननीय को यह अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आपकी प्रेरणा से जल-संरक्षण के इस महत्वपूर्ण एवं मूलभूत कार्य में **"कर्मभूमि से मातृभमि अभियान"** के अन्तर्गत हमारे **प्रवासी राजस्थानी** भाई तन-मन-धन से जुड़कर अपना अहम योगदान दे रहे हैं।

राजस्थान प्रदेश के लिए यह सौभाग्य की बात है कि सूर्यदेव की कृपा से यहां सर्वाधिक सौर दिवस उपलब्ध हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी राजस्थान, विशेषतः बीकानेर, जैसलमेर एवं फलोदी में विकसित हो रहे सौर ऊर्जा प्रकल्पों और नवीकरणीय ऊर्जा जोनों के माध्यम से, हरित ऊर्जा क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए 24 जिलों में **दिन के समय बिजली** दिया जाना संभव हो पाया है। आपके नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश **पीएम सूर्यघर** योजना तथा **कुसुम योजना** के माध्यम से हरित ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

देश के युवाओं को अपने उद्बोधन में आप अक्सर कहते हैं कि **"देश के युवाओं को नौकरी प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है।"** इसी बीज मंत्र को लेकर प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **युवा नीति तथा रोजगार नीति** 2026 लागू की गई है। सरकार बनते ही हमने पूर्व में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पेपर लीक पर कड़ा प्रहार कर राज्य में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और युवाओं में भरोसे का नया वातावरण निर्मित किया है। श्रीमान के सान्निध्य में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र युवाओं को प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में 1.35 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, साथ ही आपकी प्रेरणा से हमने 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं का भर्ती कैलेण्डर 2026 भी जारी किया है। निजी क्षेत्र में भी हमने **तीन लाख से अधिक** नियुक्तियां दिलवाई हैं, जो प्रदेश में सुशासन और युवाओं में विश्वास की पुनर्स्थापना का परिचायक है।

हमारे लिए यह गौरव की बात है कि आपके राष्ट्रीय संबोधन **"मन की बात"** में प्रेरक दृष्टांत के रूप में राजस्थान का संदर्भ कई बार अभिव्यक्त हुआ है। गत दिनों आपके द्वारा मन की बात के 132वें एपिसोड (29 मार्च, 2026) में बीकानेर के अभय जैन ग्रंथालय की सराहना ने प्रदेश के लाखों लोगों को हमारी समृद्ध ज्ञान

परंपरा के प्रति सजग बनाया है। आपके नेतृत्व में संचालित **"ज्ञान भारतम् मिशन"** भारतवर्ष की अमूल्य प्राचीन परम्परा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर, इस धरोहर को विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं आमजन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य कर रहा है।

विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए आपके सुझाए मार्ग से हम नीति आयोग की तर्ज पर एक **थिंक टैंक रीति** (RITI - राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफोर्मेशन एंड इनोवेशन) का गठन कर लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि **विकसित भारत 2047** के आपके संकल्प पथ पर अग्रसर होते हुए आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक-सांस्कृतिक समृद्धि के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे।

मान्यवर, भारत को विश्व गुरु बनाने की आपकी दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता से प्रेरणा पाकर हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का संकल्प किया है। प्रदेश की जनता-जनार्दन को पूरा भरोसा है कि आपका कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन **संकल्प से सिद्धि** तक अवश्य ले जाएगा।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फलक पर आपकी वचनबद्धता एवं नेतृत्व क्षमता से प्रेरित होकर हमारी सरकार पूर्ण विश्वास के साथ राज्य के सर्वांगीण विकास में जुटी है। किसान कल्याण, औद्योगिक विस्तार, प्रौद्योगिकीय प्रोन्नति एवं पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में आपके विचार हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। आपके नेतृत्व में केन्द्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयास 'डबल इंजन' की अवधारणा को वास्तविक अर्थ प्रदान कर रहे हैं।

महोदय, आपके द्वारा **सार्वजनिक जीवन में 8931 से अधिक दिनों का रिकॉर्ड सेवा संकल्प** बिना किसी अवकाश और विश्राम के पूरा करना हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आपकी इसी लोक हितकारी भावना का अनुसरण करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़कर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

माननीय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि डबल इंजन की राजस्थान सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के **एकात्म मानववाद** और **अन्त्योदय** से प्रेरणा पाकर आमजन के लिए **समस्या समाधान पोर्टल एवं कॉल सेन्टर सी.एम. संपर्क-181** को पूर्ण आधुनिक, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की पहल की है। आपकी जनसेवा भावना से प्रेरणा पाकर मेरे स्वयं के द्वारा नियमित जनसुनवाई के साथ ही सी.एम. हेल्पलाइन पर भी आमजन/परिवादियों से संवाद किया जा रहा है। जनसमस्याओं का समय पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके स्नेहशील प्रेरक नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राजस्थान की कर्मठ जनता की सहभागिता से विकसित राजस्थान और विकसित भारत का महान संकल्प अवश्य साकार होगा। हम सभी इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण समर्पण, निष्ठा और जनभागीदारी के साथ निरंतर प्रयत्नशील हैं।

मैं यहां कृतज्ञतापूर्वक इंगित करना चाहता हूं कि जब-जब भी मैं राजस्थान के विकास और कल्याण हेतु किसी योजना को लेकर आपके पास आया, आपने पूरा समय देकर पूर्ण गंभीरता से मेरी बात को सुना और उम्मीद से अधिक बजट मुहैया करवाने के साथ-साथ मुझे बहुमूल्य सुझाव भी दिए। आपके साथ हुई इन मुलाकातों के दौरान आपके करिश्माई व्यक्तित्व ने मेरे अंतर्मन को गहराई से प्रभावित किया और मुझे नई जीवन दृष्टि प्रदान की। इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा।

आपका स्नेह और मार्गदर्शन ऐसे ही मुझे सदैव मिलता रहे, जिससे आपके गहन अनुभवों से प्रेरणा पाकर हम प्रदेश को सतत विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर कर सकें।

गोवर्धनधारी भगवान श्रीकृष्ण से आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए श्रीमान के प्रेरणादायी संदेश एवं आशीर्वचन के लिए पुन: हृदय से आभार।

जय हिन्द - जय भारत।

सदैव आपका,

भजन लाल शर्मा

सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि
किसान हित सर्वोपरि

आलोक आनंद, उपनिदेशक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किसान-केंद्रित नीतियों और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में राजस्थान का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। "किसान देश की रीढ़ हैं" यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की नीति का मूल आधार है। उनके नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं को राज्य सरकार ने न केवल प्रभावी रूप से लागू किया है, बल्कि राज्य स्तर पर अतिरिक्त सहयोग देकर किसान की समृद्धि को नई गति दी है।

श्री नरेन्द्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से किसान संबंधी नीति में एक नई सोच आई है। उन्होंने किसानों को देश की असली ताकत माना। उनका यह दृढ़ संकल्प रहा है कि भारत का किसान समृद्ध हो, उसके जीवन में सम्मान हो। राज्य सरकार भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत पात्र किसानों को हर साल राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये की अतिरिक्त सम्मान राशि दी जा रही है। अब तक इस योजना में किसानों के खातों में 12,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं और राज्य सरकार इस सम्मान निधि की राशि को चरणबद्ध रूप से 12,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है।

फसल बीमा योजना में भी अब किसान की फसल खराब होने पर पहले की तुलना में अधिक मुआवजा मिल रहा है। फसल बीमा के मोर्चे पर भी राज्य सरकार ने किसानों को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षा दी है। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अंतर्गत 15 दिसंबर, 2023 से अब तक 8,298 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान ने 9.25 करोड़ बीमा पॉलिसियां सृजित की हैं, जो देश की ऐसी कुल पॉलिसियों का 26 प्रतिशत है और यह आंकड़ा पूरे देश में सर्वाधिक है।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026

मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य का कृषि क्षेत्र न केवल सशक्त हो रहा है, बल्कि किसान भी आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की ओर तेजी से अग्रसर हैं। इस गति में और तेजी लाने के लिए आयोजित होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 राज्य के कृषि क्षेत्र को वैश्विक स्तर से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक, देश-विदेश के कृषि वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, स्टार्टअप और एग्रीटेक डेवलपर एक मंच पर आएंगे। कृषि नवाचारों का प्रदर्शन, अत्याधुनिक समाधान और निवेश के अवसर, यह मीट राजस्थान की खेती को वैश्विक नक्शे पर स्थापित करेगी। इसके प्रचार के लिए नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद में रोड-शो सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं।

इस आयोजन की सफलता के लिए राज्य सरकार वर्ष की शुरुआत से ही सक्रिय रही है। जनवरी-फरवरी में आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों में किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी गई। यह मीट केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों को नवाचार, निवेश और तकनीकी समाधान से जोड़ने का मंच है, जिससे कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान

राजस्थान दिवस से प्रारंभ हुआ 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान' राज्य के विकास का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत करता है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में आयोजित सभाओं के माध्यम से जनता स्वयं अपने क्षेत्र के विकास की दिशा तय कर रही है। इस अभियान की विशेषता यह है कि इसमें वर्ष 2030, 2035 और 2047 तक की विकास प्राथमिकताओं को चरणबद्ध रूप से निर्धारित किया जा रहा है।

क्षेत्र-विशेष की आवश्यकताओं जैसे पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य का वैज्ञानिक आकलन कर योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही, स्थानीय संस्कृति, खान-पान, आस्था स्थल और पर्यटन स्थलों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिससे समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। यह पहल किसानों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कृषि से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण होता है।

ग्राम विकास रथ

27 अप्रैल, 2026 को शुरू हुआ 'ग्राम विकास रथ अभियान' ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और सहभागिता का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इन रथों के माध्यम से राज्य की सभी विधानसभाओं में ग्राम पंचायत स्तर तक योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। एलईडी स्क्रीन के जरिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और सफल प्रयोगों की जानकारी दी गई। साथ ही, योजनाओं से संबंधित साहित्य का वितरण और संदेशों का प्रसारण किया गया।

इस अभियान की एक खास विशेषता थी सुझाव पेटिका, जिसके माध्यम से किसान अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकते थे। इससे न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सका, बल्कि नीतियों को जमीनी जरूरतों के अनुसार ढालने में भी मदद मिली।

सूचना से सशक्तीकरण

इन सभी पहलों का मूल उद्देश्य किसानों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया का सहभागी बनाना है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती, जल प्रबंधन और बाजार से जुड़ाव जैसे विषयों पर जानकारी देकर किसानों को सशक्त किया जा रहा है। कम बजट में अधिक लाभ देने वाले कार्यों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे अधिकतम किसानों को लाभ मिल सके। इससे न केवल उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि किसानों की आय में भी स्थायी वृद्धि हो रही है।

मृदा स्वास्थ्य एवं परीक्षण सुविधाएं

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता के मूल आधार मिट्टी को स्वस्थ बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। 20 जिलों में एग्रीक्लिनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर संचालन शुरू किया गया है। अब तक 18.65 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं, जिससे किसान अपनी भूमि में पोषक तत्वों की सही जानकारी प्राप्त कर उचित खेती कर पा रहे हैं।

भूमि सुधार के लिए 3.31 लाख बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरित किए गए। साथ ही 66.22 लाख बीज मिनीकिट (जिनमें से 61.50 लाख महिला किसानों को) निःशुल्क दिए गए, जिस पर 122.66 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

उर्वरक उपलब्धता एवं जैविक खाद

समय पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 60.82 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 16.54 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. किसानों तक पहुंचाया गया। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 50 हजार किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए प्रति किसान 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। 70,061 वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गईं और 1,515 कृषकों को पशुपालन आधारित कृषि से जोड़ा गया।

जल प्रबंधन - हर बूंद कीमती

राजस्थान में जल संरक्षण लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन सरकार ने इसे अवसर में बदलते हुए किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 12,476 डिग्गियों का निर्माण कराया गया, जिस पर 274 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। इसी क्रम में 35,368 खेत तलाइयों (फार्म पौंड) का निर्माण कर 328 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। साथ ही, जल अपव्यय को रोकने और सिंचाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 32,918 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन बिछाई गई, जिस पर 143 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

कृषि यंत्र, फसल सुरक्षा एवं आधुनिक उपकरण

1.31 लाख कृषि यंत्रों पर 329 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। जानवरों से फसल बचाने के लिए किसानों के खेतों पर 414 लाख मीटर तारबंदी करवाई गई, जिस पर 458 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। 9,355 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। 46,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नैनो यूरिया के प्रदर्शन किए गए। कृषि ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना लागू की गई। महिला स्वयं सहायता समूहों को नैनो यूरिया/ डी.ए.पी. छिड़काव पर 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जा रही है।

महिला सशक्तीकरण एवं शिक्षा

महिलाओं को कृषि क्षेत्र का मुख्य आधार बनाते हुए विशेष पहल की गई। 86,101 छात्राओं को कृषि अध्ययन (10+2, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी) के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई, जिस पर 150 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 9.61 लाख किसानों (महिला एवं पुरुष) को प्रशिक्षण दिया गया तथा 9,481 किसानों को भ्रमण पर भेजा गया।

प्राकृतिक खेती एवं पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा

2.50 लाख किसानों को चुनकर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे-सीमांत किसानों के लिए बैलों से खेती करने पर 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ■

राजस्थान में खेती की तस्वीर बदल रही है। किसान अब केवल बारिश का इंतजार नहीं करता। उसके खेत में डिग्गी है, पाइपलाइन है, तारबंदी है। उसकी बेटी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, उसकी पत्नी ड्रोन उड़ा रही है और उसके हाथ में मोबाइल पर फसल बीमा की जानकारी है। यह बदलाव संयोग नहीं है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शी नीतियों और मुख्यमंत्री श्री शर्मा के निष्ठावान नेतृत्व का परिणाम है। राजस्थान का किसान आज न केवल बेहतर जीवन जी रहा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है और यही इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने यह साबित किया है कि जब नीयत साफ हो और नीति किसान-केंद्रित हो, तो खेत सोना उगलते हैं। सम्मान निधि से लेकर एग्रीटेक मीट तक, डिग्गी से लेकर ड्रोन तक, हर कदम पर किसान को केंद्र में रखा गया है। डबल इंजन की सरकार में राजस्थान का अन्नदाता आज न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि विकसित भारत 2047 के सपने को भी सींच रहा है।

मोबाइल वेटरनरी यूनिट

पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयास

रचना सिद्धा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में पशुपालकों और पशुओं के कल्याण के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की योजना मोबाइल वेटरनरी यूनिट का संचालन ऐसे प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के लिए 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की, जिनके माध्यम से पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोबाइल वेटरनरी यूनिट एक ऐसा वाहन है, जो पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पशुपालक के घर तक जाता है।

मोबाइल यूनिट आवश्यक उपकरणों और दवाइयों से लैस

एम.वी.यू. का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए उनके घर तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सा सेवाएं सीमित हैं। एम.वी.यू. में पशु चिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा, कृमिनाशक, गर्भ जांच, टीकाकरण जैसी सेवाएं शामिल हैं। प्रत्येक मोबाइल यूनिट में एक पशु चिकित्सक, एक पशुधन सहायक और एक वाहन चालक कम हेल्पर होते हैं। सभी वाहन आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों तथा दवाइयों से लैस हैं। कहा जा सकता है कि ये वाहन पशुओं के लिए चलते-फिरते अस्पताल हैं। योजना के संचालन के लिए 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जा रही है।

एक कॉल पर तुरंत इलाज की सुविधा

इस व्यवस्था का अधिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस सेवा में एक कॉल सेंटर का प्रावधान है, जिसे एक हेल्प लाइन नंबर 1962 से जोड़ा गया है। इस पर कॉल करते ही मोबाइल यूनिट के माध्यम से पशुपालक के घर पर उसके पशु के लिए तुरंत इलाज की सुविधा मिल जाती है। यह एक टोल फ्री नंबर है, जिस पर कॉल करके पशुपालक अपने बीमार पशु के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सेवा को बुक कर सकता है।

चैटबॉट सुविधा से एमवीयू को जोड़कर किया नवाचार

इस योजना को आधुनिक तकनीकी से जोड़ते हुए इसका अधिक से अधिक लाभ लेने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉल सेंटर सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चैटबॉट सेवा की सुविधा से भी इसे जोड़ दिया गया है। कॉल सेंटर के माध्यम से 1962- एमवीयू राजस्थान चैटबॉट भी संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ऑडियो एवं वीडियो टेली परामर्श सहित ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा भी प्रदेश के पशुपालकों को दी जा रही है। साथ ही वीओआईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से टेली वेटरनरी मेडिसिन की सेवाएं भी पशुपालकों को उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सीएसआर के तहत हो रहा है कॉल सेंटर और चैटबॉट का संचालन

इस योजना के अंतर्गत कॉल सेंटर और व्हाट्सएप नंबर 9063475027 पर चैटबॉट का संचालन सीएसआर के तहत किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कॉल सेंटर बीएफआईएल और इंडसइंड बैंक द्वारा विकसित किया गया है और कॉल एक्जीक्यूटिव, सॉफ्टवेयर आदि जैसे आवर्ती व्यय बैंक द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि विभाग आधारभूत संरचना और लीज्ड लाइन के व्यय को वहन कर रहा है। इस व्यवस्था से राज्य को लगभग तीन करोड़ रुपये वार्षिक की बचत हो रही है।

व्यापक स्तर पर पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

इस योजना के तहत अब तक 62 लाख से अधिक पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और 16 लाख से अधिक पशुपालक इसका लाभ ले चुके हैं। चैटबॉट के माध्यम से भी एक लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो चुके हैं। ■

ग्राम रथ अभियान

गांव-गांव पहुंची विकास की रोशनी

किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम

अंजलिका पंवार, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

प्रदेश के किसानों को हर क्षेत्र में अग्रणी एवं उन्नत बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर सक्रिय प्रयास कर रही है। कृषि, निवेश, नवाचार और तकनीक के माध्यम से किसान समृद्धि का नया अध्याय लिखने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा ग्राम (ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट) 2026 का राज्य स्तरीय आयोजन किया जायेगा। इस महाआयोजन में प्रदेशभर से कृषक और पशुपालक भाग लेकर आधुनिक कृषि की नई संभावनाओं से रूबरू होंगे।

ग्राम रथ अभियान - जन-जागरूकता का अभिनव माध्यम

इस आयोजन को जन-जन तक पहुंचाने और ग्रामीण भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से ग्राम रथ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में 183 ग्राम रथ संचालित किए गए। इस अभियान की शुरूआत 27 अप्रैल, 2026 से की गई। एलईडी मोबाइल वैन आधारित इस पहल के माध्यम से योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी को गांव-गांव तक प्रभावी रूप से पहुंचाया गया।

घर-घर पहुंचकर बदल रहा जागरूकता का स्वरूप

ग्राम रथ केवल एक प्रचार माध्यम नहीं रहा, बल्कि ग्रामीणों के घर-घर तक पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी बन गया। यह अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और हर ग्रामीण तक सरकारी पहल की जानकारी सीधे पहुंचे।

ग्रामीणों में उत्साह, महिलाओं और युवाओं की बढ़ी भागीदारी

ग्राम रथ अभियान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण महिलाओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया और संध्या चौपाल में भी बढ़-चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । इस दौरान आयोजित कला जत्था जैसे कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र बने, जिन्होंने संदेशों को रोचक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एलईडी स्क्रीन से रोचक अंदाज में योजनाओं का प्रसार

ग्राम रथों में लगी एलईडी स्क्रीन इस अभियान की खास विशेषता बनकर उभरी। इन स्क्रीन के माध्यम से ऑडियो-वीडियो के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं को सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे ग्रामीणों को जानकारी समझने में आसानी रही और उनकी रुचि भी बनी रही।

13 विभागों की योजनाएं और प्रचार सामग्री एक ही मंच पर

ग्राम रथों के माध्यम से 13 विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध करवाई गई। कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभागों की प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण इन रथों के माध्यम से किया गया, जिससे ग्रामीणों तक योजनाओं की विस्तृत जानकारी पहुंच सकी और वे अधिक से अधिक लाभ उठा सके।

सुझाव और समाधान का सशक्त मंच

ग्राम रथ अभियान केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सरकार और ग्रामीणों के बीच संवाद का एक प्रभावी मंच भी बन गया। ग्राम रथों के माध्यम से गांववासियों ने राज्य सरकार को योजनाओं के बारे में अपने सुझाव दिए और सुझाव पेटिका के जरिए अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाई। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया तथा प्रशासन द्वारा मौके पर ही समस्याओं के समाधान सुनिश्चित किए गए।

हर दिन कई स्थानों पर कार्यक्रम, बढ़ रहा प्रभाव

ग्राम रथ के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन चार से पांच स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई, जिससे ग्रामीणों को सीधे लाभ मिल सका और उनकी भागीदारी भी लगातार बनी रही।

मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, अभियान को मिली नई गति

इस अभियान का शुभारंभ 27 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर से ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसके बाद 28 अप्रैल से ये रथ विभिन्न ग्रामीण विधानसभाओं के लिए रवाना किए गए, जिससे अभियान को गति और व्यापकता मिली।

आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता राजस्थान

"कृषि, किसान और गांव सशक्त होंगे, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा" इसी सोच से प्रेरित ग्राम रथ अभियान ने न केवल योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई, बल्कि यह ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और सुझावों के आदान-प्रदान का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया। यह अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें हर गांव, हर किसान और हर नागरिक तक विकास की रोशनी पहुंचाने का संकल्प निहित है। ■

राजस्थान की बाजरा क्रांति

रेतीले बंजर से वैश्विक बीज शक्ति बनने की ओर अग्रसर

डॉ. बनवारी यादव, जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान की तपती रेत अब केवल मरुस्थलीय संघर्ष की पहचान नहीं रही। यही धरती आज भारत की नई कृषि क्रांति का केंद्र बनती दिखाई दे रही है। जलवायु परिवर्तन, घटते जल संसाधन और बढ़ती खाद्य चुनौतियों के बीच राजस्थान ने बाजरा बीज आत्मनिर्भरता की दिशा में जो कदम बढ़ाया है, वह आने वाले समय में देश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। इसी परिवर्तनकारी सोच को वैश्विक मंच देने के लिए आयोजित होने वाला ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026, एक ऐसा आयोजन होगा जहां कृषि, तकनीक, निवेश और नवाचार का संगम देखने को मिलेगा। राजस्थान की पहचान अब केवल बाजरा उत्पादन करने वाले राज्य की नहीं रहेगी, बल्कि वह विश्वस्तरीय बाजरा बीज हब बनने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। यह पहल भारत को वैश्विक एग्रीटेक नेतृत्व की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगी।

बीज आत्मनिर्भरता की चुनौती और अवसर

राजस्थान देश के सबसे बड़े बाजरा उत्पादक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान रखता है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख क्विंटल बाजरा उत्पादन होता है, जो इसकी कृषि क्षमता और किसानों की मेहनत को दर्शाता है। वर्तमान में राज्य में हर वर्ष लगभग 36 लाख किलोग्राम बाजरा बीज की आवश्यकता रहती है, जिसे पूरा करने के लिए बाहरी राज्यों से भी सहयोग लिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राजस्थान के लिए एक बड़ा अवसर है। यदि राज्य में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन को और मजबूत बनाया जाए, तो न केवल किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर गुणवत्ता के बीज आसानी से उपलब्ध होंगे, बल्कि राजस्थान भविष्य में बाजरा बीज उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बन सकता है।

बाजरा - भविष्य की 'क्लाइमेट-स्मार्ट' फसल

कभी गरीबों का भोजन समझा जाने वाला बाजरा, आज दुनिया के सबसे चर्चित 'सुपर फूड्स' में शामिल हो चुका है। प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर बाजरा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फसल कम पानी, अधिक तापमान और सूखे जैसी परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। जब दुनिया जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब बाजरा जैसी जलवायु-अनुकूल फसलें भविष्य की खाद्य सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकती हैं। इसी कारण राजस्थान की बाजरा बीज पहल को केवल कृषि कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

विज्ञान और तकनीक से बदलती कृषि की तस्वीर

राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र और बीज संस्थान मिलकर नई पीढ़ी के उन्नत बाजरा बीज विकसित करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक ऐसे बीज तैयार कर रहे हैं, जो सूखा सहन करने में सक्षम हों, अत्यधिक तापमान में भी उत्पादन दें, रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हों, प्रति हेक्टेयर

अधिक पैदावार दें और बेहतर पोषण गुणवत्ता प्रदान करें। इसके साथ ही आधुनिक बीज भंडारण, प्रसंस्करण और गुणवत्ता परीक्षण तकनीकों पर भी तेजी से काम हो रहा है। डिजिटल कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मौसम आधारित सलाह और प्रिसिज़न फार्मिंग जैसी तकनीकों का उपयोग भी बढ़ रहा है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 में इन तकनीकों का लाइव प्रदर्शन, स्टार्टअप शोकेस और किसान-वैज्ञानिक संवाद प्रमुख आकर्षण बनेंगे।

किसान बनेंगे बदलाव के असली नायक

राजस्थान की इस बाजरा क्रांति का केंद्र स्वयं किसान ही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां और गांव स्तर के बीज उद्यम इस परिवर्तन को गति देंगे। यदि किसानों को प्रमाणित बीज उत्पादन से जोड़ा जाता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, ग्रामीण रोजगार के नए अवसर बनेंगे, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, बाहरी राज्यों पर निर्भरता घटेगी और किसानों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध होंगे, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्र बीज उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त माने जा रहे हैं। उचित प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सरकारी समर्थन मिलने पर ये इलाके विशेष 'सीड प्रोडक्शन ज़ोन' के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं।

नीति, निवेश और वैश्विक सहयोग की जरूरत

विशेषज्ञों के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान, मजबूत नीति समर्थन, निजी निवेश और संस्थागत साझेदारी के समन्वय से राजस्थान बाजरा बीज उत्पादन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। राज्य सरकार के लिए यह क्षेत्र कृषि विकास और निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस दिशा में कई अहम पहल प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं, जैसे बीज तकनीक में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा, कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ मजबूत सहयोग, आधुनिक बीज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं का विस्तार, किसान प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियानों को गति और बीज उत्पादकों के लिए बेहतर बाजार सहायता। ग्राम 2026 निवेशकों, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, बीज कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय कृषि संगठनों को एक मंच पर जोड़कर राज्य में कृषि नवाचार, तकनीकी सहयोग और निवेश को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला अहम मंच साबित होगा।

> "भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है, इसलिए इसे वैश्विक आंदोलन बनाना हमारी जिम्मेदारी है।"
>
> **- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी**

वैश्विक मंच पर राजस्थान की नई पहचान

दुनियाभर में मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने मिलेट्स को अंतरराष्ट्रीय खाद्य बाजार में नई पहचान दिलाई है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देश जलवायु-स्मार्ट कृषि मॉडल की तलाश में हैं और राजस्थान का रेगिस्तानी कृषि अनुभव इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत स्थानीय बीज प्रणाली और उन्नत कृषि तकनीकों के विस्तार के साथ राजस्थान देश की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले बाजरा बीज और कृषि तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

थार से उठती नई कृषि क्रांति

राजस्थान की बाजरा बीज आत्मनिर्भरता की यात्रा केवल कृषि सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक नवाचार, जलवायु अनुकूल कृषि, ग्रामीण विकास और किसान सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ते सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बन रही है। जब ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 में देश-विदेश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्यमी और किसान एक मंच पर एकत्र होंगे, तब राजस्थान की यह पहल टिकाऊ कृषि विकास और आधुनिक कृषि नवाचार के प्रभावशाली मॉडल के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी विशेष पहचान मजबूत करती दिखाई देगी। थार के रेगिस्तान से आगे बढ़ रही यह बाजरा पहल अब राजस्थान की कृषि क्षमता, नवाचार और भविष्य-उन्मुख सोच का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रही है। ■

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026

कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की पहल

राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का कृषि क्षेत्र नई संभावनाओं की ओर अग्रसर है और किसान तेजी से आत्मनिर्भरता व आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य से आयोजित होने वाली "ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026" कृषि क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। इस आयोजन में देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, एग्रीटेक कंपनियां, स्टार्टअप्स, निवेशक, पशुपालक और बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे। कार्यक्रम में कृषि नवाचार, नई तकनीकों, आधुनिक समाधानों और निवेश के अवसरों पर विशेष फोकस रहेगा। आयोजन के प्रचार-प्रसार हेतु नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद में रोड-शो आयोजित किए गए।

'सशक्त किसान- समृद्ध भारत' की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली में आयोजित ग्राम-2026 इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "सशक्त किसान, समृद्ध भारत" विज़न को धरातल पर उतारने के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों, कृषि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक मंच पर लाकर कृषि तकनीक के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

कृषि उत्पादन में राजस्थान अग्रणी

राजस्थान आज बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं मेथी, लहसुन, सौंफ, धनिया, अजवायन, मूंग और मूंगफली के उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। कृषि उत्पादन की यह विविधता फूड प्रोसेसिंग, स्पाइस पार्क और एग्री-एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं पैदा करती है। राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कृषि क्षेत्र में लगभग 44 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए, जिनमें से करीब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है।

टेक कंपनियों के लिए 'लिविंग लैब' बनेगा राजस्थान

बेंगलुरु इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान कृषि तकनीक और नवाचार के लिए 'लिविंग लैब' बन सकता है। प्रदेश में पानी और बिजली के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, जिससे कृषि निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत दो वर्षों में 65 हजार से अधिक सोलर पंप संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों की बिजली लागत में भारी कमी आई है और कृषि उत्पादकता बढ़ी है। आज प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और वर्ष 2027 तक इसे पूरे राजस्थान में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

हैदराबाद इन्वेस्टर्स मीट - निवेशकों को दिया 'पधारो म्हारो देस' का न्योता

हैदराबाद में आयोजित ग्राम-2026 इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों, एग्रीटेक स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राजस्थान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एग्रीटेक और फूड प्रोसेसिंग के सुनहरे अवसरों की भूमि बन चुका है। उन्होंने कहा कि कृषि पैदावार की विविधता के कारण राज्य में प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड चेन, स्पाइस पार्क और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ग्राम-2026 निवेशकों के लिए बड़े अवसरों का मंच है और राज्य सरकार निवेशकों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करने के लिए तैयार है। उन्होंने हैदराबाद के "लैब टू लैंड" मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग का यहां विकसित इकोसिस्टम राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी और ऊर्जा किसान की प्रगति के प्रमुख आधार हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर और गंगनहर के सुदृढ़ीकरण जैसे कार्य कर रही है।

राजस्थान बनेगा एग्री बिजनेस पावरहाउस

अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपनी कृषि विविधता के दम पर देश का बड़ा एग्री बिजनेस हब बन सकता है। राजस्थान और गुजरात की कृषि संरचना में समानताएं होने के कारण दोनों राज्यों के बीच फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं।

प्रदेश में अब तक फूड प्रोसेसिंग इकाइयों में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है। राज्य सरकार ने 39 फूड पार्क विकसित करने की योजना बनाई है, जिनमें से 34 स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। ■

श्रमेव जयते

राजस्थान में श्रम कल्याण

योजनाएं एवं उपलब्धियां

शैलेन्द्र सिंह, राज. आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा

आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए श्रम शक्ति किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है। राजस्थान जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में, जहां कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों समान रूप से जरूरी हैं, वहां एक संतुलित और समावेशी श्रम नीति की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी संदर्भ में राजस्थान सरकार ने अपनी वर्तमान श्रम नीति और श्रम सुधारों के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण- दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

राज्य सरकार ने 'श्रमिकों का सम्मान, सहूलियत और सुरक्षा' को अपनी श्रम नीति का मूल आधार घोषित किया है। राजस्थान में श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, खनन श्रमिक और छोटे उद्योगों से जुड़े कामगार शामिल हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई, खनन, वस्त्र उद्योग, पर्यटन और निर्माण क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। इसलिए श्रम नीति का फोकस केवल औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण पर भी है।

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल

राजस्थान में श्रम विभाग के अंतर्गत 'राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल' स्थापित है, जो निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। यह मंडल अब तक 33 लाख 14 हजार से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कर चुका है। मंडल द्वारा 26 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा 60 श्रमिक वर्ग अधिसूचित हैं।

प्रमुख श्रम कल्याण योजनाएं

1. **निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना**

   इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति दी जाती है। 10वीं या 12वीं में बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों को 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

2. **निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना**

   पंजीकृत हिताधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन) मिशन, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या

केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य आवास योजना की पात्रतानुसार आवास प्राप्त करने के लिए अथवा स्वयं का आवास निर्माण के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।

3. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों द्वारा अपने बैंक खातों के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए जमा कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि अथवा अंशदान (1000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने हेतु) राशि का 50 से 100 प्रतिशत तक मंडल द्वारा पुनर्भरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आम आदमी को बीमा योजना से लाभान्वित करने के लिए शत -प्रतिशत प्रीमियम राशि मंडल द्वारा दी जाएगी।

4. दुर्घटना सहायता एवं मृत्यु सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये एवं सामान्य मृत्यु होने की दशा में 2 लाख रुपये की सहायता राशि तथा दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रुपये, स्थाई आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपये तथा घायल होने पर 5 से 20 हजार रुपये तक सहायता राशि मंडल द्वारा दी जाती है।

5. प्रसूति सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत महिला हिताधिकारी अथवा पुरुष हिताधिकारी की पत्नी के अधिकतम 2 प्रसव के लिए देय प्रति प्रसव लड़के का जन्म होने पर 20 हजार रुपये तथा लड़की का जन्म होने पर 21 हजार रुपये की सहायता राशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जाता है।

6. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों को सिलिकोसिस पीड़ित होने पर 3 लाख रुपये तथा सिलिकोसिस से पीड़ित की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दी जाती है।

7. टूलकिट सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत तीन वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसका नियमित अंशदान जमा है, को 2 हजार रुपये कार्य संबंधित औजार खरीदने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

8. प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना

निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि देय होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक लाख रुपये तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रुपये। इसके अतिरिक्त आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस का पुनर्भरण तथा विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर 5 हजार रुपये का पुनर्भरण भी किया जाता है।

9. अंतरराष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अंतर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख रुपये, कांस्य पदक पर 5 लाख रुपये, रजत पदक पर 8 लाख रुपये तथा स्वर्ण पदक पर 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

10. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को 31 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया और 16 मई, 2009 से लागू किया गया। राजस्थान में इसके अंतर्गत 2011 के नियम

अधिसूचित हुए और असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

11. ई-श्रम पोर्टल - डिजिटल सशक्तीकरण

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'ई-श्रम' नाम से पंजीयन पोर्टल www.eshram.gov.in बनाया गया है, जिसे 26 अगस्त 2021 को प्रारंभ कर दिया गया। राजस्थान में ई-मित्र केन्द्रों को भी उक्त योजनाओं हेतु पंजीयन के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

12. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक मासिक अंशदान जमा करते हैं तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें 3 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है। योजना में श्रमिक द्वारा जमा की गई राशि के बराबर अंशदान केंद्र सरकार भी देती है।

महिला श्रमिकों का सशक्तीकरण

राजस्थान सरकार ने महिला श्रमिकों के कार्यस्थल पर बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें यौन शोषण रोकथाम दिशा-निर्देश, समान पारिश्रमिक अधिनियम की पालना, रात्रिकालीन कार्य में छूट तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम के तहत प्रसूति और अवकाश सुविधाएं शामिल हैं।

न्यूनतम मजदूरी एवं श्रमिक हितों की रक्षा

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राजस्थान में 56 से अधिक नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। राजस्थान सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन के उल्लंघन के मामलों में नियोजकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा एवं भविष्य निधि की निगरानी

इस योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्थान में ईएसआई के तहत बीमाकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। विभाग के श्रम निरीक्षकों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है और उल्लंघनों के मामले में कार्रवाई की जाती है।

LDMS पोर्टल — डिजिटल श्रम प्रशासन

राजस्थान श्रम विभाग ने श्रमिकों तक सेवाएं डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए LDMS (Labour Department Management System) पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक अपना पंजीयन, विभिन्न योजनाओं में आवेदन, छात्रवृत्ति फॉर्म और अन्य सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं।

राजस्थान बजट 2025-26 में श्रमिकों के लिए प्रावधान

राजस्थान के बजट 2025 -26 में श्रमिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति विवाह की गई। साथ ही, असहाय श्रमिकों को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाने का प्रावधान किया गया।

राजस्थान सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में काम करने वाले गिग वर्कर्स (जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी, राइड शेयरिंग, फ्रीलांस वर्कर्स) को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की पहल की। इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 350 करोड़ रुपये की लागत से एक नया गिग और असंगठित श्रमिक विकास कोष स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया।

श्रम शिकायत निवारण एवं हेल्पलाइन

श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-999 जारी किया गया है। विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों की छानबीन व निराकरण की कार्यवाही की जाती है। ट्रिपल सिस्टम अर्थात् त्रिपक्षीय कार्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुए श्रमिक हित में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं जिसमें सरकार, नियोजक और श्रमिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ■

सेहत के लिए सरकार की तकनीकी पहल

मधुनेत्र AI अभियान

तरुण कुमार जैन, उपनिदेशक

आमजन को बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार लगातार तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी विज़न के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित 'मिशन मधुनेत्र' कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो मधुमेह से ग्रसित मरीजों में होने वाली दृष्टिहीनता को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नवाचार के लिए विभाग को सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर सीएम-एक्सीलेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।

डायबिटीज रेटिनोपैथी - एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती

डायबिटीज एक मेटाबॉलिक विकार है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। डायबिटिक रेटिनोपैथी इसी बीमारी की एक गंभीर जटिलता है, जो सीधे आंखों के रेटिना को प्रभावित करती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके शुरुआती लक्षण सामान्यतः दिखाई नहीं देते और अक्सर तब पता चलता है जब दृष्टि प्रभावित हो चुकी होती है। देश और प्रदेश में केवल लगभग 10 प्रतिशत डायबिटीज मरीज ही नियमित रूप से आंखों की जांच करवाते हैं, जिसके कारण कई मामलों में दृष्टि हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मधुनेत्र एआई सिस्टम की कार्यप्रणाली

डायबिटिक रेटिना की जांच के लिए सामान्यतः नेत्र रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, लेकिन एआई आधारित फंडस कैमरा इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है। इस तकनीक के माध्यम से ली गई आंखों की तस्वीरों को एआई प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, जहां कुछ ही सेकंड में उनका विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। यह सिस्टम मरीज की स्थिति को चार श्रेणियों नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट और गंभीर में वर्गीकृत करता है, जिससे समय पर उपचार संभव हो पाता है।

डायबिटिक रेटिनोपैथी का उपचार और उपलब्ध सुविधाएं

डायबिटिक रेटिनोपैथी के गंभीर (ग्रेड-4) मरीजों के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत लगभग 16 हजार रुपये मूल्य का एंटी-वीईजीएफ इंजेक्शन उपलब्ध कराती है, जिससे दृष्टि बचाने में मदद मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर लेज़र उपचार की सुविधा भी दी जाती है। इस तकनीक के व्यापक उपयोग के लिए फंडस कैमरा मशीनों की उपलब्धता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मरीज लाभान्वित हो सकें।

पायलट प्रोजेक्ट और भविष्य की योजना

प्रदेश में यह कार्यक्रम वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिला अस्पतालों में शुरू किया गया है। विभाग का उद्देश्य इस नवाचार को निचले स्तर तक विस्तारित कर सभी मरीजों को सटीक और समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। जल्द ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के सहयोग से इसे सभी जिला अस्पतालों में लागू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पिछले वर्ष 5 अस्पतालों में एआई आधारित फंडस कैमरा प्रणाली के माध्यम से यह अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक 1 हजार से अधिक मरीजों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से लगभग 200 मरीज माइल्ड से गंभीर स्थिति की ओर बढ़ रहे थे, जिनका समय रहते उपचार संभव हो सका। इस सफलता के आधार पर राज्य सरकार ने इसे अन्य जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञों और ऑप्टोमेट्रिस्टों को एआई उपकरणों के प्रभावी उपयोग हेतु विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। ■

भारत की पहली
डिजिटल गणना
डिजिटल भारत की नई पहचान

डॉ. गोरधन लाल शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा

"जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। जनगणना 2027 डिजिटल और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी नागरिक इस महाअभियान से जुड़ें एवं राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देकर इसे सफल बनाएं।"

- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

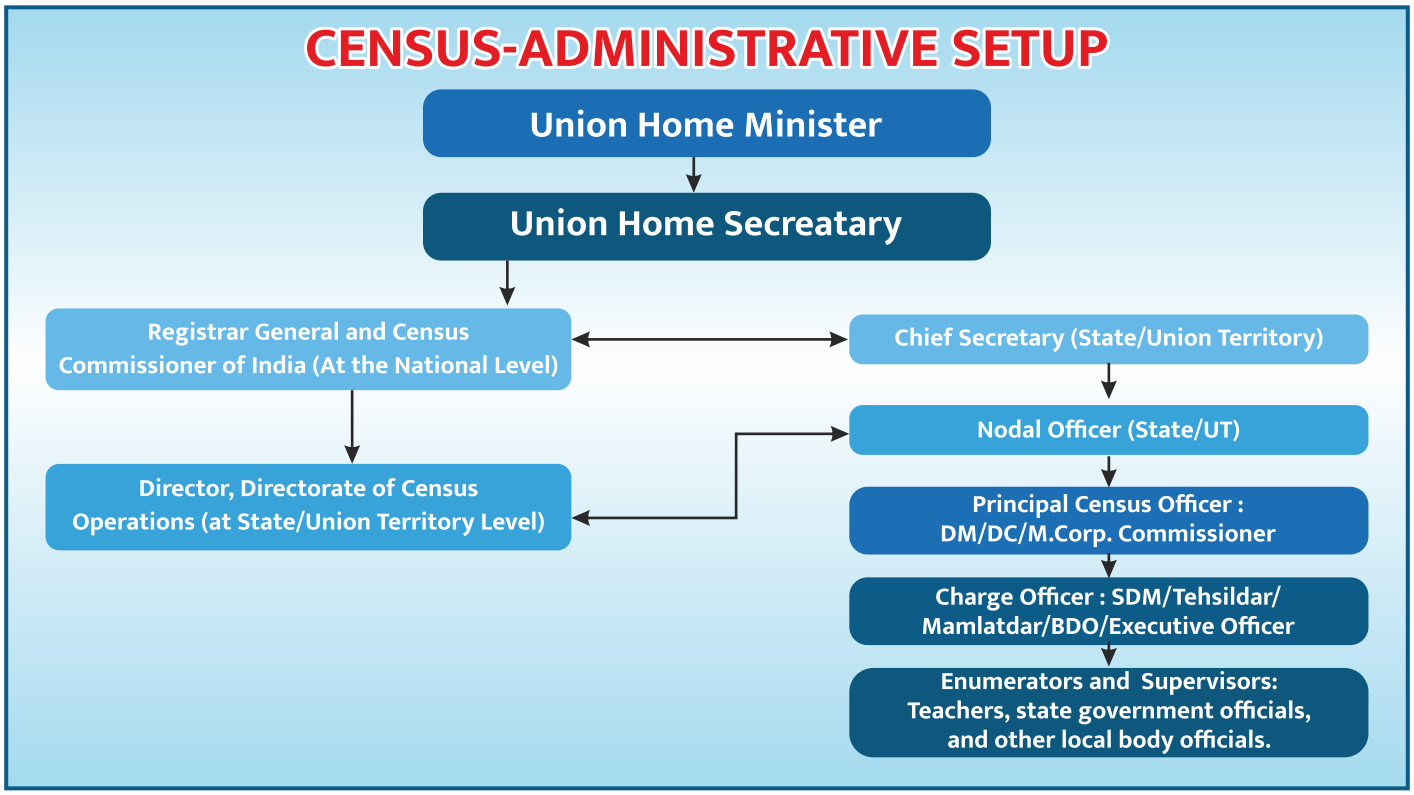

जनगणना किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। यह योजनाकारों, प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों का स्रोत होती है। जनगणना के आंकड़े शासन और नीति निर्माण में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता करते हैं तथा समावेशी और लक्षित विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारत में जनसंख्या की गणना के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, कर प्रणाली और सैन्य आवश्यकताओं के लिए जनसंख्या के आंकड़े जुटाने की पुख्ता व्यवस्था थी। भारत में जनगणना के सबसे प्राचीन साहित्यिक साक्ष्य ऋग्वेद से मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि उस काल में किसी न किसी प्रकार से आबादी की गिनती रखी जाती थी। मौर्य काल में कौटिल्य ने राज्य के प्रशासनिक और कर सुधारों के लिए जनसंख्या के आंकड़ों के संग्रह का स्पष्ट उल्लेख किया है।

पहली आधुनिक जनगणना वर्ष 1865-1872 के बीच आयोजित की गई, जबकि पहली समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में हुई। तब से भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना आयोजित की जा रही है, जो जनसंख्या संबंधी विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करती है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना समय पर नहीं की जा सकी। इसलिए, जनगणना 2027 इस क्रम की अगली गणना होगी, जो कुल मिलाकर भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। समय के साथ इसकी विधियों, कवरेज और प्रश्नावली में सुधार किए गए हैं ताकि जनसंख्या को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

जनगणना 2027 - डिजिटल भारत की नई पहचान

जनगणना 2027 विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान होगा, जिसमें डिजिटल तकनीक, मजबूत डेटा सुरक्षा और सरल प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मोबाइल आधारित डेटा संग्रह, सीएमएमएस पोर्टल द्वारा वास्तविक समय निगरानी, स्व-गणना की सुविधा और सटीक भौगोलिक मानचित्रण जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। साथ ही, इसमें जनसंख्या गणना चरण में व्यापक जातिगत गणना भी की जाएगी। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों की सहायता से, इस अभियान का उद्देश्य डेटा सुरक्षा और जन-भागीदारी के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए, अधिक तीव्र, सटीक और विस्तृत आंकड़े प्रदान करना है।

जनगणना 2027 की संस्थागत और विधिक संरचना

जनगणना 2027 एक मजबूत प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे पर आधारित है, जो डेटा संग्रह की विश्वसनीयता और देशभर में एकरूपता सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता के बाद से जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत किया जा रहा है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में जनगणना को संघ सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है। इसका समन्वय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

जनगणना का समय ही वह पैमाना है, जिससे गणनाकार यह तय करते हैं कि किन नागरिकों को सूची में शामिल किया जाना है।

डेटा गोपनीयता एवं वित्तीय स्वीकृति

यह ढांचा व्यक्तिगत जानकारी की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करता है, जिससे जनभागीदारी और सार्वजनिक विश्वास मजबूत होता है। जनगणना अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रहती है और उसे न तो आरटीआई के तहत सार्वजनिक किया जा सकता है, न न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है और न ही किसी अन्य संस्था के साथ साझा किया जा सकता है। जनगणना 2027 आयोजित करने की अधिसूचना 16 जून, 2025 को भारत के राजपत्र में जारी की गई थी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है।

डेटा संग्रह, ट्रांसमिशन और भंडारण के दौरान एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तथा सुरक्षित ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा। सभी डेटा को प्रमाणित और सुरक्षित डेटा केंद्रों में संगृहीत किया जाएगा, जिन्हें महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा (सीआईआई) घोषित किया गया है। ये प्रणालियाँ ISO/IEC 27001:2022 अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं तथा उनकी नियमित सुरक्षा ऑडिट भी कराई जाती है, जिससे एक सुरक्षित और विश्वसनीय डेटा इकोसिस्टम सुनिश्चित होता है।

दो चरणों वाली गणना की योजना और समय-सारणी

जनगणना 2027 को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण, हाउसलिस्टिंग एवं आवास गणना (एचएलओ), अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मकानों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। इस चरण से पहले 15 दिनों तक स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध रही। द्वितीय चरण, जनसंख्या गणना (पीई), फरवरी, 2027 में आयोजित होगी, जिसमें व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रवासन और प्रजनन संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। इसी चरण में जातिगत गणना भी की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में यह चरण सितंबर, 2026 में आयोजित होगा। सरकार ने जनवरी, 2026 में प्रथम चरण के लिए भवन और आवास संबंधी प्रश्नों का व्यापक सेट भी अधिसूचित कर दिया है।

जनगणना 2027 के लिए राज्य-वार कार्यक्रम

जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए, संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 की मध्यरात्रि होगी। समय के इसी निश्चित बिंदु को 'जनगणना का मानक क्षण' कहा जाता है।

जाति गणना

भारतीय जनगणना 2027 की एक प्रमुख विशेषता के रूप में जातिगत गणना उभर कर सामने आई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना तक, इस प्रक्रिया में केवल अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की ही व्यवस्थित गणना की जाती थी। इस बार 30 अप्रैल, 2025 को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) द्वारा लिए गए निर्णय के बाद, जनगणना 2027 के तहत जातिगत गणना भी की जाएगी।

डिजिटल माध्यम से पहली जनगणना

जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अभी से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया के वास्तविक समय में प्रबंधन और निगरानी के लिए 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' (सीएमएमएस) नामक एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है। एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से उप-मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी गणना की प्रगति, क्षेत्रीय कार्य-प्रदर्शन और परिचालन संबंधी तैयारियों की निगरानी कर सकेंगे।

हाउसलिस्टिंग और आवास जनगणना (एचएलओ) मोबाइल एप्लिकेशन

यह गणना करने वालों के लिए हाउसलिस्टिंग डेटा एकत्र करने और अपलोड करने हेतु एक सुरक्षित ऑफलाइन ऐप है, जिसका उपयोग केवल सीएमएमएस पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे। यह ऐप सीधे फील्ड-से-सर्वर तक डेटा भेजने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कागजी कार्रवाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यह एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा।

हाउसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (एचएलबीसी) वेब मैपिंग एप्लिकेशन

जनगणना 2027 का एक अन्य नवाचार एचएलबी क्रिएटर वेब मैपिंग एप्लिकेशन है, जिसका उपयोग चार्ज अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह सैटेलाइट इमेजरी (उपग्रह चित्रों) की मदद से हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) के डिजिटल निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे बिना किसी दोहराव या छूट के पूरे देश का सटीक भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित हो सकेगा।

स्व-गणना पोर्टल

घर-घर जाकर की जाने वाली गणना (फील्ड विजिट) से पहले 15 दिनों की एक वैकल्पिक 'स्व-गणना' अवधि दी गई। स्व-गणना पोर्टल एक सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा है, जो किसी परिवार के पात्र उत्तरदाताओं को क्षेत्रीय कार्य (फील्ड ऑपरेशंस) शुरू होने से पहले अपने परिवार की जानकारी

ऑनलाइन जमा करने की सुविधा देता है। सफलतापूर्वक डेटा जमा करने पर, एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) जनरेट होती है। इस एसई आईडी को एन्यूमेरेटर के साथ साझा करने से एन्यूमेरेटर द्वारा जानकारी की पुष्टि की जाती हैं।राज्य में स्व-गणना के माध्यम से 15 लाख से अधिक परिवारों द्वारा प्रथम चरण की प्रश्नावली भरी गई। राज्य में स्व-गणना पत्र के अंतर्गत भरे गये प्रपत्रों में जयपुर जिले के 21.4 प्रतिशत अर्थात लगभग 3 लाख से अधिक परिवार व सीकर जिले के 11.2 प्रतिशत परिवार स्व-गणना पूर्ण कर क्रमशः प्रथम स्थान व द्वितीय स्थान पर रहें।

न्यूनतम संभव समय में संपन्न करना

डेटा संग्रहण से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक के हर चरण में अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर, यह प्रयास किया जाएगा कि जनगणना के आंकड़े पूरे देश में न्यूनतम संभव समय में उपलब्ध कराए जा सकें। इसके अतिरिक्त, जनगणना के परिणामों को अधिक अनुकूलित विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स के माध्यम से प्रसारित करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

सुचारु क्रियान्वयन के लिए विस्तृत तैयारी

जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत 1 जनवरी, 2026 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रीज कर दी गई तथा नवंबर, 2025 में लगभग 5 हजार जनगणना ब्लॉकों में देशव्यापी प्री-टेस्ट आयोजित कर कार्यप्रणाली, डिजिटल उपकरणों और प्रशिक्षण प्रणालियों का परीक्षण किया गया। समन्वय और निगरानी को मजबूत करने के लिए जनवरी, 2026 में उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं और जिला व चार्ज स्तर पर जनगणना कर्मियों की नियुक्ति पूरी कर ली गई। क्षेत्रीय स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु 19 भाषाओं में विस्तृत निर्देश पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं। साथ ही, गतिविधियों के समयबद्ध निष्पादन और निरंतर निगरानी के लिए एक विस्तृत कैलेंडर लागू किया गया है, जिससे जनगणना प्रक्रिया की प्रशासनिक दक्षता और तैयारियां और अधिक मजबूत हुई हैं।

क्षमता संवर्धन एवं मानव संसाधन की पूर्व-तैयारी

जनगणना 2027 में मानव संसाधन की तैयारी पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए लगभग 31 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों तथा 1 लाख से अधिक जनगणना अधिकारियों को तैनात किया गया है। उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु प्रत्येक चरण के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और 80 हजार से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि डेटा की गुणवत्ता, सटीकता और कार्य दक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, जनगणना कार्यों के सफल संचालन के लिए लगभग 18,600 तकनीकी कर्मियों को करीब 550 दिनों के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिससे लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

सटीक आंकड़े, समृद्ध भविष्य - राजस्थान में जनगणना 2027 का शंखनाद

जनगणना 2027 भारत के लिए 'डेटा संचालित शासन' की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐतिहासिक रूप से जो प्रक्रिया कागजों के ढेरों में दबी रहती थी, वह अब 'प्रगति' और 'विकास' (जनगणना के शुभंकर) के माध्यम से एक आधुनिक, पारदर्शी और सशक्त भारत की तस्वीर पेश करने के लिए तैयार है। राजस्थान में 'जनगणना 2027' की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ 1 मई को राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे द्वारा लोक भवन में स्व-गणना के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही राज्य भर में जनगणना गतिविधियों का पहला चरण शुरू हुआ।

राजस्थान में जनगणना 2027 का प्रथम चरण 1 मई से 15 मई तक चला, जिसमें नागरिकों द्वारा पोर्टल के जरिये स्व-गणना की गई। इसके बाद मकानों की सूची और गणना का कार्य 16 मई से 14 जून तक प्रगणकों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसके पश्चात द्वितीय चरण में वास्तविक जनसंख्या गणना का कार्य फरवरी, 2027 में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण के मकान सूचीकरण एवं गणना के लिए स्व-गणना की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इस राष्ट्रीय प्रक्रिया में जनभागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की। उन्होंने कहा कि जनगणना शासन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो अगले दशक के लिए भारत की विकास योजना का आधार प्रदान करती है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े हमें विकास के स्तर और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की जरूरतों के बारे में बताते हैं। पुख्ता आंकड़ों से ही गांव-शहरों के व्यक्तियों और परिवारों की स्थिति, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, स्कूल, चिकित्सालय और घरेलू गैस कनेक्शन आदि की उपलब्धता और आवश्यकता के बारे में जानकारी मिलती है।

प्रदेश के 1 लाख 74 हजार से अधिक कार्मिक जनगणना में दे रहे सहभागिता

राज्य सरकार द्वारा जनगणना कार्य बेहतर क्रियान्वयन के लिए योग्य कार्मिकों एवं अधिकारियों का चयन कर जनगणना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 1 लाख 74 हजार से अधिक कार्मिक इस जनगणना को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। जनगणना की इस प्रक्रिया में सभी जिलों में कुल 759 चार्ज कार्यालय हैं।

वहीं, जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए 100 से अधिक मास्टर ट्रेनर और 2 हजार 500 से अधिक फील्ड ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया, जो प्रदेश के लगभग 1 लाख 74 हजार से अधिक कार्मिकों को विभिन्न चार्ज स्तरों पर प्रशिक्षित करेंगे। साथ ही, जनगणना के लिए प्रदेश में 1 लाख 42 हजार 177 हाउसलिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र से लेकर पंचायत स्तर तक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। मास्टर एवं फील्ड ट्रेनर्स द्वारा जिला और तहसील स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। डिजिटल माध्यम से डेटा प्राप्त होने पर भविष्य में फील्ड एन्यूमरेशन (क्षेत्रीय गणना) की निर्भरता कम होगी और प्राप्त आंकड़े अधिक सटीक व पारदर्शी होंगे। ■

हाइटेक वाचनालयों से संवर रहा युवाओं का भविष्य

गांव-ढाणियों तक पहुंच रही आधुनिक अध्ययन सुविधाएं

हरिशंकर आचार्य, उपनिदेशक

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में युवा कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इस दिशा में ऐसे सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे प्रदेश के युवा अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकें तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास में सार्थक योगदान दे सकें। विभिन्न सरकारी विभाग भी युवाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में बीकानेर जिले में युवाओं के भविष्य निर्माण को केंद्र में रखते हुए की गई एक अभिनव पहल प्रदेश के लिए प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में सामने आई है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सशक्त आधार

क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत बीकानेर जिले के दूरस्थ गांव-ढाणियों में रहने वाले युवाओं को अक्सर बेहतर अध्ययन वातावरण और आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। इसके तहत युवाओं को प्रतियोगी

परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल और आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत जिले की विभिन्न पंचायत समितियों की सौ से अधिक ग्राम पंचायतों में हाइटेक पुस्तकालय-वाचनालय स्थापित किए गए हैं, जो युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में सामने आए हैं। आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित ये वाचनालय न केवल अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहे हैं, बल्कि जिले के हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में सशक्त आधार भी तैयार कर रहे हैं।

वाचनालयों का विस्तार और सुविधाएं

जिले में अब तक कुल 105 वाचनालय बनाए जा चुके हैं। इनमें बज्जू खालसा पंचायत समिति में 13, पूगल में 14, लूणकरणसर तथा बीकानेर में नौ-नौ, नोखा तथा खाजूवाला में सत्रह-सत्रह तथा कोलायत में 6, श्रीडूंगरगढ़ एवं पांचू में दस-दस वाचनालय सम्मिलित हैं। यह वाचनालय 30 से 50 युवाओं की क्षमता के आधार पर बनाए गए हैं। जहां प्रतिदिन एक अथवा दो पारियों में बैठकर युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यह वाचनालय सभी सुविधाओं से युक्त हैं, जिनमें फर्नीचर, पानी, बिजली, कम्प्यूटर, वाईफाई तथा आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं।

संचालन, सहयोग और नियमित निगरानी

इन वाचनालयों में अध्ययनकर्ताओं से न्यूनतम शुल्क लिया जा रहा है, जिससे वाचनालय में केयरटेकर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है। इन वाचनालयों के निर्माण के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, पंद्रहवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सांसद स्थानीय विकास निधि, विधायक स्थानीय विकास निधि, डीएमएफटी सहित सीएसआर मद से राशि स्वीकृत की गई है। जिला स्तर से जिला कलक्टर तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इनकी नियमित समीक्षा की जा रही है।

जनसहभागिता से साकार हो रही पहल

जिले के जनप्रतिनिधि भी युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। उनकी अनुशंसा और सहयोग से विभिन्न स्थानों पर वाचनालय स्थापित किए गए हैं। जिला परिषद द्वारा जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से ऐसे वाचनालय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा वाचनालयों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा समय-समय पर सुविधाओं में भी विस्तार किया जा रहा है, जिससे युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध हो सके।

सकारात्मक परिणाम और बढ़ती भागीदारी

कुल मिलाकर युवाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की मंशा के अनुसार बीकानेर जिले की यह पहल बेहद कारगर साबित हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किए जाने के बाद इन वाचनालयों में युवाओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यहां युवा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के माहौल में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही, विचारों के आदान-प्रदान और सामूहिक अध्ययन की दृष्टि से भी ये वाचनालय महत्वपूर्ण केंद्र साबित हो रहे हैं। ■

भरतपुर में हो रहा है ऐतिहासिक मन्दिरों का भव्य कायाकल्प

आस्था, विरासत और विकास का संगम

बिहारीजी, गंगाजी और लक्ष्मणजी मंदिर

हरिओम सिंह गुर्जर, संयुक्त निदेशक

ब्रजभूमि की ऐतिहासिक नगरी भरतपुर सदियों से आस्था, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। यहां स्थित प्रमुख धार्मिक धरोहर बिहारीजी मंदिर, गंगाजी मंदिर और लक्ष्मण जी मंदिर न केवल स्थानीय श्रद्धा के केंद्र हैं, बल्कि अपने विशिष्ट इतिहास, स्थापत्य शैली और राजवंशीय संरक्षण के कारण पूरे प्रदेश में विशेष पहचान रखते हैं। ये तीनों मंदिर भरतपुर की धार्मिक चेतना, लोक-आस्थाओं और शिल्प परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य प्रगति पर है। इसके तहत इन तीनों आस्था केन्द्रों (बिहारीजी मंदिर, गंगाजी मंदिर और लक्ष्मण जी मन्दिर) का व्यापक जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है, जो न केवल धार्मिक महत्व को सुदृढ़ करेगा, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

बिहारीजी, गंगाजी और लक्ष्मणजी मंदिर का यह पुनरुद्धार कार्य केवल निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि आस्था के सम्मान और विरासत के संरक्षण का संकल्प है। यह पहल दर्शाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाकर सांस्कृतिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और समृद्ध बनाया जा सकता है। भरतपुर अब एक ऐसे धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां इतिहास की गूंज, आस्था की शक्ति और विकास की नई दिशा एक साथ दिखाई देती है।

बिहारीजी मंदिर - इतिहास के द्वार से आधुनिक सुविधाओं तक

लोक-मान्यताओं के अनुसार वैरागी नागा साधु चतुरशिरोमणि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को विग्रह के रूप में प्रकट किया। जब साधु इस विग्रह को जयपुर ले जा रहे थे, तो आगे नहीं बढ़ सके। इसे भगवत् इच्छा मानकर महाराजा सूरजमल के शासनकाल में (सन् 1760) लोहागढ़ किले में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर बंसी पहाड़पुर के पत्थर से बना है और नागर शैली में निर्मित है। इसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह मुख्य भाग हैं। मंदिर में बिहारी जी की 4 फुट ऊंची पाषाण मूर्ति के साथ धातु से बनी राधा जी की मूर्ति है, जो युगल स्वरूप में पूजे जाते हैं।

परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम

बिहारीजी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इस मंदिर को 3 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं के साथ पुरातन संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भव्य और आकर्षक मुख्य प्रवेश द्वार, भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पार्क की तरफ अतिरिक्त प्रवेश द्वार और रसोईघर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंदिर के सामने स्थित धर्मशाला का स्टोन वर्क द्वारा सौंदर्यीकरण तथा मुख्य सड़क की ओर हेरिटेज लुक के साथ नया प्रवेश द्वार तैयार किया जा रहा है। परिसर में फॉल्स वॉल और अन्य संरचनात्मक सुधार के कार्य शुरू किए गए हैं।

विरासत का वैभव ऐतिहासिक गंगाजी मंदिर

भरतपुर रियासत के महाराजा बलवंत सिंह को कोई संतान नहीं थी। राजपुरोहित ने उन्हें हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा मैया से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी। महाराजा बलवंत सिंह ने ऐसा ही किया, कुछ समय पश्चात महाराजा बलवंत सिंह को महाराजा जसवंत सिंह के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद महाराजा बलवंत सिंह ने सन् 1845 में गंगा मां के मंदिर के निर्माण की नींव रखी। मंदिर के निर्माण में बंसी पहाड़पुर के प्रसिद्ध लाल एवं गुलाबी पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर की नक्काशी, स्थापत्य कला और भव्यता का पूरा ख्याल रखा गया। यही वजह है कि महाराजा बलवंत सिंह के बाद भी 4 पीढ़ियों तक मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा और पांचवीं पीढ़ी ने 90 वर्ष के अन्तराल में मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया। सवाई बृजेंद्र सिंह ने 22 फरवरी 1937 को मंदिर में गंगा मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई। यह मन्दिर 275 गुणा 275 फीट में लाल बलुआ पत्थरों से बना है।

यूरोपियन, द्रविड़ एवं नागर शैली का होगा संगम

देश के प्रमुख गंगा मन्दिरों में एक गंगा माता मन्दिर के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्य 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से प्रगति पर है। यह मंदिर अब यूरोपियन, द्रविड़ एवं नागर शैली के संगम में दिखाई देगा। मन्दिर

परिसर के चारों ओर दुकानों के आगे लगी टिनशेड हटाकर 3.70 करोड़ रुपये से सौंदर्यीकरण एवं बाजार की तरफ बनी दुकानों को एकरुपता प्रदान करने के लिए फसाड़ कार्य प्रगति पर है। रियासत काल में गुम्बद बनने से शेष रहे मंदिर के ऊपर 50 फीट ऊंचाई का भव्य शिखर तथा 40 फीट ऊंचाई का मुख्य द्वार होगा, जिसमें मां गंगा के धरती पर अवतरण के वेग को धारण करने वाले भगवान शंकर की प्रतिमा लगाई जा रही है। परिसर में विशाल हॉल और रसोई का नवीनीकरण, छतरियों का पुनर्निर्माण और प्रसाद कक्षों का निर्माण भी हाथ में लिया गया है। मन्दिर में प्रतिदिन गंगा जल को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, इसके लिए एक हौद का निर्माण भी राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है।

भरतपुर के आराध्य लक्ष्मण जी मन्दिर

लक्ष्मण जी भरतपुर महाराजाओं के इष्ट देव रहे हैं। देशभर में प्रसिद्ध लक्ष्मण जी मंदिर की नींव सन् 1823-24 में महाराजा बलदेव सिंह ने रखी तथा निर्माण उनके पुत्र महाराजा बलवंत सिंह ने पूरा करवाया था। मन्दिर के प्रवेशद्वार बारहदरी तथा मुख्य भवन के साथ प्रस्तर तख्त पर भी नक्काशी की गई है। मन्दिर एक भव्य प्लेटफार्म पर बनाया गया है। गर्भगृह के चारों ओर कलापूर्ण खम्भे और परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। गर्भगृह में लक्ष्मणजी एवं उर्मिला जी की ऐतिहासिक प्रतिमाएं स्थापित हैं। लक्ष्मण जी मन्दिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1.25 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रगति पर हैं। इसके अंतर्गत परिक्रमा मार्ग का विकास, अधूरे कार्यों को पूर्ण करना, रसोई का जीर्णोद्धार तथा जर्जर पत्थरों को हटाकर उनकी जगह नक्काशीदार पत्थरों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

इन तीनों मंदिरों के कायाकल्प से भरतपुर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन के मानचित्र पर भी और अधिक सशक्त रूप से उभरेगा। यहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को अब बेहतर सुविधाएं और सुव्यवस्थित वातावरण मिलेगा। केवलादेव अभयारण्य में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को स्थापत्य कला के साथ आस्था, विरासत और विकास का संगम देखने को मिलेगा। ■

सौर ऊर्जा से सिंचाई में आत्मनिर्भर बने किसान

पीएम कुसुम योजना, डूंगरपुर

छाया चौबीसा
सहायक निदेशक, डूंगरपुर

जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिले में भौगोलिक विषमताओं और पहाड़ी परिस्थितियों के कारण लघु एवं सीमांत किसानों को कम भूमि, पानी की कमी और वर्षा पर निर्भरता के साथ-साथ बिजली की अनिश्चितता के चलते समय पर सिंचाई नहीं कर पाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कई ठोस कदम उठाए गए, जिनका सकारात्मक असर जनजाति क्षेत्रों के लघु और सीमांत कृषकों पर विशेष रूप से दिखाई दिया है। डूंगरपुर जैसे सुदूर पहाड़ी इलाकों में, जहां किसान पहले बिजली की अनिश्चितता के कारण समय पर सिंचाई नहीं कर पाते थे और आर्थिक कारणों से वैकल्पिक साधनों से वंचित थे, वहीं अब सौर पंपों की उपलब्धता ने खेती को अधिक सुगम और स्थिर बना दिया है, जिससे वे रबी, खरीफ और जायद इन तीनों मौसमों की फसलों की खेती करने में सक्षम हो रहे हैं।

दो वर्षों में 1168 जनजाति किसानों को मिला निःशुल्क सौर ऊर्जा संयंत्र

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पी.एम. कुसुम) योजना के कंपोनेंट-बी के तहत वर्ष 2024-25 में जिले के 239 कृषकों के यहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, जिनमें 229 अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान शामिल थे, जबकि वर्ष 2025-26 में 980 कृषकों के यहां संयंत्र स्थापित हुए, जिनमें 939 अनुसूचित जनजाति किसान लाभान्वित हुए। इस प्रकार दो वर्षों में कुल 1168 जनजाति किसानों को इसका लाभ मिला।

योजना का स्वरूप

पी.एम. कुसुम योजना के तहत सामान्य श्रेणी के कृषकों को 3 एच.पी. एवं 5 एच.पी. सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए क्रमशः 96,770 रुपये और 1,23,657 रुपये कृषक हिस्से के रूप में जमा कराने होते हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को इसके लिए

51,770 रुपये और 78,656 रुपये जमा कराने होते हैं। राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के किसानों को उद्यानिकी आयुक्तालय के जरिए प्रति सौर ऊर्जा पंप 45 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इसके साथ ही अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए शेष राशि हेतु भी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सहयोग से आर्थिक सहायता प्रदान कर योजना का लाभ उन्हें पूर्णतः निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराया गया है।

सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की पात्रता एवं आवश्यक शर्तें

इस योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए पात्रता में सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के नाम न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है, जबकि अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भू-स्वामित्व निर्धारित है। साथ ही, कृषक के पास पूर्व से कृषि बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए और यदि कनेक्शन है तो उसे समर्पित करना आवश्यक होता है।

सौर ऊर्जा से बढ़ी आय और आत्मनिर्भरता

राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में डूंगरपुर जिले के कुल 1168 जनजाति कृषकों के यहां निःशुल्क सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इससे उन्हें बिजली के बिल से राहत मिली है और उन्हें आर्थिक संबल मिला। साथ ही अब किसान सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहे और समय पर पानी की उपलब्धता के कारण पैदावार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे वे आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। ■

"राज्य सरकार द्वारा लगाए गए निःशुल्क सोलर पंप से मुझे काफी लाभ मिला है। अब मुझे रात में सिंचाई नहीं करनी पड़ती और बिजली का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ रहा है। सोलर पंप की वजह से मैं खेतों में अधिक सिंचाई कर पा रही हूं, जिससे मुझे आर्थिक लाभ हुआ है।"

केशु देवी

गांव धोलपुरा (तहसील साबला, जिला डूंगरपुर)

"इस वर्ष राज्य सरकार से 5 एच.पी. का सौर ऊर्जा पंप निःशुल्क मिलने के बाद सिंचाई में बहुत सुविधा हो गई है। अब मैं सब्जी की खेती भी कर रहा हूं और जब भी जरूरत होती है, आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा मुझे अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है, जिसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।"

भोगीलाल

गांव पांतली (तहसील दोवड़ा, जिला डूंगरपुर)

"मुझे 5 एच.पी. का सोलर पंप निःशुल्क मिला है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की अच्छी सुविधा हो गई है। इस बार मैंने गेहूं की फसल भी ली है और मुझे अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।"

विमल प्रकाश परमार

गांव रागेला (तहसील दोवड़ा, जिला डूंगरपुर)

ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक समृद्धि का नया प्रतिमान

राजस्थान महिला निधि

नेहा गिरि, भारतीय प्रशासनिक सेवा

भारत की विकास यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती, जब तक देश की महिलाएं आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक समान और सम्मानजनक पहुंच प्राप्त न कर लें। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी केवल आजीविका का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, परिवार की स्थिरता और स्थानीय अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। इसी दृष्टि से वित्तीय समावेशन वर्तमान में राष्ट्रीय विकास नीति का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरा है। राजीविका एवं मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 6 जिलों के 2242 महिला लाभार्थियों के अनुभवों से योजना की प्रभावशीलता और नीति-स्तरीय उपयोगिता का व्यापक आकलन संभव हुआ।

वित्तीय सेवाओं की सरलता और डिजिटल विस्तार

एक अध्ययन के अनुसार लगभग 84 प्रतिशत लाभार्थियों ने ऋण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बताया है। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में राजस्थान महिला निधि (आरएमएन) एक ऐसे अभिनव मॉडल के रूप में सामने आई है, जिसने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को केंद्र में रखकर वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण समाज के सबसे अंतिम छोर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह पहल केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तीकरण की एक समेकित प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई है। साथ ही, लगभग 15 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा दस्तावेजीकरण संबंधी अनुभव यह दर्शाते हैं कि वित्तीय समावेशन को और अधिक सरल एवं डिजिटल रूप से सुलभ बनाने की दिशा में आगे सुधार की संभावनाएं मौजूद हैं।

भरोसे और भागीदारी का मॉडल

राजस्थान महिला निधि की सबसे बड़ी विशेषता इसका समुदाय आधारित विकेन्द्रीकृत ढांचा है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली जो अक्सर ग्रामीण महिलाओं के लिए जटिल और दूरस्थ प्रतीत होती थी, वहीं इस मॉडल ने वित्तीय सेवाओं को उनके अपने सामाजिक ढांचे के भीतर उपलब्ध कराया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित यह प्रणाली महिलाओं में पारस्परिक विश्वास, सामूहिक उत्तरदायित्व और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करती है। इससे न केवल ऋण प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। यह मॉडल दर्शाता है कि जब वित्तीय सेवाओं को स्थानीय सामाजिक संरचना के अनुरूप ढाला जाता है, तब उनकी स्वीकार्यता और प्रभावशीलता दोनों बढ़ती हैं।

आय वृद्धि और ग्रामीण उद्यमिता का विस्तार

राजस्थान महिला निधि के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण आयाम ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि और रोजगार के नए अवसरों का सृजन है। योजना से जुड़ने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने कृषि, पशुपालन, सूक्ष्म उद्योग और लघु व्यापार जैसी उत्पादक गतिविधियों में निवेश किया है। लगभग 71.8 प्रतिशत महिलाओं ने ऋण का उपयोग कृषि, पशुपालन और लघु व्यवसायों के लिए किया। इस प्रक्रिया ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा दिया है। महिलाओं द्वारा स्थापित छोटे व्यवसाय केवल आय का स्रोत नहीं बने, बल्कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तीकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। राजस्थान में भी राजीविका के माध्यम से महिलाएं प्रदेश के विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर, आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। राजीविका की प्रत्येक बहन, पारिवारिक आय बढ़ाने में योगदान दे रही है और पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बना रही है।"

श्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

गतिविधियों को भी गति दी है। यह परिवर्तन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय बाजार व्यवस्था को भी सशक्त करता है।

आर्थिक सशक्तीकरण से सामाजिक परिवर्तन तक

महिलाओं को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिलने का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। राजस्थान महिला निधि से जुड़ी महिलाओं में पारिवारिक निर्णय-निर्माण में भागीदारी बढ़ी है और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई है। योजना से जुड़ने के बाद महिलाओं की औसत मासिक आय में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जब महिलाएं अपनी आय अर्जित करती हैं और वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, तब उनके सामाजिक सम्मान और नेतृत्व क्षमता में स्वाभाविक वृद्धि होती है। यह परिवर्तन ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति निर्माण की दिशा में कदम

यह पहल महिलाओं को केवल तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा की दिशा में भी अग्रसर कर रही है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने ऋण का उपयोग पशुधन, कृषि उपकरण, सूक्ष्म उद्योग उपकरण तथा अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया है। संपत्ति निर्माण ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार होता है। महिलाओं के स्वामित्व वाली परिसम्पतियां न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं, बल्कि परिवार और समाज में उनकी निर्णयात्मक भूमिका को भी सुदृढ़ बनाती हैं।

समावेशी भागीदारी और बहु-पीढ़ीय प्रभाव

राजस्थान महिला निधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी व्यापक समावेशिता है। इस पहल में विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। युवा महिलाओं के लिए यह उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता का अवसर प्रदान करती है, जबकि वरिष्ठ महिलाओं के लिए यह पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायक सिद्ध होती है। इसमें 19 से 85 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई, जो इस योजना की समावेशी प्रकृति को दर्शाती है। इस प्रकार यह मॉडल केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्रामीण समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की दीर्घकालिक नींव तैयार करता है।

कौशल, डिजिटल सशक्तीकरण और बाजार संपर्क

यह पहल उल्लेखनीय सफलता के साथ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, जहां भविष्य की संभावनाएं इसे और अधिक सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। महिलाओं की बढ़ती उद्यमिता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और बाजार से बेहतर जुड़ाव को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास निरंतर जारी हैं। लगभग 77 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है तथा 65 प्रतिशत से अधिक महिलाएं स्वयं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं।

समावेशी विकास की दिशा में प्रभावी मॉडल

राजस्थान महिला निधि यह सिद्ध करती है कि जब वित्तीय समावेशन को सामुदायिक भागीदारी, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तीकरण के साथ जोड़ा जाता है, तब यह महिलाओं के जीवन में गहरे और स्थायी परिवर्तन ला सकता है। यह मॉडल न केवल महिलाओं के आर्थिक उत्थान का माध्यम है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में एक सशक्त पहल भी है। ■

150 Years of the National Song

वंदे मातरम् और विधानसभा के नवाचार

गोपेन्द्र नाथ भट्ट, स्वतंत्र लेखक

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान विधानसभा द्वारा वर्ष 2026 का विशेष कैलेंडर तथा भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रकाशित दैनन्दिनी (डायरी), दोनों ही इस ऐतिहासिक अवसर को समर्पित अभिनव पहल के रूप में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाने की घोषणा भारतीय परंपरा के पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उसी क्रम में दैनन्दिनी का प्रकाशन भी इसी तिथि से प्रारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के मार्गदर्शन में तैयार ये प्रकाशन केवल तिथियों का संकलन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को सजीव रूप में प्रस्तुत करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

कैलेंडर एवं दैनन्दिनी एक साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रभावना और राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करते हैं। एक ओर जहां कैलेण्डर में वर्ष के 12 महीनों को एक ओर राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायी प्रसंगों से जोड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर दैनन्दिनी में प्रत्येक माह की शुरुआत अतीत और वर्तमान के स्वर्णिम दृश्यों के माध्यम से राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली यात्रा को दर्शाती है।

कैलेंडर वर्ष के 12 महीनों को 12 ऐतिहासिक तथ्यों से जोड़ते हुए राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की गौरवगाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। प्रत्येक माह में इसके इतिहास, रचना, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को सरल और प्रभावी शैली में दर्शाया गया है। इससे कैलेंडर देखने वाला व्यक्ति केवल तिथियां ही नहीं देखता, बल्कि हर माह राष्ट्रगीत के एक नए आयाम से भी परिचित होता है।

- जनवरी माह में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए वंदे मातरम् के प्रथम हिंदी अनुवाद (सरस्वती पत्रिका के जनवरी, 1906 के अंक में प्रकाशित) को स्थान दिया गया है।
- फरवरी माह रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस गीत के गायन को समर्पित है।
- मार्च में श्री बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के नैहाटी स्थित पैतृक घर के उस कक्ष का चित्र है, जहां वह साहित्य का सृजन करते थे।
- अप्रैल माह श्री अरबिन्दों घोष के विचारों को समर्पित है, जिसमें उन्होंने इस गीत को जन-जन की देशभक्ति का आधार बताया।
- मई में श्री बिपिन चंद्र पाल द्वारा प्रारंभ किए गए "वंदे मातरम्" समाचार पत्र और उसके सम्बन्ध में लाला लाजपत राय के विचारों का उल्लेख है।
- जून माह भगिनी निवेदिता द्वारा 1905 में बनाए गए व्रज ध्वज और उसमें निहित राष्ट्र चेतना की भावना को दर्शाता है।
- जुलाई में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित उन समाचार पत्रों के बारे में बताया गया है, जिनमें वंदे मातरम् का उल्लेख और भारत माता की तस्वीरें प्रकाशित होती थीं और जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया था।
- अगस्त माह में श्री मदनलाल ढींगरा के अंतिम शब्द "वंदे मातरम्" को वीरता की पुकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- सितंबर से नवंबर तक के पृष्ठों में इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिलने की यात्रा दिखाई गई है, जिसमें सेठ गोविन्द दास और श्री शिब्बनलाल सक्सेना के प्रयासों का उल्लेख है। साथ ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद के 24 जनवरी 1950 के संबोधन का अंश भी शामिल है, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम् को "जन-गण-मन" के समान सम्मान देने की बात कही थी।
- दिसंबर माह में श्री बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय से जुड़े पश्चिम बंगाल के लालगोला के प्रसंग को स्थान दिया गया है।
- दैनंदिनी में वर्ष के प्रत्येक माह की शुरुआत एक ऐसे स्वर्णिम दृश्य से होती है, जिसमें अतीत की ऐतिहासिक झलकियों और वर्तमान की आधुनिक राजस्थान विधानसभा का प्रेरणादायी समन्वय दिखाई देता है। प्रत्येक

माह का प्रथम पृष्ठ श्वेत-श्याम ऐतिहासिक चित्र से तथा उसके पृष्ठ भाग पर समकालीन उपलब्धियों को दर्शाते रंगीन चित्र है।

- चैत्र–वैशाख में वर्ष 1952 में सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा सवाई मानसिंह को राजप्रमुख पद की शपथ दिलाने के ऐतिहासिक क्षण का श्वेत-श्याम चित्र तथा वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव द्वारा श्री हरिभाऊ बागडे को शपथ दिलाते हुए वर्तमान परिदृश्य का रंगीन चित्र है।
- वैशाख–प्रथम ज्येष्ठ में जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल का श्वेत-श्याम चित्र और वर्तमान राजस्थान विधानसभा भवन का रंगीन चित्र प्रकाशित किया गया है।
- वैशाख–द्वितीय ज्येष्ठ में टाउन हॉल में संचालित पुरानी कार्यवाही श्वेत-श्याम तथा आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से युक्त वर्तमान विधानसभा सभागार में संचालित कार्यवाही के दृश्य का रंगीन चित्र प्रकाशित किया गया है।
- द्वितीय ज्येष्ठ–आषाढ़ में प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह के अभिभाषण (1956) का श्वेत-श्याम तथा वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण का रंगीन चित्र है।
- आषाढ़–श्रावण में वर्ष 1949 में श्री हीरालाल शास्त्री की सरकार के गठन का श्वेत-श्याम चित्र तथा वर्ष 2023 में श्री भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का रंगीन चित्र है।
- श्रावण–भाद्रपद में श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा विधानसभा संबोधन (वर्ष 1952) का श्वेत-श्याम चित्र तथा वर्ष 2023 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का रंगीन चित्र है।
- भाद्रपद–आश्विन में वर्ष 1961 की ऐतिहासिक घटना राज्यपाल गुरूमुख निहाल सिंह (राजभवन में अभिभाषण) का श्वेत-श्याम चित्र तथा महिला सशक्तीकरण का प्रतीक- श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुमित्रा सिंह और श्रीमती वसुन्धरा राजे के रंगीन छायाचित्रों का समावेश है।
- आश्विन–कार्तिक में श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा "विधान बोधनी" का विमोचन (वर्ष 1993) तथा वर्ष 2026 में श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 'संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष' के पुस्तक विमोचन का दृश्य है।
- कार्तिक–मार्गशीर्ष में विधानसभा भवन के शिलान्यास (वर्ष 1994) तथा वर्ष 2001 में श्री के. आर. नारायणन द्वारा लोकार्पण का चित्र है।
- मार्गशीर्ष–पौष में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रबोधन कार्यक्रम में संबोधन (वर्ष 1991) तथा श्री ओम बिरला के प्रबोधन कार्यक्रम में संबोधन (वर्ष 2024) को दर्शाया गया है।
- पौष–माघ में श्री रामनिवास मिर्धा द्वारा विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी के अवलोकन (वर्ष 1978) तथा वर्ष 2025 में डिजिटल म्यूजियम "वंदे मातरम् दीर्घा" के उद्घाटन का दृश्य है।
- माघ–फाल्गुन में टाउन हॉल का ऐतिहासिक गार्ड ऑफ ऑनर तथा वर्तमान विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर का गौरवपूर्ण दृश्य प्रस्तुत है।
- फाल्गुन–चैत्र में अंतरराष्ट्रीय संसदीय संबंधों को दर्शाते हुए सुश्री बेट्टी बूथरॉयड के स्वागत (अतीत) तथा वर्ष 2026 में ब्रिटिश सांसद श्री बॉब ब्लैकमैन की विधानसभा अध्यक्ष से की गई शिष्टाचार भेंट (वर्तमान) को दर्शाया गया है।

इस दैनन्दिनी में "राजस्थान एक नजर में" के साथ-साथ राज्य के सभी पूर्व एवं वर्तमान राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विधानसभाध्यक्षों, नेता प्रतिपक्ष, सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों तथा प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के नाम, छायाचित्र और संपर्क विवरण भी सम्मिलित किए गए हैं। ■

चौपाल से चौतरफा सशक्तीकरण

राजस्थान की बदलती तस्वीर

संतोष कुमावत, सहायक निदेशक

सुबह की हल्की धूप में गांव की चौपाल पर बैठे लोग—कोई पानी की बात कर रहा है, कोई सड़क की। बीच में बैठी महिला सरपंच सबकी बात सुनकर निर्णय ले रही है। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि आज के राजस्थान के बदलते गांवों की पहचान है। अब फैसले बाहर नहीं, गांव के बीच ही लिए जा रहे हैं। हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला पंचायती राज दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत गांवों में बसती है। राजस्थान ने इस दिशा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर से शुरू हुई यह व्यवस्था आज एक मजबूत जनभागीदारी मॉडल बन चुकी है।

पंचायती राज - गांव-गांव में लोकतंत्र

राजस्थान में पंचायती राज तीन स्तरों पर काम करता है—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम सभा के माध्यम से आम लोग सीधे फैसलों में भाग लेते हैं। यही कारण है कि अब विकास योजनाएं लोगों की जरूरतों के अनुसार बन रही हैं। राज्य में 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 1 मई (मजदूर दिवस)

को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिला परिषदें, 457 पंचायत समितियां और 14,403 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। पुनर्गठन के बाद 8 नई जिला परिषदों, 94 नई पंचायत समितियों और 3,467 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

राजस्थान की पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एक बड़ी क्रांति बनकर उभरी है। वर्ष 2020 के चुनावों में बड़ी संख्या में महिलाएं सरपंच बनीं। इससे न केवल नेतृत्व बदला है, बल्कि गांवों की सोच और प्राथमिकताएं भी बदली हैं। अब शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

सरकारी योजनाएं - विकास की रफ्तार

गांवों के विकास में कई योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है-

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जल संरक्षण, तालाब और चेक डैम से खेती को मजबूती मिली है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान - पंचायतों को प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
- स्वामित्व योजना - ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार और आर्थिक सुरक्षा मिली है।
- 15वां वित्त आयोग - पंचायतों को सीधे फंड मिलने से स्थानीय विकास तेज हुआ है।

राजस्थान सरकार - गांवों के विकास को नई दिशा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पंचायतों को मजबूत करने के लिए कई नवाचार किए गए हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर

वर्ष 2025 में आयोजित इन शिविरों ने गांवों में सरकारी सेवाओं को आसान बना दिया। एक ही जगह पर नामांतरण, पट्टा, प्रमाण पत्र जैसे कई काम पूरे हुए। इससे लोगों का समय बचा और प्रशासन पर भरोसा भी बढ़ा।

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान (2026)

यह अभियान गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। हर गांव के लिए अलग विकास योजना बनाई जा रही है- जहां सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

ग्राम रथ और कला जत्था अभियान

सरकार की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए यह अनोखा प्रयास किया गया है। लोक कलाकारों और मोबाइल वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी है।

नई सोच, नया राजस्थान

आज पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं रहीं, बल्कि बदलाव की ताकत बन चुकी हैं। डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता और जनभागीदारी ने इन्हें और प्रभावी बना दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के गांव आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बन रहे हैं। सरकार की सोच साफ है-"मजबूत गांव, मजबूत राजस्थान"। पंचायती राज अब केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि गांवों की आत्मनिर्भरता की कहानी बन चुका है। जब चौपाल में बैठकर लोग अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, तब असली लोकतंत्र मजबूत होता है। राजस्थान के गांव आज उसी सशक्त लोकतंत्र का उदाहरण बन रहे हैं- जहां हर आवाज सुनी जाती है और हर व्यक्ति विकास का भागीदार है। ■

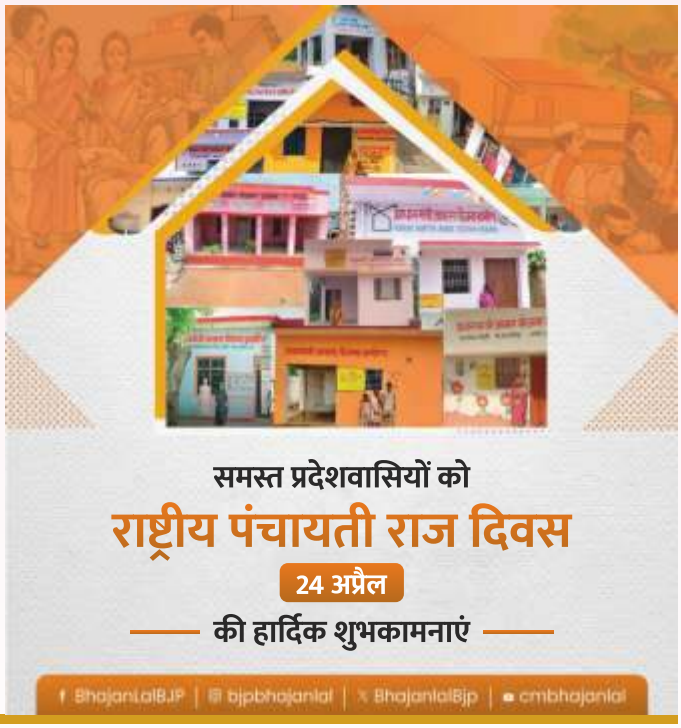

जन संवाद से समस्या समाधान तक

ग्राम विकास चौपाल

विकास और विश्वास की नई मिसाल

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के कड़ैल, सीकर के जाजोद, प्रतापगढ़ के बम्बोरी और जालोर के पंसेरी, जयपुर के ठिकरिया और बांसवाड़ा के चुड़ादा गांवों में ग्राम विकास चौपाल आयोजित कर रात्रि प्रवास किया तथा गांवों में पैदल भ्रमण कर किसानों, महिलाओं, युवाओं, पशुपालकों और बुजुर्गों से सीधे संवाद किया। उनके अनुभव जाने और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया। ■

जालोर में मिली 0 को पहचान

भीनमाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने विश्व-गणित को दी नई दिशा

राजस्थान में शुरू होगा 'ब्रह्मगुप्त पुरस्कार'

संदीप जोशी, शिक्षाविद

भारत को विश्व में यदि किसी बौद्धिक देन के लिए सबसे अधिक पहचाना जाता है, तो वह है गणित। भारतीय गणित की परंपरा विश्व इतिहास में अद्वितीय स्थान रखती है। आर्यभट्ट से लेकर श्रीनिवास रामानुजन तक गणितज्ञों की लंबी गौरवशाली शृंखला है। दशमलव पद्धति, शून्य की अवधारणा, बीजगणितीय विधियां और खगोल गणना, ये सभी योगदान मानव सभ्यता की प्रगति में आधारभूत सिद्ध हुए हैं। आधुनिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान सबकी नींव दशमलव पद्धति और शून्य, इसी गणितीय संरचना पर टिकी हैं। किंतु बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि शून्य को गणितीय नियमों के साथ व्यवस्थित स्वरूप देने का कार्य सातवीं शताब्दी में राजस्थान की धरती पर हुआ था। आज के जालोर जिले का भीनमाल (प्राचीन श्रीमाल) वह ऐतिहासिक स्थल है, जहां महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने जन्म लिया और विश्व गणित को नई दिशा दी।

शून्य की अवधारणा

सामान्य जनमानस में एक धारणा प्रचलित है कि "शून्य का आविष्कार" आर्यभट्ट ने किया। अकादमिक जगत में भी प्रायः उनका नाम शून्य के संदर्भ में लिया जाता है। वास्तव में स्थिति अधिक सूक्ष्म और ऐतिहासिक रूप से जटिल है। शून्य की अवधारणा भारतीय गणना-पद्धति में क्रमशः विकसित हुई और शून्य के गणितीय नियमों को व्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय मुख्यतः ब्रह्मगुप्त को जाता है। इसी संदर्भ में राजस्थान का प्राचीन नगर भीनमाल बीजगणित की एक महत्वपूर्ण "गंगोत्री" के रूप में उभरता है।

आर्यभट्ट का गणित और खगोल विज्ञान में योगदान

पांचवीं शताब्दी के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आर्यभटीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें गणित और खगोल विज्ञान के अनेक मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित

किए गए। उन्होंने पाई (π) का अत्यंत सटीक मान 3.1416 के निकट दिया और पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत तथा ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। उनके ग्रंथ में शून्य का आधुनिक अर्थों में स्पष्ट नियमात्मक प्रतिपादन नहीं मिलता। स्थान-मूल्य प्रणाली में रिक्त स्थान का प्रयोग था, लेकिन शून्य के साथ गणितीय संक्रियाओं के नियम बाद में स्पष्ट हुए। इस प्रकार आर्यभट्ट का योगदान गणित और खगोल विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि शून्य के औपचारिक सिद्धांत का श्रेय बाद के आचार्य को जाता है।

ब्रह्मगुप्त और शून्य के गणितीय नियम

598 ईस्वी में जालोर जिले के भीनमाल में जन्मे ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुटसिद्धांत की रचना की। इसी ग्रंथ में पहली बार शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के स्पष्ट नियम दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर वही संख्या रहती है ($x + 0 = x$) और किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर परिणाम शून्य होता है ($x \times 0 = 0$)। उन्होंने ऋण और धन संख्याओं के साथ संक्रियाओं के नियम भी निर्धारित किए। यद्यपि शून्य से भाग देने के नियम में कुछ अपूर्णताएं थीं, फिर भी यह पहली बार था जब शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में स्वीकार कर उसके साथ संक्रियाएं परिभाषित की गईं। शून्य को संख्या के रूप में स्थापित करने और उसके नियम प्रतिपादित करने का श्रेय ब्रह्मगुप्त को जाता है, जिन्होंने इसे केवल रिक्त स्थान नहीं, बल्कि एक गणितीय इकाई के रूप में प्रस्तुत किया।

आधुनिक बीजगणित की नींव

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि बीजगणित के वास्तविक पितामह ब्रह्मगुप्त हैं। यद्यपि नवीं शताब्दी के अरब गणितज्ञ अल-ख्वारिज्मी को दुनिया 'बीजगणित का पिता' मानती है, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने उनसे लगभग 200 वर्ष पूर्व ही बीजगणित के सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया था, जिन्हें आज आधुनिक बीजगणित का आधार माना जाता है। उन्होंने ऋणात्मक संख्याओं (धन और ऋण) की अवधारणा दी और नियम बताया कि दो ऋण संख्याओं का गुणनफल धन होता है (- × - = +)। ब्रह्मगुप्त की गणितीय परंपरा भारत की प्राचीन वैदिक गणितीय परंपरा से जुड़ी है। ऋग्वैदिक काल से ही गणितीय चिंतन विकसित था और शुल्ब सूत्रों में जटिल गणनाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें भारतीय बीजगणित और ज्यामिति के प्रारंभिक साक्ष्य माना जाता है। आज जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वह बौधायन के सूत्रों में पहले से मिलता है। ब्रह्मगुप्त ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियमों के माध्यम से बीजगणित को वैज्ञानिक स्वरूप दिया, जो आगे चलकर आधुनिक बीजगणित का आधार बना।

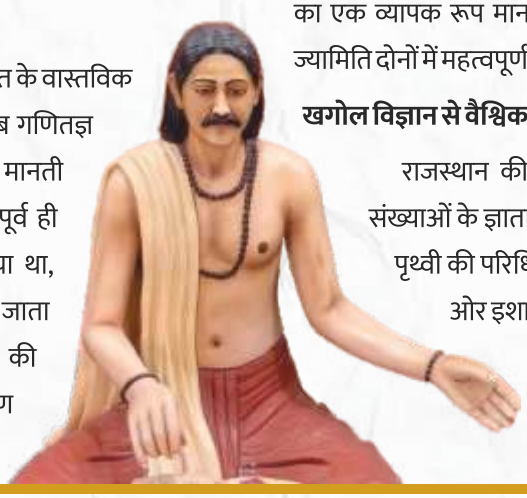

द्विघात समीकरण और ब्रह्मगुप्त सूत्र

द्विघात समीकरण ($ax^2 + bx + c = 0$) जैसे जटिल समीकरणों को हल करने का सूत्र ब्रह्मगुप्त से जोड़ा जाता है। उन्होंने ज्यामिति में भी बीजगणित का प्रयोग करते हुए चक्रीय चतुर्भुज के लिए प्रसिद्ध 'ब्रह्मगुप्त सूत्र' दिया, जिसमें चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। उन्होंने शून्य के प्रमुख नियम भी बताए। शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है और शून्य से किसी भी संख्या का गुणनफल शून्य होता है। उन्होंने ऋण और धन संख्याओं के नियम भी निर्धारित किए, जैसे ऋण संख्याओं का योग ऋण होता है और उनका गुणनफल धन होता है। चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए उन्होंने अर्ध-परिधि ($s = (a + b + c + d)/2$) की अवधारणा का उपयोग कर सूत्र प्रस्तुत किया, जिसे आज 'ब्रह्मगुप्त सूत्र' कहा जाता है। यह हीरोन के सूत्र का एक व्यापक रूप माना जाता है। इस प्रकार उन्होंने अमूर्त गणित और ज्यामिति दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

खगोल विज्ञान से वैश्विक ज्ञान यात्रा तक

राजस्थान की माटी में जन्मे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त केवल संख्याओं के ज्ञाता नहीं थे, वे एक महान खगोलशास्त्री भी थे। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की ओर इशारा करते हुए कहा था-"जैसे पानी का स्वभाव बहना है, वैसे ही पृथ्वी का स्वभाव वस्तुओं को अपनी ओर खींचना है।" यह कथन न्यूटन से एक हजार वर्ष पूर्व का है। उनके इसी विराट

ब्रह्मगुप्त पुरस्कार से सम्मानित होंगी
वैज्ञानिक प्रतिभाएं

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर राजस्थान में 'ब्रह्मगुप्त पुरस्कार' शुरू करने की घोषणा की। यह पुरस्कार विज्ञान, गणित, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा।

व्यक्तित्व के कारण उन्हें 'गणकचक्रचूड़ामणि' (गणितज्ञों के मुकुट का रत्न) कहा गया।

ज्ञान का वैश्विक प्रवाह - जालोर से यूरोप तक

ज्ञान के वैश्विक प्रवाह की कहानी राजस्थान के जालोर से यूरोप तक जाती है। आठवीं शताब्दी में भारतीय विद्वान 'ब्रह्मस्फुट सिद्धांत' लेकर बगदाद पहुंचे। इसका अरबी अनुवाद 'सिंधहिंद' नाम से हुआ, जिसे इब्राहिम अल-फजारी और मुहम्मद इब्न इब्राहिम अल-फजारी ने एक भारतीय विद्वान (संभवतः कनक) की सहायता से किया।

हिंदू-अरबी अंक प्रणाली और बीजगणित का वैश्विक विस्तार

अल-ख्वारिज्मी ने 'सिंधहिंद' का अध्ययन कर भारतीय अंक प्रणाली (0–9) को अपनाया, जिसे अरबों ने 'हिंदसा' कहा और बाद में यूरोप में यह 'अरबी अंक' के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुटसिद्धांत के आधार पर अल-ख्वारिज्मी ने अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत कीं और उनकी पुस्तक 'किताब अल-जबर वल-मुकाबला' से 'अलजेब्रा' शब्द विकसित हुआ। बाद में यह ज्ञान यूरोप पहुंचा और बारहवीं शताब्दी में फिबोनाची ने हिंदू-अरबी अंकों को यूरोप में प्रसारित किया। इस प्रकार गणितीय ज्ञान की गंगोत्री भारत मानी जाती है। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ-साथ द्विघात समीकरणों, चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल (ब्रह्मगुप्त सूत्र) और अनिर्धार्य समीकरणों पर भी कार्य किया। यह ज्ञान परंपरा आगे भास्कराचार्य तक विकसित हुई। ब्रह्मस्फुटसिद्धांत के अरबी अनुवाद 'सिंधहिंद' के माध्यम से भारतीय गणित यूरोप तक पहुंचा, जिससे आधुनिक विज्ञान की नींव मजबूत हुई।

भीनमाल - प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र

आज का भीनमाल, जो प्राचीन काल में श्रीमाल कहलाता था, सातवीं शताब्दी में एक समृद्ध और शिक्षित नगर था। यह व्यापारिक मार्गों से जुड़ा था और यहां संस्कृत व जैन विद्वानों की परंपरा सक्रिय थी। उसी काल में महाकवि माघ ने शिशुपालवध की रचना की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भीनमाल केवल गणित का केंद्र नहीं, बल्कि व्यापक बौद्धिक चेतना का नगर था। यह नगर प्राचीन गुर्जर साम्राज्य की राजधानी रहा और राजनीतिक रूप से यह हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत की स्थिरता व सांस्कृतिक समृद्धि का समय था, जिससे गणित और खगोल विज्ञान का विकास हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी पुस्तक सी-यू-की (Si-Yu-Ki) में भीनमाल (पीलो-मोलो) का उल्लेख किया है और यहां की बौद्धिक संपदा का वर्णन किया है।

राजस्थान की ज्ञान-परंपरा और वैश्विक बौद्धिक विरासत

अक्सर राजस्थान की पहचान यहां के अदम्य साहस, किलों और केसरिया बाने से होती रही है, किंतु इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि यह मरुधरा केवल शौर्य की ही नहीं, बल्कि 'अगाध ज्ञान' की भी गंगोत्री रही है। जालोर की माटी से उपजे ब्रह्मगुप्त की गणितीय मेधा ने यह सिद्ध किया है कि राजस्थान के धोरों में केवल वीरता का लहू ही नहीं, बल्कि विज्ञान और गणित की सरिता भी प्रवाहित रही है। ■

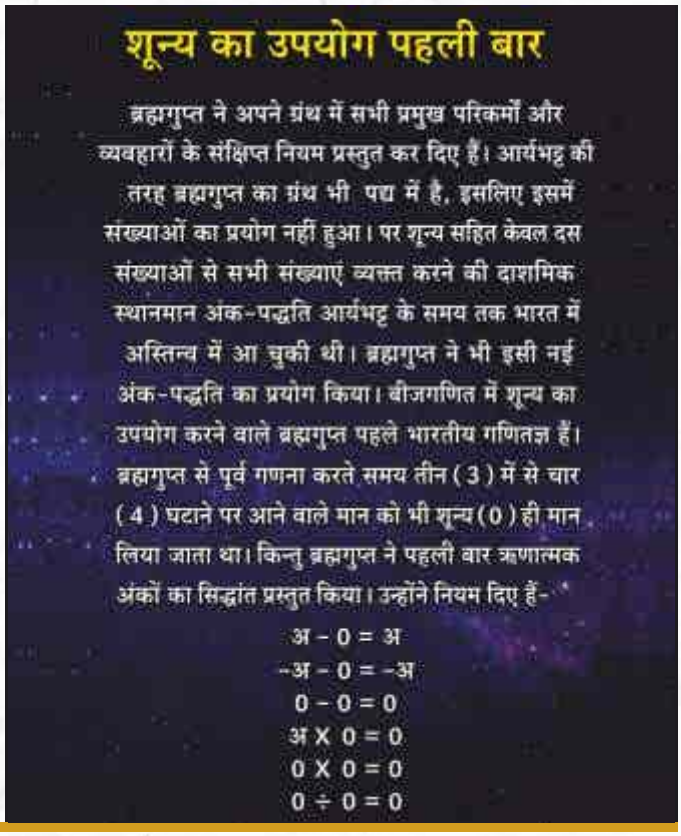

Ministry of Home Affairs

Leads a Youth-Centric Anti-Drug Mission

Through NCORD

Isha Saini, APRO

India's fight against drug abuse is closely linked to safeguarding its youth, who are regarded as the nation's greatest strength. As concerns surrounding substance abuse continue to grow, the response has evolved from isolated enforcement measures to a comprehensive, preventive and community-driven approach. Recognising this urgency, the Government of India has strengthened its efforts through the Narco-Coordination Centre (NCORD), placing youth protection at the centre of its anti-drug mission.

Established under the Ministry of Home Affairs, NCORD serves as a unified coordination mechanism, bringing together enforcement agencies, policymakers and social sector departments. The Narcotics Control Bureau acts as the nodal coordinating body, enabling real-time intelligence sharing and coordinated action across the country. With its four-tier structure - Apex, Executive, State and District levels - NCORD ensures the effective implementation of anti-narcotics efforts from the national level down to the grassroots.

What makes this framework particularly effective is its balanced approach. While stringent enforcement under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985 targets trafficking networks, equal emphasis is placed on awareness, rehabilitation and prevention. Campaigns in schools, colleges and communities aim to prevent the initiation of drug use, reinforcing the idea that an informed society is the strongest defence against substance abuse.

Rajasthan: Turning Policy into People-Centric Action

Rajasthan is steadily translating this national vision into action on the ground. By operationalising the NCORD framework, the state has ensured close coordination between the Home Department, Police, Excise, Health and Social Justice departments.

Targeted enforcement measures, such as scientific disposal of seized narcotics, strict action against illegal cultivation and focused crackdowns on trafficking networks, have strengthened supply-side control. Simultaneously, sustained awareness campaigns and outreach efforts are engaging communities, particularly youth, in prevention initiatives. Helplines like MANAS (1933) and awareness drives in educational institutions reflect a clear shift towards early intervention and community participation.

Raj-SAVERA: A Budget-Backed Integrated Response

Further strengthening these efforts, the State Budget 2026–27 has announced the Raj-SAVERA programme (Statewide Anti-Drugs Vigilance, Enforcement, Rehabilitation and Awareness), providing a structured and integrated framework to combat substance abuse. The programme brings together enforcement, vigilance, awareness and rehabilitation under a unified strategy. Alongside strengthening action against drug trafficking, it emphasises preventive awareness, counselling and improved access to de-addiction services. ■

लोक रौ सरूप अर लोक साहित्य

राजस्थानी लोक साहित्य री सांस्कृतिक विरासत

प्रो. अर्जुन देव चारण, राजस्थानी कवि-नाटककार

लोक साहित्य रौ अरथ होवै 'लोक' रौ साहित्य। इण वास्तै सैं सूं पैलां 'लोक' अर 'साहित्य' रै अरथ नै समझण री जरुत है। अै दो न्यारा सबद दो न्यारी दुनिया रचै पण जद दोनूं साथै जुड़ै, तद आपरै परिवेस में आखी स्रिस्टी नै समेट लेवै। 'लोक' सबद री व्युत्पत्ति रुच/लुच धातु सूं मानीजी है, जिणरौ अरथ होवै प्रकासित होवणौ या प्रकासित करणौ। इण सूं बणण वाळा सबद है आलोक, लोचन, आलोचना, लौकिक, लोकोत्तर, लोकायत। प्रकासित करण रै अरथ में 'लोक' रौ खेतर अणूंतौ विस्तार लियोड़ौ मानीजै। इणी सारूं, अपां 'लोक' रौ अरथ करां 'संसार'। तीन लोक, सात लोक या चवदै लोक भी इणी सारूं कैइजिया है। इणरौ अरथ इण 'लोक' में रैवण वाळी जनता भी है। क्यूंकै इणरौ अरथ प्रकास सूं जुड़ियोड़ौ है, तौ अपारै सांम्ही जका भी परतख अणभव रा विसय है, वै भी इणरै अन्तर्गत आवै है।

'लोक' सबद री अेक दूजी व्युत्पत्ति 'लोकृदर्शने' धातु में 'घञ्' प्रत्यय लगावण सूं उपजियोड़ी मानी जावै है। इण धातु सूं 'देखण' रौ भाव अभिव्यक्त होवै। इण वास्तै 'लोक' सबद रौ अरथ होय जावै 'देखण वाळौ'। हरेक प्राणी जकौ 'देखण' रौ काम करै, वौ उणनै इणमें स्वीकार करै। 'देखण' रौ भाव पसुवां में, पंखेरुवां में भी मिलै है अर विग्यान तो अठै तांई कैवै के झाड़, बूंटा अर रुंख भी देखै है। इण बात री पुस्टि अपारै लोक साहित्यय में घड़ी-घड़ी होवती भी दीखै। अपांनै इण 'देखण' नै ठीक सूं समझणौ चाइजै क्यूंकै 'लोक' रौ दूजौ अरथ होवै देखण वाळौ जन समुदाय।

'लोक' रौ अरथ है प्रकास। इणी सारूं सबद बणियौ आलोक पण उणरौ अस्थ कांई होवै, औ समझणौ चाइजै। औ अरथ अपांरी इन्द्रियां सूं जुड़ियोड़ौ है। उजास रौ सीधौ सम्बन्ध अपांरी आंखियां सूं जुड़ै। तद 'लोक' रौ अरथ होवै अपांरी आंखियां सूं देखियोड़ौ संसार। औ अणभव अपांरी ग्यानेंद्रियां री सक्रियता बतावै क्यूं कै 'देखणौ' फगत देखणौ इज नीं होवै, वौ सुणणौ भी होवै, वौ मैसूस करणौ भी होवै। उणरै साथै अपांरी कल्पना सगती जागै। उणरै कारण अपारै मांय कीं 'रचण' री ईच्छा रौ स्फुरण होवै, अपांरौ मन अर चित्त उणरै साथै

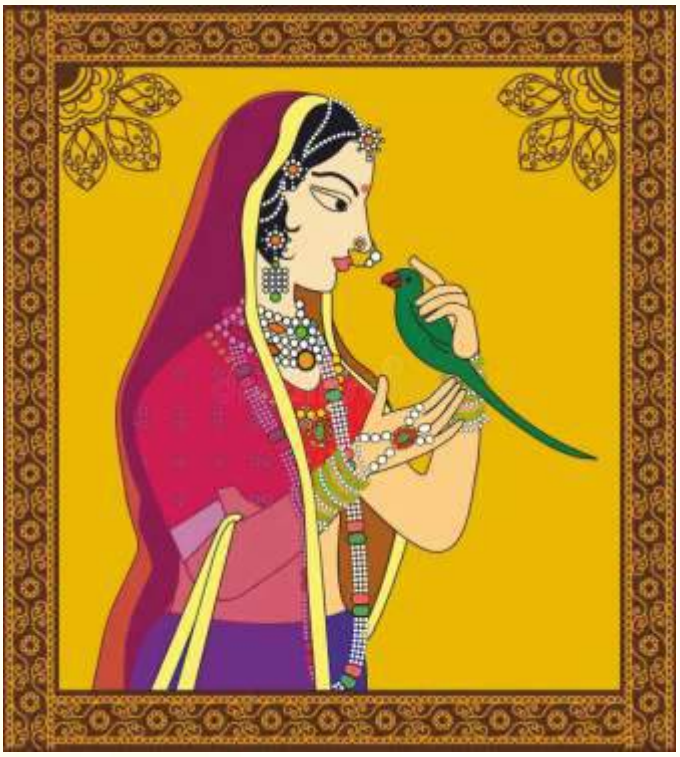

जुड़ै। इण तरै सूं उण 'देखण' रै भाव पसराव होवै जको साहित्य रै रचण री प्रेरणा बणै।

भारतीय परम्परा में 'लोक' रौ अरथ करती बेळा औ याद राखणौ है कै अठै 'लोक' फगत मिनख जात री बात इज नीं करै है, उणरै दायरै में आखी स्रिस्टी समायोड़ी है। आ दीठ अेकांगी नीं है, अठै व्यस्टि भाव री बात नीं करीजै बल्कि अठै तौ समस्टि री बात करण वाळी दीठ री थरपना करीजै, जकी जीवण नै पूरणता देवण री आकांक्षा सूं परिचालित होवै। जठै पूरणता री प्रतिस्ठा होवै, उठै लोक मंगळ या लोक कल्याण री भावना तो होवैला इज। इण सारूं, जद अपां लोक साहित्य नै देखां, तद उणमें लोक रै उजास सूं सुरु होयोड़ी आ देखण री जातरा हरेक 'स्थिति' नै समग्रता में देखै, जिण सूं लोक री दीठ अखण्ड रै बोध सूं जुड़ै। देखण अर सुणण सूं सुरु होयोड़ी इण प्रक्रिया में केई चीजां साथै-साथै घटित होवै, जिणरौ वरणन अर विवरण मिनख री 'कल्पना' रै पांण साहित्य रै सरुप नै घड़ै। अपांरी सास्तरीय परम्परा में तौ कल्पना रौ विसेस बखांण देखण नै मिळै इज है पण लोक री 'दीठ' आपरी कल्पना अर स्मृति रै तानै बानै सूं जिण बणगट री सिरजणा करै, उणनै इज अपां लोक साहित्य रौ नाम देवां।

'लोक' रौ अरथ जद 'देखण वाळौ' करां तद आ सावचेती राखणी पड़े, के अपां 'प्रकृति' नै उपभोग री वस्तु नीं मानां। आथूणी संस्कृति अरथात् पास्चात्य संस्कृति अर भारतीय संस्कृति में 'प्रकृति' रै साथै मिनख रै वैवार में घणौ फरक दीखै। इण फरक रौ कारण औ 'देखणौ' इज है। भारतीय संस्कृति में मिनख 'प्रकृति' रै साथै होय, उणरौ हिस्सो होय जीवै। इण वास्तै भारतीय 'दीठ' में प्रकृति नै लूटण रौ भाव नीं मिळै। अपांरी संस्कृति में देखण वाळौ महताऊ है। वो कीकर देख रैयौ है, उण माथै समाज री निजर रैवै। अठै देखण वाळौ फगत 'अेक' होय नीं देखै बल्कि वो 'सब' होय, 'सर्वमय' होय देखै अर सम्यक् देखै। इण वास्तै वौ देखणौ आधौ -अधूरौ 'देखणौ' नीं होवै। वौ फगत 'देखणौ' नीं रैवै, वौ होवणौ अर पावणौ भी होय जावै। औ पावणौ इज लोक दीठ नै मिरतु रै भौ सूं मुगत करै।

लोक दीठ में रची बसी जकी परतखता (प्रत्यक्षता) है, वा मिनखाजूंण रै वरतमांन नै, उणरै नैरन्तर्य अर उण नैरन्तर्य में घटित होवतै बदळाव री अणदेखी नीं करै। इण वास्तै जद अपां लोक साहित्य या लोक कला री बात करां, तौ वा कोई अतीत री कला या अतीत रौ साहित्य नीं होवै, वो हमेसा 'अपारै' बगत री अभिव्यक्ति होवै। वो कोरी जूनी बातां रा बखांण नीं करै, बल्कि वो आपरै कलेवर में जका जीवण मूल्यां रौ उजास लियां ऊभौ दीखै वे आज भी अपांनै अर अपारै समाज रै चरित् नै घड़ण रौ काम करै। इण लोक साहित्य रै पांण राजस्थानी समाज आज भी आपरी धड़कण में वां गुणां री ऊर्जा नै अर वां जीवण मूल्यां री गूंज नै मैसूस करै है।

स्रिस्टी रै बणियां पछै, आपरी ग्यांनेन्द्रियां री सगती रै पांण मिनख स्रिस्टी में घटित होवण वाळी हर घटना नै ओळखण लागौ। इण ओळख नै थिर राखण सारूं वो वां चीजां नै नाम दिया, वो वांरौ रूप याद राखण लागौ। इणी 'लोक दीठ' रै पंसाव अपां आज नाम अर रूप वाळी इण दुनिया नै जांणां हां। नाम अर रूप री सिरजणा रा केई जूना सबद अपांरी स्मृति सूं अलोप होय गिया है। अपांरौ लोक साहित्य अैड़ा सबदां रौ भण्डार अपारै सांम्ही खोलै, जिणरै चांनणै में अपां अपांरी गमियोड़ी दुनिया नै पाछी ओळखण लागां। राजस्थानी लोक कथावां, लोक गीत, लोक गाथावां, लोक नाट्य, पहेलियां, मुहावरा अर कैवतां राजस्थानी संस्कृति री हेमांणी है। आ विरासत लोक साहित्य री ओप बधावै। उणरै उजास में सरूप धारण करती राजस्थानी संस्कृति री छबि माथै अपां आज अंजस करां हां।

पण विडम्बना आ है कै औपनिवेसिक सिक्सा रै कारण अपां अपांरी ग्यांन परम्परा रा घणा सबदां नै अंगरेजी सबदां रै माध्यम सूं समझण री आफळ करां। अपां परम्परा नै ट्रैडिसन सूं, धरम नै रिलिजन सूं अर संस्कृति नै कल्चर सूं समझणी चावां हां। इण कारण सू आं सबदां रा मूळ अरथ अपां सूं छूट गिया है, इण कारण अपां अपांरी परम्परा, धरम अर संस्कृति रा आधा अधूरा अरथ करां। क्यूं कै लारलै दो सौ बरसां सूं अपांरी पीढियां री भणाई अंगरेजां रै बतायोडै मारग चाल पूरी होई है। इण सारूं आज इक्कीसवें सईकै में उभै मिनख सारूं, अैड़ा महताऊ सबदां री जड़ां तांई पूगणौ घणौ मुश्किल होय गियौ है। उणी मारग चालता अपां 'लोक' नै 'फोक' की चिलक में जांणणी चावां अर साहित्य नै लिटरेचर में सोधण लागां। पास्चात्य संस्कृति 'फोक' रौ अरथ करै अणपढ़, असभ्य, गंवार अर उणी 'दीठ' नै साच मानता अपांरा विद्वान भी औ कैय देवै कै लोक रै व्यावहारिक ग्यांन रौ आधार पोथियां नीं है। वां विद्वानां नै स्यात् ध्यांन भी नीं होवैला कै जिणनै भारतीय ग्यांन परम्परा 'लोक' कैय सैं सूं बत्तौ सनमांन दियौ है उण लोक रौ आपरौ अेक 'सास्तर' भी है। इण सास्तर री चरचा महाभारत रै शांति पर्व में भीसम पितामह राजा युधिस्ठर सूं करै है-

ये हि ते ऋषयः ख्याताः सप्तचित्रशिखण्डिनीः ।।27।।
तैरेकमतिभिर्भूत्वा यत् प्रोक्तं शास्त्रमुत्तमम्।
वैदेश्चतुर्भिः समितं कृतं मेरौ महागिरौ ।।28।।
आस्यैः सप्तभीरुदीर्णं लोकधर्ममनुत्तमम् ।
मरीचित्यांगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।
वशिष्ठश्च महातेजास्ते हि चित्रशिखण्डिनीः ।।29।।

(महाभारत-शांतिपर्व-अध्याय-335)

भीसम युधिस्ठर सूं कैय रैया है कै मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु अर वसिस्ठ- अै सात प्रसिद्ध रिसी चित्र सिखण्डी बाजै है। चित्र सिखण्डी नाम सूं विख्यात अै सातूं रिसी महागिरी मेरू परबत माथै भेळा होया अर अेकमत होय जिण उत्तम सास्तर रौ निरमांण अर प्रवचन करियौ, वो चारूं वेदां जित्तौ ई आदरजोगो अर प्रमाणभूत है। उण में सात मूंडां सूं परगट होयोड़ै उत्तम 'लोक धरम' री व्याख्या होई है।

महाभारत बतावै कै अै सातूं रिसी प्रकृति रा सात रूप है अरथात् परजा रा स्रस्टा है। आठवां ब्रह्मा है। अै सगळा मिळनै इण सम्पूरण लोक नै धारण करै। आं रै द्वारा इज सास्तर रौ प्राकट्य होयौ है। अै तपस्वी ग्यांनी सबद, अरथ और हेतु सूं युक्त वाणी रौ प्रयोग करियौ। वा आंरी 'प्रथम' रचना ही-

तत प्रवर्तिता सम्यक् तपोविद्धि र्द्विजातिभिः।
शब्दे चार्थे च हेतौ च एषा प्रथम सर्गजा ।।36।।

महाभारत बतावै कै औ सास्तर प्रवृत्ति अर निवृत्ति रै विसय में ऋक्, यजुः, साम अर अथर्व वेद रै मन्तरां सूं अनुमोदित ग्रंथ दांई प्रमाण मानीजैला। खुद भगवान पुरुसोत्तम इण उत्तम सास्तर नै प्रामाणिक मानण री आग्या दीनी अर कैयौ कै औ सास्तर सगळा सास्तरां सूं श्रेस्ठ मानीजैला। औ धरम सास्तर, अरथ सास्तर अर उत्तम रहस्यमय ग्रंथ है। भगवान री आग्या री पालना में ई वे परजापति धरम रै मूळभूत उण सनातन सास्तर रौ जगत में प्रचार करियौ-

ततस्ते लोकपितरः सर्वलोकार्थचिन्तकाः।
प्रावर्तयन्त तच्छास्त्रं धर्मयोनिं सनातनम् ।।53।।

(महाभारत शांति पर्व - अध्याय 335)

महाभारत द्वापर जुग रौ ग्रंथ है अर उणमें वरणित अै सातूं रिसी स्रिस्टी बणण री प्रक्रिया में उत्पन्न होयोड़ा ब्रह्मा रा मानसपुत्र है। आं रिसियां नै इज 'पितर' कैयौ गियौ है। जिण मैथूनी स्रिस्टी रौ रूप आज अपारै सांम्ही, वा स्रिस्टी आं री सिरजणा रै पछै बणी है। इण वास्तै कैय सकां कै 'लोक सास्तर' इण स्रिस्टी रौ आदूसास्तर है बाकि सगळा सास्तर इणरै पछै री रचनावां है। इण लोक सास्तर सूं उपजियोडी दीठ इज लोक री दीठ बणी अर वा लोक दीठ इज लोक साहित्य नै आधार दियौ। आज अपां अपांरी नासमझी में लोक साहित्य नै अणपढ लोगां रौ साहित्य मांन उणरै प्रति हेय भावना राखां हां क्यूं कै अपां जांणां ई नीं हां कै उण साहित्य रा बीज तो भारतीय ग्यांन परम्परा रा सिरमौर सप्त-रिसियां रा बीजियोड़ा है।

अंगरेजी सिक्सा सूं मिळियोड़ी आथूणी दीठ नै अंगेजण रै कारण अपां अपांरी समृद्ध ग्यांन परम्परा नै भूलियोडा बैठा हां। इण रै कारण इज अपां लोक री हेमांणी- लोक साहित्य नै अर लोक कलावां नै वो मांन नीं देवां जिण री वे हकदार है। लोक साहित्य री सहजता अर सरलता इज उणरी कमजोरी मांनीजी। लोक धरम री जिण जोत नै वे सप्तरिसी चेतन कर लोक नै सूंपी ही, उणरै सरूप री ओळख साहित्य अर कला रै आदू सास्तर 'नाट्य सास्तर' रै कारण सांम्ही आई। ढाई हजार बरस जूनै इण सास्तर में 'नाट्य' री चरचा करीजी है। इणमें नाट्य रै 'लोकधरमी' रूप री ओळखांण कीकर करणी चाइजै इणरौ बरणन है। नाट्य सास्तर कैवै है कै-

स्वभावोपगतं शुद्धन्त्वविकृतं तथा।
लोकवार्ताक्रियोपेतमंगलीलाविवर्जितम् ।।69।।
स्वभावाभिनयोपेतं नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्।
यदीदृशं भवेन्नाटयं लोकधर्मी तु सा स्मृता ।।70।।

(नाट्यशास्त्र, अध्याय-14)

अरथात् जे कोई रूपक लोक स्वभाव रै अनुसार भावप्रदर्शित करण वाळौ, सादगी अर बिना बाहरी दिखावट वाळौ होवै, जकौ आपरी कथावस्तु में सामान्य प्रजाजन रा आचार अर क्रियावां प्रदर्सित तथा आंगिक प्रदर्सण जकौ लीलाभिनय सूं रहित सादौ अर सहज भाव रौ प्रदर्सण करै अर जिणमें भिन्न-भिन्न स्त्री अर पुरुस पात्र होवै, उणनै लोक धरमी नाट्य प्रकार समझणौ चाइजै।

क्यूं कै नाट्य सास्तर नाट्य रौ आदू ग्रंथ है। नाटक श्रव्य-द्रस्य काव्य मांनीजियौ है। नाटक रै सास्तरीय रूप सूं इतर लोक धरमी रूप भविस री न्यारी न्यारी भासावां रै लोक साहित्य रूप रा पग मंडणा कर दिया। किणी भी भासा रै लोक साहित्य रै सरूप रै निर्धारण में इण लोक धरमी दीठ री रंगत अपांनै देखण नै मिलै है। लोक रै सभाव री हिमायत करती आ दीठ साहित्य अर कला में बारलै दिखावै नै आछौ नीं मांनै। सादगी, सरलता अर सहजता इज जिण साहित्य में परजा रै आचरण रौ आधार बणै उठै इज लोक साहित्य आपरौ झण्डौ गाडियोड़ौ ऊभौ दीखै। ■

पोषण पखवाड़े में राजस्थान प्रथम

गजाधर भरत, सहायक निदेशक

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों का परचम लहराया है। वर्ष 2026 के अप्रैल माह में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आयोजित 'अष्टम पोषण पखवाड़ा' में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है, जो राज्य में पोषण स्थिति में निरंतर सुधार के लिए राज्य सरकार के सतत प्रयासों को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में आयोजित 'सप्तम पोषण पखवाड़ा' में भी राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था।

सर्वाधिक गतिविधियों का आयोजन

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'अष्टम पोषण पखवाड़ा' (9 से 23 अप्रैल 2026) में राजस्थान ने सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अभियान के तहत राज्य के 41 जिलों के 62,139 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुल 45,37,229 गतिविधियां संपन्न हुईं, जो प्रदेश की व्यापक भागीदारी और अभूतपूर्व सक्रियता को दर्शाती हैं।

जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास

बच्चों के जीवन के पहले 6 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस उम्र में यदि समुचित पोषण मिलता है, तो वह बच्चा स्वस्थ, तंदुरूस्त रहेगा और आने वाले समय में देश की ताकत बनेगा। भारत सरकार ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष पोषण पखवाड़े की मुख्य थीम 'जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास' हैं।

अभियान की दिन वार उपलब्धियां

अभियान की शुरुआत से ही राजस्थान डैशबोर्ड पर शीर्ष पर बना रहा।

- पहला दिन (9 अप्रैल)- रैली, नारा लेखन, जागरूकता गतिविधियां, पोषण एवं अम्मा कार्यक्रम पर चर्चा तथा स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुए। पहले दिन ही 2.17 लाख गतिविधियां दर्ज कर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- दूसरा दिन (10 अप्रैल)- पोषण व्यंजन प्रदर्शन, जंक फूड के खिलाफ जागरूकता और खाना बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- तीसरा एवं चौथा दिन (11–12 अप्रैल)- विकासात्मक माइलस्टोन पहचान और नवचेतना मार्गदर्शिका आधारित गतिविधियां हुईं।
- पांचवां दिन (13 अप्रैल)- स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) जागरूकता सत्र आयोजित हुए।
- छठा दिन (14 अप्रैल)- मां-बच्चे की अंतःक्रिया, भाषा व कहानी सत्र और खेल आधारित शिक्षा पर गतिविधियां हुईं।
- सातवां दिन (15 अप्रैल)- पुरुष अभिभावकों की भागीदारी और डीआईवाई खिलौना निर्माण गतिविधियां आयोजित हुईं।
- आठवां दिन (16 अप्रैल)- खेल, नृत्य व योग गतिविधियां।
- नौवां दिन (17 अप्रैल)- स्क्रीन टाइम कम करने में माता-पिता की भूमिका पर सुरक्षित डिजिटल आदतों के संदेश प्रसारित किए गए।
- दसवां दिन (18 अप्रैल)- 'नो स्क्रीन आवर' और 'फैमिली प्ले टाइम' गतिविधियां।
- ग्यारहवां एवं बारहवां दिन (19–20 अप्रैल)- सामुदायिक समर्थन पर फोकस रहा, पंखुड़ी पोर्टल की जानकारी दी गई और भामाशाहों व समुदाय को आंगनबाड़ी सहयोग के लिए प्रेरित किया गया।
- तेरहवां दिन (21 अप्रैल)- दान अभियान, पोषण मेला और खिलौने/शिक्षण सामग्री जुटाने के लिए जनभागीदारी गतिविधियां आयोजित हुईं।
- चौदहवां दिन (22 अप्रैल)- सोशल मीडिया और आईईसी अभियान के माध्यम से आंगनबाड़ी सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाई गई।
- पंद्रहवां दिन (23 अप्रैल)-क्विज, पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन और डिजिटल जुड़ाव गतिविधियों के साथ अभियान का समापन हुआ। ■

अंधकार से आलोक तक

स्वामी ब्रह्मदेव का सेवा- संकल्प और श्री जगदंबा अंधविद्यालय की प्रेरणादायी गाथा

जब सेवा तपस्या बन जाए और संकल्प जीवन का ध्येय, तब इतिहास रचा जाता है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर हनुमानगढ़ रोड स्थित श्री जगदंबा अंधविद्यालय की कहानी इसी अदम्य इच्छाशक्ति, करुणा और समर्पण की गाथा है। यह हजारों दृष्टिबाधित, मूक-बधिर और जरूरतमंद लोगों के जीवन में उजाला भरने वाला एक प्रकाश-स्तंभ है। इस विराट सेवा यात्रा के प्रेरणास्रोत हैं स्वामी ब्रह्मदेव, जिनका जीवन समाज के वंचित वर्ग को सम्मान और आत्मनिर्भरता दिलाने के लिए समर्पित रहा है।

अनिल शाक्य, जनसम्पर्क अधिकारी

प्रेरणा से प्रारंभ हुआ सेवा का महायज्ञ

वर्ष 1963 में अमृतसर के श्री दुर्ग्याणा मंदिर स्थित अंधविद्यालय को देखकर स्वामी ब्रह्मदेव के मन में एक विचार आया। दृष्टिबाधित बच्चों की स्थिति ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि यदि इन बच्चों को सही दिशा, शिक्षा और अवसर मिलें, तो वे भी समाज की मुख्यधारा में अपनी पहचान बना सकते हैं। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वे श्रीगंगानगर आए और 13 दिसंबर, 1980 को श्री जगदंबा अंधविद्यालय की स्थापना की। प्रारंभिक दिनों में विद्यालय में केवल एक शिक्षक और एक विद्यार्थी था। संसाधन सीमित थे, पर संकल्प असीम था। कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू हुई और धीरे-धीरे यह प्रयास एक जनआंदोलन में परिवर्तित हो गया।

संघर्ष से सफलता तक का विस्तार

निरंतर प्रयासों से विद्यालय को 10वीं कक्षा तक क्रमोन्नत किया गया। वर्ष 1986-87 के बीच विद्यालय ने अभूतपूर्व प्रगति की। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई। बढ़ती संख्या को देखते हुए परिसर में तीन छात्रावासों का निर्माण किया गया, ताकि दूर-दराज से आने वाले बच्चों को रहने की सुविधा मिल सके। विद्यालय ने शिक्षा के स्तर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए स्वीडन से 20 लाख रुपये की लागत वाला आधुनिक ब्रेल लिपि सिस्टम मंगवाया। उस समय यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयास था। इससे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सकी और उनकी शिक्षा अधिक प्रभावी बनी।

मूक-बधिर बच्चों के लिए विशेष पहल

स्वामी ब्रह्मदेव का दृष्टिकोण समावेशी था। उन्होंने केवल दृष्टिबाधित बच्चों तक ही अपनी सेवा सीमित नहीं रखी, बल्कि मूक एवं बधिर बच्चों के लिए भी विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए। सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज), स्पीच थेरेपी, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि कोई भी बच्चा केवल शारीरिक अक्षमता के कारण अवसरों से वंचित न रहे। आज अनेक मूक-बधिर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर स्वरोजगार या नौकरी के माध्यम से सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक सेवा

शिक्षा के साथ-साथ स्वामी ब्रह्मदेव ने नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नि:शुल्क नेत्र शिविरों का आयोजन नियमित रूप से किया गया। पिछले तीन दशकों में उनके प्रयासों से जरूरतमंदों के साढ़े पांच लाख से अधिक नेत्र ऑपरेशन किए जा चुके हैं। विशेष रूप से सफेद मोतियाबिंद के नि:शुल्क ऑपरेशन कर लाखों लोगों को नई दृष्टि प्रदान की गई। इन शिविरों में जांच, ऑपरेशन, दवाइयां और बाद की देखभाल की संपूर्ण व्यवस्था की जाती रही है। कई बुजुर्गों ने वर्षों बाद अपने बच्चों और पोते-पोतियों का चेहरा स्पष्ट देखा। कई परिवारों की आजीविका फिर से शुरू हुई। यह सेवा केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि जीवन को पुनः प्रकाश देने का प्रयास थी।

"सामाजिक सेवा के क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भपंग वादक श्री गफरूद्दीन मेवाती जोगी जी, अलगोजा वादक श्री तगा राम भील जी को पद्मश्री सम्मान की घोषणा ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। आपकी साधना, समर्पण और लोक संस्कृति के संरक्षण के प्रति आपका सेवाभाव हम सभी के लिए प्रेरणा का पुंज है। यह सम्मान आपके उत्कृष्ट कार्यों और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का प्रमाण है।"

श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

दानवीरों और समाज का अभूतपूर्व सहयोग

श्री जगदंबा अंधविद्यालय की इस महान यात्रा में श्रीगंगानगर सहित देशभर के दानवीरों, समाजसेवियों और उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थानीय व्यापारियों, कृषकों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं ने समय-समय पर आर्थिक सहायता, भवन निर्माण, छात्रावास विस्तार, भोजन व्यवस्था और चिकित्सा शिविरों के आयोजन में सहयोग दिया। कई परिवारों ने अपने परिजनों की स्मृति में कक्षाएं, छात्रावास कक्ष और उपकरण दान किए।

समाज की मुख्यधारा से जुड़ते सपने

विद्यालय ने हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाया। अनेक पूर्व विद्यार्थी आज सरकारी सेवाओं, निजी संस्थानों और स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्यरत हैं। कुछ ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में उल्लेखनीय स्थान बनाया है। समय के साथ पड़ोसी राज्यों में भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विद्यालय खुलने लगे। ऐसे में दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों को उनके घर के निकट स्थित संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि वे परिवार के पास रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह निर्णय भी बच्चों के हित को सर्वोपरि रखने की भावना का प्रतीक था। ■

प्रकृति और सदियों पुरानी इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम

बूंदी जिले का गुढ़ा बांध

अनुप्रिया, जनसंपर्क अधिकारी

बूंदी जिले का गुढ़ा बांध ऐतिहासिक जल-संरक्षण परंपरा और प्रकृति के अनूठे तालमेल का जीवंत उदाहरण है। गुढ़ा बांध की वास्तुकला आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। बांध की पाल पूरी तरह मिट्टी की बनी हुई है और इसकी लंबाई लगभग 2407 मीटर है। बिना आधुनिक मशीनों के सदियों पहले तैयार किया गया, यह बांध तत्कालीन इंजीनियरिंग कौशल और दूरदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

जलस्रोत और क्षेत्रफल

गुढ़ा बांध 1859 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी जलधारण क्षमता 95.56 मिलियन क्यूबिक मीटर है। यह विशाल जलस्रोत केवल इंसानों की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सिंचाई और कृषि में योगदान

बांध की नहरों के माध्यम से लगभग 11,380 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। इस जल के माध्यम से बूंदी जिले के कई हिस्सों में खेतों की हरियाली बनी रहती है और किसानों की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होती है।

गुढ़ा बांध न केवल बूंदी जिले का जलस्रोत है, बल्कि यह सदियों पुरानी इंजीनियरिंग, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय जीवन के बीच का अद्भुत संगम भी है। यह बांध आज भी अपने ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के कारण लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। ■

भीड़-भाड़ सूं दूर सुकून अर मौज
ब्यावर रो खास ठिकाणो

सतीश सोनी, जनसम्पर्क अधिकारी

ब्यावर केवल एक ऐतिहासिक नगर ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू-विरासत स्थल भी है, जो करोड़ों वर्षों के भूगर्भीय विकास और समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर को अपने भीतर समेटे हुए है। राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर सेन्दड़ा के समीप स्थित ग्रेनाइट भूवैज्ञानिक स्मारक मार्ग के दोनों ओर आकर्षक एवं दर्शनीय रूप में दिखाई देता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1977 में इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल घोषित किया गया था। यह स्मारक प्रकृति की अद्भुत शिल्पकारी और उसकी सृजनात्मक क्षमता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित सेन्दड़ा का ग्रेनाइट क्षेत्र अपनी अद्वितीय प्राकृतिक संरचना एवं विशिष्ट भू-आकृतियों के लिए विशेष पहचान रखता है।

राजस्थान की पहली कपड़ा मिल तथा प्रमुख ऊन मंडी के रूप में ब्यावर का औद्योगिक महत्व भी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय रहा है, जिसके कारण यह प्रदेश की महत्वपूर्ण विरासत स्थलों में शामिल होता है। वहीं, सेन्दड़ा क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राचीन प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें इस क्षेत्र को वैज्ञानिक एवं भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं, जो पृथ्वी के प्राचीन भू-इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं।

रोमांच और एडवेंचर ट्रैकिंग का अनुभव

सेन्दड़ा क्षेत्र केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि साहसिक गतिविधियों के लिए भी उपयुक्त है। ऊबड़-खाबड़ रास्ते और पहाड़ी चढ़ाई इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, किंतु यही विशेषता इसे एक उत्कृष्ट एडवेंचर ट्रैकिंग अनुभव में परिवर्तित करती है। यहां आने वाले पर्यटक प्रकृति की मूल, अप्रदूषित सुंदरता का अनुभव करते हैं, जो उन्हें शहरी जीवन की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और एकांत वातावरण प्रदान करता है। इसलिए इसे एक 'ऑफ बीट डेस्टिनेशन' के रूप में देखा जा सकता है।

सौन्दर्य ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी

यह भू-विरासत स्थल केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा वैज्ञानिक मूल्य भी है। यहां की चट्टानें पृथ्वी के प्रारंभिक भूगर्भीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करती हैं। ये संरचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि किस प्रकार पृथ्वी के भीतर स्थित मैग्मा धीरे-धीरे ठंडा होकर ठोस चट्टानों में परिवर्तित हुआ। यह प्रक्रिया लाखों-करोड़ों वर्षों में हुए भूगर्भीय परिवर्तनों का जीवंत साक्ष्य है।

प्रकृति की अनूठी कलात्मकता

सेन्दड़ा स्थल की प्रमुख विशेषता इसका अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है। समय के साथ हवा और जल के अपरदन (कटाव) के कारण इन चट्टानों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उभर आई हैं, जो कहीं शेर, कहीं उल्लू और अन्य जीव-जंतुओं जैसी प्रतीत होती हैं। यह दृश्य प्रकृति की कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसे 'नेचर स्कल्पचर' भी कहा जा सकता है। यह स्थान फोटोग्राफी और प्रकृति अवलोकन के लिए अत्यंत आकर्षक है।

प्रशासनिक प्रयास और संरक्षण

जिला प्रशासन ब्यावर द्वारा सेन्दड़ा स्थल को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की पहल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर यहां विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने प्राकृतिक वातावरण में योगाभ्यास कर इस स्थल की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। साथ ही, इस अमूल्य भू-धरोहर को अवैध खनन व माफियाओं की नजर से बचाने के लिए प्रशासन और स्थानीय स्तर पर निगरानी, जनजागरूकता और सख्त कार्रवाई जैसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, ताकि इसकी प्राकृतिक विरासत सुरक्षित बनी रहे। ■

धोरों की शांत वादियों में बसा आस्था और श्रद्धा का पावन केन्द्र

श्याम पांडिया मंदिर

मनीष कुमार, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी
छाया - **मुकेश दाधीच**

राजस्थान की धार्मिक परंपराओं में ऐसे अनेक तीर्थस्थल हैं, जहां लोकविश्वास, पौराणिक कथाएं और जनआस्था एक साथ मिलकर आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इसी दिव्य आस्था का सजीव प्रतीक है श्याम पांडिया मंदिर, जो चूरू जिले के तारानगर उपखंड मुख्यालय के निकट नेठवा ग्राम पंचायत के कैलाश गांव में धोरों के मध्य स्थित है। यह पवित्र धाम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत पौराणिक मान्यताओं और ऐतिहासिक कथाओं के कारण भी विशेष महत्व रखता है। महाभारत काल से जुड़ी लोककथाएं तथा जनश्रुतियां इस स्थल को क्षेत्रीय आस्था और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र बनाती हैं।

धार्मिक आस्था एवं महाभारत कालीन सांस्कृतिक संबंध

यह मंदिर स्थानीय निवासी श्याम पांडिया की स्मृति और सम्मान में स्थापित माना जाता है। उनका गोत्र पांडिया था तथा वे अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक शक्तियों और तपस्या के कारण क्षेत्र में अत्यंत पूजनीय माने जाते थे। यह धार्मिक स्थल प्राचीन द्वापर युग से जुड़ी लोकमान्यताओं के कारण क्षेत्रीय आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मंदिर का संबंध महाभारत काल के महान तपस्वी श्याम पांडिया से माना जाता है। प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार, महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव कुरुक्षेत्र में यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, किंतु उनके सभी प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। उसी दौरान उन्हें साधु पुरुष श्याम पांडिया के चमत्कारिक व्यक्तित्व और सिद्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई।

एकात्मक सांस्कृतिक केंद्र एवं वार्षिक भाद्रपद मेला

मंदिर परिसर में भगवान शिव, हनुमानजी एवं श्याम पांडिया के मंदिर स्थित हैं, जहां पारंपरिक धूणा और श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्नान कुण्ड भी बने हुए हैं। यहां आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों और मेलों में स्थानीय संस्कृति एवं ग्रामीण परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद अमावस्या पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश-विदेश से श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। मेला अमावस्या की पूर्व संध्या पर जागरण से प्रारंभ होकर पूजा, स्नान एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होता है। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता का भी प्रतीक है।

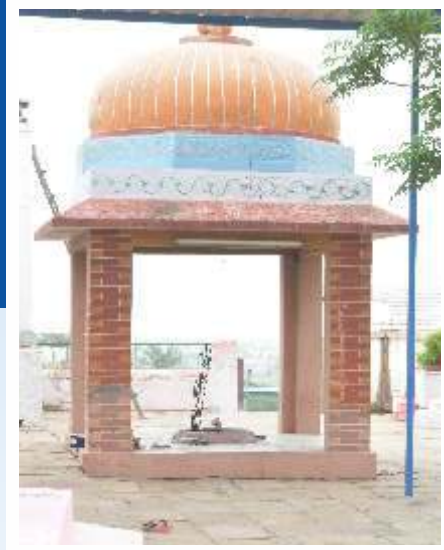

कथा के अनुसार, पांडवों में से भीम श्याम पांडिया से मिलने उनके आश्रम पहुंचे और उनसे यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का आग्रह किया। प्रारंभ में साधारण वेशभूषा और सामान्य कद-काठी में श्याम पांडिया को देखकर भीम उनके दिव्य व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सके। किंतु जब श्याम पांडिया ने अपनी धोती हवा में उछाली, जो बिना किसी सहारे के स्वयं सूखकर व्यवस्थित रूप से सिकुड़ गई, तब वे उनकी साधना, सिद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों से अत्यंत प्रभावित हुए तथा उन्हें एक महान संत के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात श्याम पांडिया भीम के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उनके मार्गदर्शन में यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस घटना के बाद पांडवों ने उन्हें विलक्षण आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न तपस्वी मानते हुए अत्यंत सम्मान प्रदान किया।

बावड़ी का निर्माण

यज्ञ संपन्न होने के पश्चात पांडव निकटवर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र 'बांय' पहुंचे, जहां पानी की अत्यंत कमी थी। स्थानीय ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाने के लिए विवश होना पड़ता था। जनश्रुतियों के अनुसार पानी की समस्या के समाधान हेतु भीम ने बावड़ी का निर्माण करवाया। यह बावड़ी आज भी उसी स्थल पर विद्यमान है, जिसके ऊपर पारंपरिक शैली में मंदिर स्थापित किया गया है।

वर्तमान समय में स्थानीय जनसहयोग से श्याम पांडिया एवं खाटू श्यामजी मंदिर को समर्पित एक भव्य मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। मंदिर के पुरोहितों के अनुसार, इस बावड़ी का जल कभी समाप्त नहीं होता तथा इसके जलस्रोत का आज तक कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।

जनमान्यता है कि यह जल दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो वर्षभर निरंतर उपलब्ध रहता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस बावड़ी में आज तक किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है।

भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टि से विशिष्ट एवं सौंदर्यपूर्ण क्षेत्र

यह मंदिर चूरू जिले के तारानगर कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर दूर नेठवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्थित है। मंदिर के चारों ओर 141.31 हेक्टेयर अधिसूचित वन भूमि फैली हुई है, जो इसे धार्मिक के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी विशेष बनाती है। लगभग 300 फीट ऊंचे टीले पर स्थित इस मंदिर परिसर के आसपास केर, खेजड़ी, बबूल, नीम, शीशम और कनेर सहित अनेक वन्य प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। ऊंचाई और रेतीली मिट्टी के कारण यहां का तापमान आसपास के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। वन क्षेत्र होने से यहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी निवास करते हैं, जो इस स्थल की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं।

पर्यटन मानचित्र पर उभरता श्याम पांडिया मंदिर

श्याम पांडिया मंदिर अपनी विशिष्ट पहचान के साथ पर्यटन मानचित्र पर धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभर रहा है। प्रतिवर्ष आयोजित मेले में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय क्षेत्र के विकास को भी व्यापक प्रोत्साहन मिल रहा है। श्याम पांडिया धाम परिसर के आसपास विस्तृत वन भूमि संरक्षित है, जिसमें लोमड़ी, हरिण, नीलगाय, जंगली बिल्ली, गिरगिट, पाटागोह, दुमई, विभिन्न प्रकार के सर्प, गोयरा, खरगोश, बाज तथा चिड़िया, कबूतर, कौवा और कोयल जैसे अनेक पक्षी स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां तितलियों की भी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं।

पर्यटकों की सुविधाओं और आकर्षण को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा 'लव-कुश वाटिका' का विकास किया जा रहा है। इस वाटिका में अनेक संरचनात्मक एवं सौंदर्यीकरण कार्य संपन्न किए गए हैं, जिनमें पुल एवं दर्शनीय स्थल, जोहड़ की मरम्मत, रेलिंग निर्माण, टिकट काउंटर, मंदिर तक सीढ़ियों का निर्माण, तालाब एवं चेकडैम निर्माण, वृक्ष संरक्षण हेतु गट्टा निर्माण, ईको ट्रेल, गज़िबो हट, प्रवेश द्वार, कुंड, श्याम कुंड तक सीढ़ियां, मार्ग निर्माण, अमृत सरोवर तथा व्यापक वृक्षारोपण कार्य शामिल हैं। ■

भारत की ज्ञान विरासत का पुनरुद्धार

ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥

हिमांशु सिंह, जनसंपर्क अधिकारी

विद्या (ज्ञान) विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता (पात्रता) आती है, योग्यता से धन (समृद्धि) प्राप्त होता है, धन से धर्म (सत्कर्म) होता है और उससे सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान ही सुख का मूल है।

इसी ज्ञान को सुरक्षित और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने नाना प्रकार के यत्न किए। कभी वाचिक-मौखिक परंपराओं के द्वारा, तो कभी ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र, कागज, कपड़े इत्यादि पर उसी ज्ञान को सुरक्षित करने का निरंतर प्रयास भारतीय संस्कृति में किया गया। यही वजह रही कि हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का मूल तत्व 'वसुधैव कुटुंबकम्' तमाम विदेशी आक्रमण को झेलने के बाद भी अक्षुण्ण बना रहा है।

प्राचीन पांडुलिपियों से आधुनिक पीढ़ी तक ज्ञान का संचार

वर्तमान डिजिटल युग में, पिछले 50–70 वर्षों से प्रकाशित पुस्तकों और संदर्भ ग्रंथों तक युवा पीढ़ी की पहुंच डिजिटल माध्यमों के जरिए आसान हो गई है। अब एक क्लिक पर जानकारी का विशाल भंडार हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत विभिन्न विषयों के प्राचीन सूत्र, जो पांडुलिपियों के रूप में संरक्षित हैं, अब तक नई पीढ़ी की पहुंच से दूर थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि इन पांडुलिपियों में निहित अथाह ज्ञान का नई पीढ़ी तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। सदियों से सुरक्षित इस प्राचीन ज्ञान की रोशनी को आम जनता तक पहुंचाना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ज्ञान भारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण

भारत सदियों से ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और साहित्य की समृद्ध परंपरा का केंद्र रहा है। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित और साहित्य जैसी पांडुलिपियां देश की अमूल्य बौद्धिक विरासत हैं। समय के साथ यह धरोहर बिखर गई और कहीं-कहीं उपेक्षा के कारण नष्ट होने लगी। ऐसे में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'ज्ञान भारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' की शुरुआत एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम के रूप में की गई है।

अध्ययन के नए अवसर

16 मार्च 2026 को प्रारंभ किया गया यह सर्वेक्षण 'ज्ञान भारतम्' पहल का मुख्य हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देशभर की पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण और संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय पांडुलिपि मानचित्र तैयार होगा, जिससे पांडुलिपियों का व्यवस्थित संरक्षण संभव होगा और शोधार्थियों के लिए अध्ययन के नए अवसर खुलेंगे।

भारत की पांडुलिपि परंपरा और सर्वेक्षण की आवश्यकता

भारत की पांडुलिपि परंपरा विश्व की सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक है, जिसमें दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित और शासन जैसे विषयों पर लाखों पांडुलिपियां शामिल हैं। लेकिन इनका बड़ा हिस्सा अब तक औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हो पाया है। यह सर्वेक्षण इसी कमी को दूर करने का प्रयास है।

पांडुलिपि सर्वेक्षण की चार चरणीय प्रक्रिया

यह राष्ट्रीय अभियान चार प्रमुख चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पांडुलिपियों और उनके स्थान की पहचान की जाएगी, दूसरे चरण में विशेषज्ञों और राज्य अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा, तीसरे चरण में विस्तृत सूचीकरण और मेटाडेटा निर्माण होगा

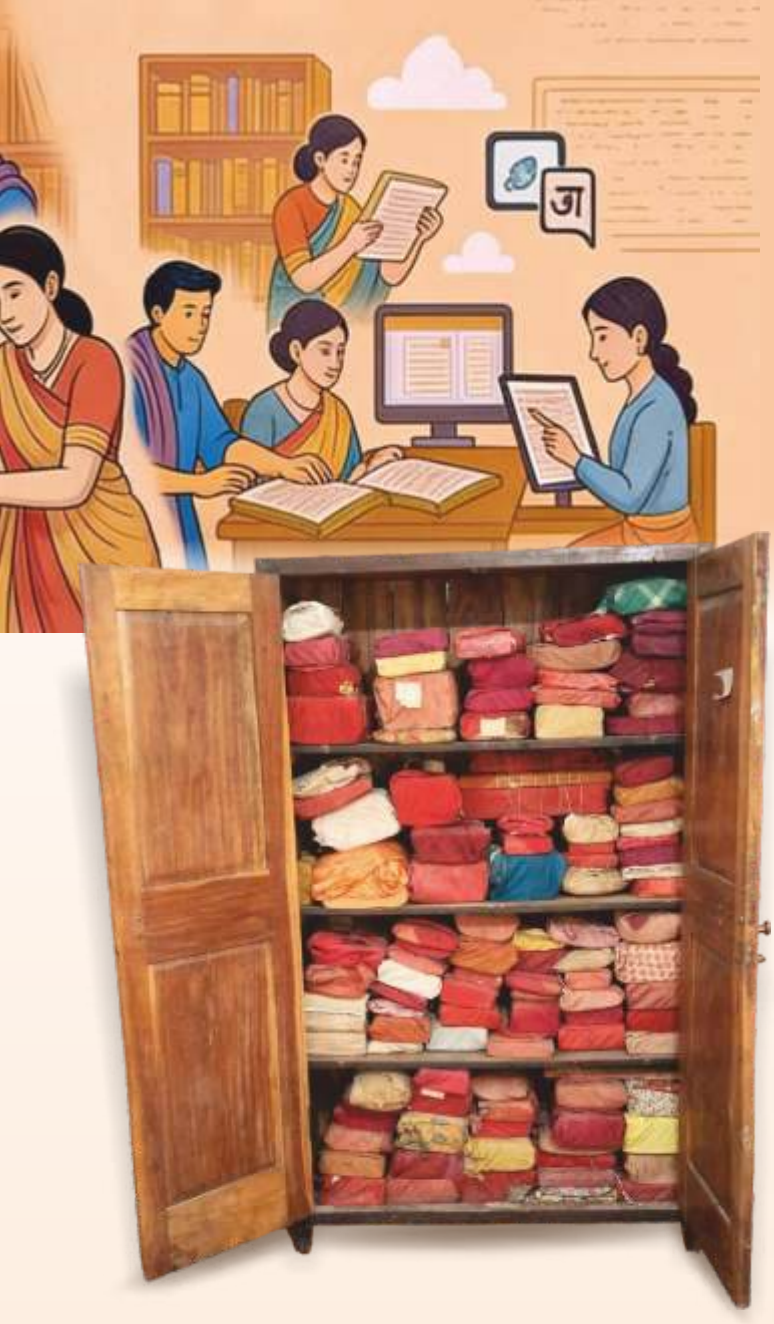

> “पांडुलिपियों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन अभिलेखों में निहित भारत की अमूल्य धरोहर हमारे ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान की गौरवशाली परंपरा को अभिव्यक्त करती है। इन्हीं अमूल्य स्रोतों से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी को भारत के समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक इतिहास से परिचित कराने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'ज्ञान भारतम् मिशन' की शुरुआत की गई है।
>
> **श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री**

और चौथे चरण में संरक्षण सहायता और उच्च-गुणवत्ता डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह संरचना पांडुलिपियों की पहचान से लेकर उनके संरक्षण और डिजिटल रूपांतरण तक पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है।

जनभागीदारी और सुरक्षित डिजिटलीकरण

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता जनभागीदारी आधारित संरचना है। 'ज्ञान भारतम्' मोबाइल एप और वेबसाइट के माध्यम से नागरिक, विद्वान, संस्थान और पांडुलिपियों के संरक्षक आसानी से जानकारी साझा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक और हस्तक्षेप रहित है, जिसमें पांडुलिपियों के स्वामित्व या स्थानांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन्हें 'जहां है, जैसी है' की अवस्था में संरक्षित कर डिजिटाइज किया जाएगा। वर्तमान में संचालित सर्वे के पहले चरण में केवल बुनियादी जानकारी जैसे स्थान, अनुमानित संख्या और संरक्षण की स्थिति दर्ज की जाती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

तकनीक और परंपरा का संगम

यह पहल केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीकों (विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास भी है। इस पहल को 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में यह बताया गया कि कैसे तकनीक और विरासत मिलकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 'ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक राष्ट्रीय अभियान है। यह पहल न केवल हमारी प्राचीन धरोहर को संरक्षित करेगी, बल्कि उसे डिजिटल माध्यम से वैश्विक मंच पर भी स्थापित करेगी।

राजस्थान में पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और सर्वेक्षण

झुंझुनूं के चिराणा में आयुर्वेद विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक डॉ. चंद्रकांत गौतम के पास 300 वर्ष पुराने ताड़ के पत्तों पर आयुर्वेद के अनेक सूत्र सुरक्षित हैं, जो आज भी उपचार में उपयोग होते हैं। डूंडलोद फोर्ट में रखी 108 पांडुलिपियों में घोड़े के इलाज सहित विभिन्न विषयों का विवरण है, जिन्हें डिजिटाइजेशन के बाद लोगों के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। प्रदेश में अब तक 15 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जो देशभर में सर्वाधिक है। ■

राजस्थान का डिजिटल सफर

पर्यटन अब एक क्लिक दूर

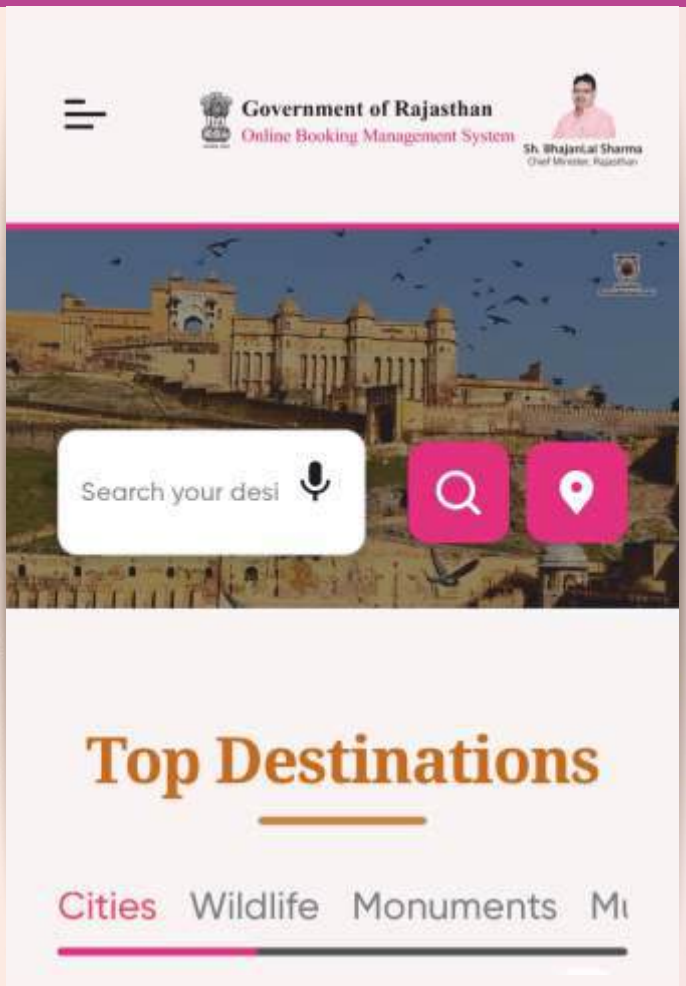

डॉ. आशीष खण्डेलवाल, उपनिदेशक

राजस्थान अब केवल महलों, किलों और रेगिस्तान का प्रदेश नहीं रहा, बल्कि यह डिजिटल नवाचार का नया गढ़ बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का नवाचार किया है। यह नवाचार है-OBMS (ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम), जो देश का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी-साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है।

आज कोई भी पर्यटक, चाहे वह भारत के किसी कोने से हो या विदेश से, obms-tourist.rajasthan.gov.in पोर्टल या OBMS मोबाइल ऐप के जरिए राजस्थान के किसी भी पर्यटन स्थल की पूरी जानकारी एक जगह पा सकता है और तुरंत टिकट बुक कर सकता है। 'पधारो म्हारे देस' का निमंत्रण अब पूरी तरह डिजिटल हो चुका है।

शानदार आंकड़े, अभूतपूर्व सफलता

इस व्यवस्था ने पर्यटन को नई ऊंचाई दी है। अब तक 90 लाख से अधिक टिकट बुकिंग हो चुकी हैं और 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक OBMS के माध्यम से राजस्थान घूम चुके हैं। इनमें 70 से अधिक देशों के विदेशी पर्यटक शामिल हैं। सिर्फ एक दिन में 28 दिसंबर, 2025 को लगभग एक लाख टिकट बुकिंग का

रिकॉर्ड बना। इस पहल से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को 30 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व भी मिला है। उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। वर्ष 2025 में OBMS को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड का सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया।

100 से अधिक स्थल एक प्लेटफॉर्म पर

वर्तमान में 100 से ज्यादा प्रमुख पर्यटन स्थल OBMS से जुड़ चुके हैं। इनमें आमेर किला, जंतर-मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल जैसे ऐतिहासिक स्मारक, सरिस्का और झालाना की वन्यजीव सफारी, कुम्भलगढ़-चित्तौड़गढ़ के किले, जवाहर कला केंद्र के कार्यक्रम और जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी जैसी विविध जगह शामिल हैं। पोर्टल पर पुरातत्व विभाग, वन विभाग, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के स्थल एक साथ उपलब्ध हैं। राज्य सरकार अब और आगे बढ़ रही है। जल्द ही आरटीडीसी के होटलों की बुकिंग और जवाहर कला केंद्र के कार्यक्रमों की टिकटिंग भी OBMS पर शुरू हो जाएगी। साथ ही, राजस्थान से बाहर एएसआई के 150 से अधिक पर्यटन स्थलों को भी इस प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय अनुभव

OBMS ने पर्यटन को पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस बना दिया है। क्यूआर कोड आधारित ई-टिकट, ऑडियो गाइड, एडवांस चेक-इन, इंटरएक्टिव मैप, स्मार्ट सर्च और रियल-टाइम डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं पर्यटकों के अनुभव को यादगार बनाती हैं। 'राजस्थान पैकेज' और 'जयपुर पैकेज' जैसे कंपोजिट पैकेज भी उपलब्ध हैं। साथ ही आसान कैंसिलेशन, त्वरित रिफंड और ऑनलाइन शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं यात्रा को परेशानी मुक्त बनाती हैं।

सकारात्मक बदलाव

इस डिजिटल पहल से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि मैनुअल कामों में भारी कमी आई है और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल रही है तो दूसरी ओर स्थानीय रोजगार बढ़ रहा है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विज़न और संकल्प से राजस्थान आज डिजिटल नवाचार और सुशासन दोनों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। OBMS सिर्फ एक टिकटिंग सिस्टम नहीं, बल्कि राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने वाला एक स्मार्ट और दूरदर्शी कदम है। ■

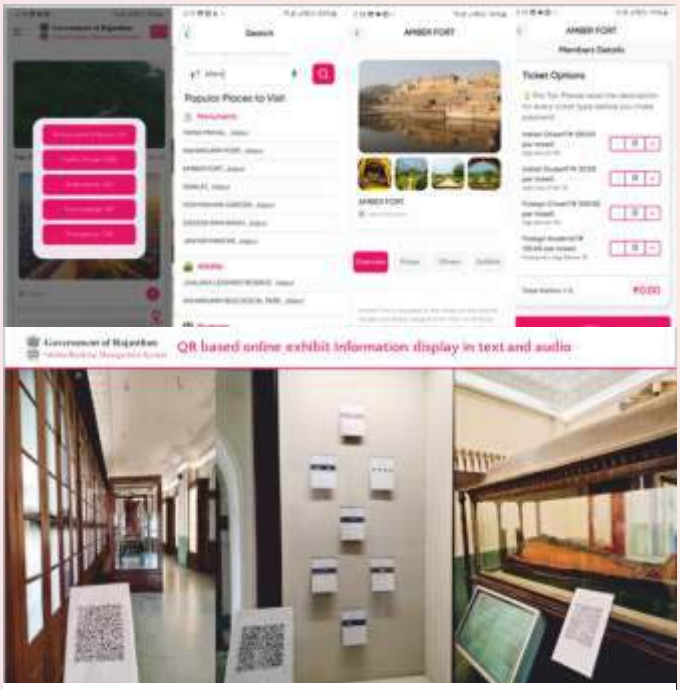

खेतों से उठ रही खुशहाली की हरित आभा

आधुनिक कृषि क्रांति से आत्मनिर्भर बनता किसान

भारतीय संस्कृति में किसान को सदा देवतुल्य माना गया है, क्योंकि वही अपनी तपस्या, श्रम और त्याग से समस्त मानव समाज के जीवन का आधार निर्मित करता है। कृषक केवल अन्न का उत्पादक नहीं, बल्कि राष्ट्र की समृद्धि, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मौन शिल्पकार होता है। उसके श्रम से ही खेतों में हरियाली आती है, अन्नागार भरते हैं और राष्ट्र की प्रगति का चक्र गतिमान रहता है। जो सरकार किसान के कल्याण को अपनी नीतियों के केंद्र में स्थापित करती है, वही वास्तविक अर्थों में लोककल्याणकारी शासन कहलाने की अधिकारी होती है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में किसानों को आधुनिक तकनीक, सशक्त सिंचाई संसाधन, उन्नत बीज, विभिन्न अनुदान योजनाएं तथा बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर एवं प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। यह केवल प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि किसानों के जीवन को सशक्त करते हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी प्रयास है।

प्रवेश परदेशी, जनसम्पर्क अधिकारी

कृषक उन्मुख नीतियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण

केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषक-उन्मुख नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे धरातल पर परिवर्तन की जीवंत गाथाएं बनकर उभर रही हैं। यही कारण है कि आज राजस्थान का किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों की सीमाओं को लांघते हुए आधुनिक तकनीकों से जुड़ रहा है और कृषि को केवल जीविकोपार्जन नहीं, बल्कि लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने अनेक कृषकों के जीवन में आर्थिक क्रांति का सूत्रपात किया है।

संघर्ष से समृद्धि तक की कहानी

राजसमंद जिले के आमेट उपखंड स्थित ग्राम सेलागुड़ा की कृषक हीरीदेवी एवं उनके पुत्र लहरीलाल कुमावत की यह प्रेरक कहानी आज कृषक समाज के लिए आशा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह परिवार पूर्व में

परंपरागत खेती पर निर्भर था, जहां बेमौसम वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं और जंगली जानवरों के कारण फसलों को भारी नुकसान होता था तथा सीमित संसाधनों के कारण वार्षिक आय लगभग 50 हजार से 1 लाख रुपये तक ही सीमित रहती थी। लगातार आर्थिक कठिनाइयों और बढ़ती खेती लागत के बीच यह परिवार संघर्ष कर रहा था, लेकिन सरकार की विभिन्न योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों ने उनके जीवन में आशा, आत्मविश्वास और समृद्धि का नया मार्ग प्रशस्त किया।

संरक्षित खेती के माध्यम से आय वृद्धि का मॉडल

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हीरीदेवी पत्नी छोगालाल कुमावत को दो आधुनिक पॉलीहाउस स्वीकृत हुए। प्रत्येक पॉलीहाउस का क्षेत्रफल 2016 वर्गमीटर है तथा एक पॉलीहाउस की कुल लागत 22 लाख 9 हजार 979 रुपये रही। इसमें कृषक द्वारा 5 लाख 5 हजार 451 रुपये का अंशदान किया गया, जबकि राज्य सरकार के उद्यान विभाग द्वारा लगभग 77 प्रतिशत अनुदान के रूप में 17 लाख 4 हजार 528 रुपये उपलब्ध कराए गए। दोनों पॉलीहाउस की संयुक्त लागत 44 लाख 19 हजार 958 रुपये रही। इसमें कृषक अंशदान 10 लाख 10 हजार 902 रुपये तथा विभागीय अनुदान 34 लाख 9 हजार 56 रुपये रहा।

पॉलीहाउस तकनीक में सरकारी सहयोग की भूमिका

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान ने हीरीदेवी के परिवार के लिए आर्थिक संबल का कार्य किया। यदि यह योजना उपलब्ध नहीं होती, तो लगभग 44 लाख रुपये की अत्याधुनिक पॉलीहाउस संरचना स्थापित करना एक सामान्य कृषक परिवार के लिए व्यावहारिक रूप से कठिन होता। किंतु राज्य सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से 34 लाख रुपये से अधिक का अनुदान प्रदान किए जाने से परिवार को कुल लागत का केवल लगभग 10 लाख रुपये ही स्वयं वहन करना पड़ा।

पॉलीहाउस स्थापना की कुल राशि का अधिकांश भार सरकार द्वारा वहन किए जाने से किसान परिवार को आर्थिक रूप से बड़ी राहत प्राप्त हुई। इस सहायता के माध्यम से न केवल लाखों रुपये की प्रत्यक्ष बचत हुई, बल्कि किसान परिवार बिना किसी भारी ऋण अथवा आर्थिक दबाव के आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़ सका। यही कारण है कि सीमित आय वाला यह परिवार आज उन्नत खेती के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। ये आंकड़े केवल आर्थिक निवेश का विवरण मात्र नहीं हैं, बल्कि यह उस दूरदर्शी शासन व्यवस्था का प्रतीक हैं, जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके साथ निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। राज्य सरकार की योजनाओं का यह मानवीय और संवेदनशील पक्ष आज ग्रामीण क्षेत्रों में नवविश्वास का संचार कर रहा है।

अब पूरे साल लेते फसल, कभी खीरा तो कभी टमाटर

हीरीदेवी और लहरीलाल कुमावत ने पॉलीहाउस स्थापना के पश्चात खीरा एवं टमाटर की उन्नत कृषि प्रारंभ की। नियंत्रित वातावरण में संचालित इस आधुनिक कृषि प्रणाली ने उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जहां खुले खेतों में मौसम की प्रतिकूलता, तापमान की अनिश्चितता और कीट-रोगों का संकट सदैव बना रहता है, वहीं पॉलीहाउस तकनीक ने खेती को वैज्ञानिक अनुशासन एवं स्थायित्व प्रदान किया है।

दो वर्षों में ही लागत वसूली, अब शुद्ध लाभ अर्जित

सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कुमावत परिवार ने मात्र दो वर्षों में पॉलीहाउस पर आई संपूर्ण लागत की वसूली कर ली तथा अब तक लगभग 10 लाख रुपये की शुद्ध आय अर्जित कर चुका है। यह उपलब्धि सामान्य नहीं है। यह परिश्रम, दूरदृष्टि और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसने एक सामान्य कृषक परिवार को आर्थिक सशक्तीकरण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है।

आज जब देश के अनेक हिस्सों में कृषि को संकटग्रस्त दृष्टि से देखा जाता है, तब राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से निकलती ऐसी प्रेरक कहानियां यह प्रमाणित करती हैं कि यदि कृषि में तकनीक, प्रशिक्षण और शासन का सहयोग सम्मिलित हो जाए, तो किसान की तकदीर वास्तव में बदल सकती है। यह परिवर्तन केवल आय वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण समाज में आत्मसम्मान, नवाचार और भविष्य के प्रति आशावाद भी विकसित हो रहा है।

पॉलीहाउस लगाकर उत्पादन बढ़ाएं किसान

पॉलीहाउस तकनीक आधुनिक कृषि विज्ञान का एक अभिनव स्वरूप है,

"आधुनिक तकनीक से राजस्थान का किसान सशक्त हो रहा है। अन्नदाता अब केवल मेहनत का प्रतीक नहीं, बल्कि नवाचार का नेतृत्वकर्ता बन चुका है। ड्रोन, स्मार्ट फार्मिंग और डिजिटल साधनों के साथ हमारे किसान नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।यह बदलाव खेती के साथ-साथ विकसित राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य को मजबूत कर रहा है।"

श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

जिसमें नियंत्रित वातावरण के माध्यम से फसल उत्पादन किया जाता है। इसमें तापमान, आर्द्रता एवं प्रकाश को वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित किया जाता है, जिससे प्रतिकूल मौसम में भी फसलें सुरक्षित रहती हैं और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन संभव हो पाता है। साथ ही यह तकनीक जल संरक्षण, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि जैसे अनेक लाभ किसानों को प्रदान करती है।

पॉलीहाउस केवल एक संरचना नहीं, बल्कि कृषि के भविष्य का एक सशक्त मॉडल है, जो परंपरागत खेती को वैज्ञानिक कृषि-उद्यम में परिवर्तित कर रहा है। इसके माध्यम से किसान वर्षभर सब्जियों एवं फूलों की उच्च

गुणवत्ता वाली फसलें उगाकर बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत आकर्षक अनुदान प्रदान कर अधिकाधिक किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ रही है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो रही सुदृढ़

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर योजनाओं का विस्तार कर रही है, जिसके अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों तथा पॉलीहाउस जैसी आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन प्रयासों से किसान अब केवल श्रमिक नहीं रहे, बल्कि तकनीक, नवाचार और उद्यमशीलता से जुड़कर कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं। गांवों में आए परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि सरकारी योजनाएं केवल कागजी नहीं हैं, बल्कि वास्तविक रूप से किसानों के जीवन में सुधार ला रही हैं, जहां पहले सीमित उत्पादन और आर्थिक असुरक्षा थी, वहां अब आधुनिक तकनीक से समृद्धि और बेहतर उत्पादन संभव हो रहा है। ■

सफलता की कहानी

नवाचार और मेहनत से खेती में समृद्धि

बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति अरथुना की ग्राम पंचायत रैयाना के गांव भरडाजाल के किसान वीरराज सिंह पुत्र गुणवन्त सिंह सिसोदिया ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि सही सोच और मेहनत से खेती को भी समृद्धि का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने पॉलीहाउस तकनीक अपनाई और कृषि विभाग की योजनाओं से जुड़कर टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों का उन्नत उत्पादन शुरू किया, जिससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता और अधिक आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही उन्होंने खुले खेतों में आलू, मूंगफली, मिर्च और तरबूज जैसी फसलों का विविधीकरण कर अपनी आय के स्रोत बढ़ाए।

कल्पना डिंडोर, उप निदेशक

आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और सही सिंचाई प्रबंधन से उनकी फसलें सफल रहीं और उन्हें बाजार में अच्छे दाम मिले। आज वीरराज सिंह न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं बल्कि अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं, जहां आसपास के किसान उनसे नई कृषि तकनीकें सीखने आते हैं। उनका मानना है कि यदि किसान नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ लें तो खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है और यह सफलता आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप नवाचार और आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ■

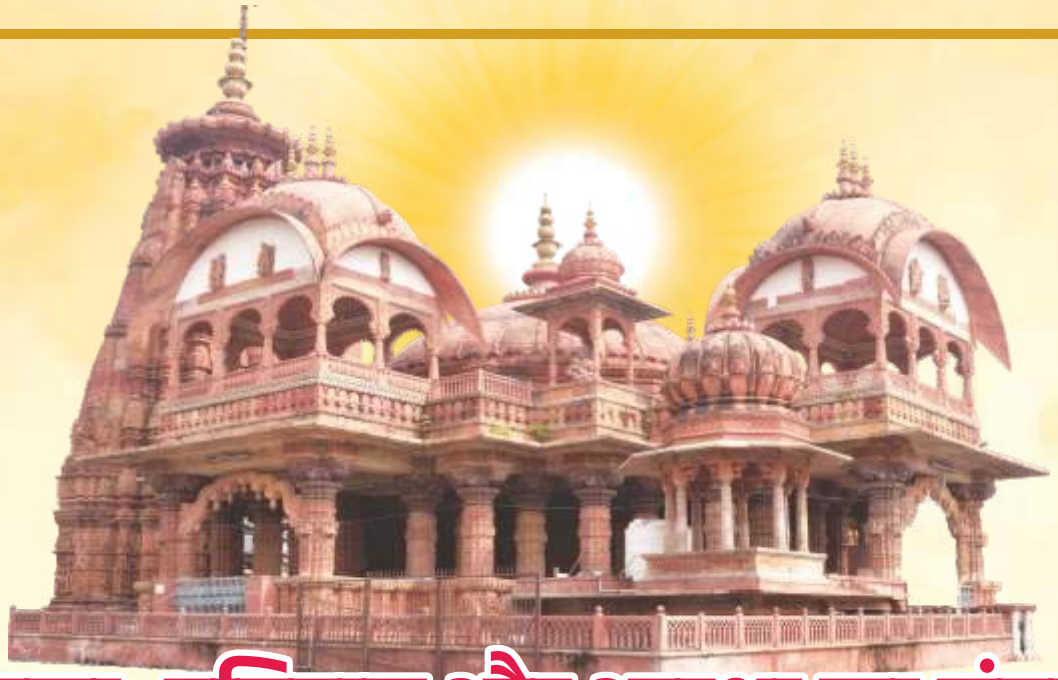

कला, इतिहास और आस्था का संगम
झालरापाटन का सूर्य मंदिर

राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित झालरापाटन सूर्य मंदिर न केवल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति है, बल्कि यह आध्यात्मिक आस्था का भी केंद्र है। प्राचीन भारत में सूर्य देवता की उपासना के लिए कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया और यह मंदिर भी उन्हीं में से एक है। इसकी अद्भुत वास्तुकला, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसे राज्य की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल करती है। यह भव्य मंदिर 9वीं–10वीं शताब्दी के दौरान निर्मित माना जाता है। इसका निर्माण प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत अद्वितीय माना जाता है। इसे 'पद्मनाभ मंदिर' तथा 'बड़ा मंदिर' के नाम से भी जाना जाता है।

हेमन्त छीपा, जनसंपर्क अधिकारी

स्थापत्य और शिल्प सौंदर्य

मंदिर की संरचना कच्छपघात शैली में निर्मित है और इसका मुख्य शिखर लगभग 98 फीट ऊंचा है। कमल के आकार में बने इस शिखर की विशेषता यह है कि यह स्वर्ग के देवी-देवताओं को आमंत्रित करता प्रतीत होता है। इसके अलावा, मंदिर में तीन अलग-अलग शिखर मौजूद हैं- प्रभामंडप, सभामंडप और गर्भगृह के ऊपर। सभामंडप को 52 सुंदर स्तंभों से सजाया गया है, जिन पर कीचक, घटपल्लव, मकराकृतियां और विविध देव आकृतियों का अंकन किया

गया है। मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर गणेश जी, योगनारायण और विभिन्न धार्मिक प्रतीकों को उकेरा गया है।

मूर्ति कला और धार्मिक महत्व

मंदिर के गर्भगृह में पद्मनाभ (भगवान विष्णु) की काले पाषाण से बनी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिर के पश्चिमी भाग में पारसी शैली में निर्मित त्रिमुखी सूर्य देवता की मूर्ति स्थापित है। इस प्रतिमा की अनूठी विशेषता यह है कि इसमें सूर्य देव कवच पहने, मुकुट धारण किए और जूते पहने हुए दर्शाए गए हैं। यह उनकी दिव्यता और अपूर्वता को दर्शाता है। मंदिर के पीछे स्थित दीवारों पर विष्णु अवतारों वराह, नृसिंह और श्रीकृष्ण की विभिन्न मुद्राओं में सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। साथ ही, शिव-पार्वती, गणेश, सप्त मातृकाएं, दिग्पाल और अन्य देवी-देवताओं की मनमोहक आकृतियां भी यहां देखी जा सकती हैं।

सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व

झालरापाटन का सूर्य मंदिर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर स्थापत्य कला प्रेमियों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित करता है। इसकी तुलना कई इतिहासकारों ने खजुराहो के मंदिरों से की है। यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की नक्काशी, विशाल प्रवेशद्वार और मूर्तिकला इसकी भव्यता को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। यदि आप राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों को देखना चाहते हैं, तो यह मंदिर अवश्य देखने योग्य स्थान है।

झालरापाटन का सूर्य मंदिर न केवल स्थापत्य और कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है। इसकी भव्य संरचना, शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्व इसे राजस्थान के सबसे अनूठे मंदिरों में स्थान दिलाते हैं। ■

PRIDE OF JAIPUR

The Amber Fort

Hemant Singh, Deputy Director

Keeping in view the geographical diversity, natural resources, and rich cultural heritage of Rajasthan, the "Panch Gaurav" programme was launched on 15 December 2024. The initiative aims to strengthen Rajasthan's economy by promoting district-based products, heritage, tourism, and innovation while ensuring sustainable development and greater public participation. Under the "One District One Tourist Destination" initiative, Amber Fort has been identified as one of the Panch Gauravs of Jaipur district. Amber Fort is recognised as one of the world's finest tourist destinations and a UNESCO World Heritage Site.

Amber was once the capital of the Kachhwaha Rajputs. In the 11th century, Dulahrai (Dhola), established the foundation of the Kachhwaha dynasty in the Dhundhar region. The construction of the present palace complex began in the late 16th century under Raja Man Singh-I. Later, Mirza Raja Jai Singh-I and Sawai Jai Singh-II introduced several modifications and additions according to the requirements and artistic preferences of their respective periods.

Jaleb Chowk

After entering through Suraj Pol or Chand Pol Gate, one steps into Jaleb Chowk, the parade ground of the Amber Palace. Near Singh Pol is the temple dedicated to Goddess Durga, popularly known as Shila Mata Temple. The idol, believed to represent Durga Mahishasuramardini, was brought from Jessore, present-day Bangladesh, by Raja Man Singh I in 1604.

Later, Sawai Man Singh II extensively decorated the temple with marble carvings and silver doors depicting the nine forms of Goddess Durga and the ten Mahavidyas. To the left of the temple stands the grand wooden gateway known as Singh Pol, followed by another wooden gateway, creating a double defence system for the palace.

Diwan-i-Aam

The roof presents a straight-line effect externally, while the interior ceiling is dome-shaped. It was constructed during the reign of Mirza Raja Jai Singh I (1621–1667 AD). Behind the main structure is Majlis Vilas, built during the reign of Sawai Ram Singh II (1835–1880 AD). This section displays distinctive Indo-European architectural features. Towards the east are open verandahs that were used as offices, while in front of them are two-storeyed servants' quarters constructed during the mid-19th century.

Ganesha Pol

On the southern side stands the magnificent Ganesha Pol, the main entrance to the palace complex, which also housed godowns, toilets, kitchens, water tank and Persian-style hammams (baths). This splendid gateway is adorned with Indo-Persian frescoes, with Lord Ganesha prominently decorating the façade. Inside the inner courtyard are two richly decorated buildings separated by a garden laid out in the Mughal Charbagh style with beautiful fountains.

Sheesh Mahal

On the eastern side of the garden stands one of the most enchanting sections of the palace - Jai Mandir or Diwan-i-Khas (Hall of Private Audience), also known as Sheesh Mahal or the Hall of Mirrors. Its walls and ceilings are embedded with convex mirrors arranged in exquisite patterns. The marble pillars and walls are inlaid with black stone from Bhainslana. The interiors of Sheesh Mahal display exquisite lattice work depicting scenes from the life of Radha and Krishna through stained glass and metal craftsmanship.

Sukh Niwas

Opposite Sheesh Mahal lies Sukh Niwas, designed as a pleasure pavilion with an ingenious water-cooling system. Water once flowed through a lattice channel here, naturally cooling the surroundings. Towards the northern verandah stands a stone pedestal from where homage was paid to the Sun God. On the eastern side is a large open courtyard popularly known as "Chandani," which served as a dancing courtyard during the 17th century.

Man Singh Mahal

The Chandani courtyard leads to the terrace above Sheesh Mahal and further to Jas Mandir, which served as a summer retreat where perforated water pipes allowed water to flow gently over khus (perfumed grass) curtains at the doorways, creating a natural cooling effect.

Built of stone, Man Singh Palace features elegant archways and jharokhas and served as the personal residence of Raja Man Singh I. The walls and doors are decorated with paintings depicting religious themes, as the palace also functioned as his private prayer chamber. The palace opens into a central courtyard surrounded by 12 apartments built for his 12 queens, with a baradari at the centre and a large underground water tank in the north-eastern corner supplying water to the apartments.

Kesar Kyari

Mohan Bari, situated amidst Maotha Lake, is popularly known as Kesar Kyari. Raja Man Singh I is believed to have planned the cultivation of saffron here around 1600 AD so that its fragrance could spread throughout the palace. Located on an island in the middle of Maotha Lake, Kesar Kyari is laid out in three levels with geometrical plantation patterns. The water-lifting system from Maotha Lake to the palace is considered an excellent example of engineering skill.

Tourists across the world can book online tickets through the Rajasthan Archaeology Department's official website: museumsrajasthan.rajasthan.gov.in. According to the Rajasthan Tourism Department, a total of 21,20,156 tourists visited Amber Fort during the financial year from 1 April 2025 to 31 March 2026. Among them, 18,87,184 were domestic tourists, while 2,32,972 were foreign tourists. ■

स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट से साकार हो रहा स्वच्छ जयपुर का सपना

धर्मिता चौधरी, सहायक निदेशक

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ कचरा प्रबंधन बड़े शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। राजधानी जयपुर ने इस चुनौती का समाधान आधुनिक एवं वैज्ञानिक कचरा निस्तारण प्लांटों की स्थापना के माध्यम से किया है। इन प्लांटों द्वारा कचरे का प्रभावी निस्तारण करने के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन, रीसाइक्लिंग, पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों के पुनः उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्वच्छ, सुव्यवस्थित और कचरा मुक्त जयपुर की दिशा में निरंतर प्रयास

नगर निगम जयपुर बदलते समय के साथ निरंतर प्रगति कर रहा है। निगम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं सुंदर जयपुर के सपने को साकार करना है। शहर को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाए रखने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना भी निगम की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

2200 टन कचरे के प्रभावी निस्तारण की बड़ी जिम्मेदारी

नगर निगम जयपुर में 13 जोन एवं 150 वार्ड हैं। शहर में लगभग 8 लाख 95 हजार 837 घर हैं, जहां से नगर निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्रतिदिन लगभग 2200 टन कचरा एकत्रित किया जाता है। इतने बड़े स्तर पर कचरा संग्रहण एवं उसके प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नगर निगम जयपुर ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

निगम ने एक दिवसीय 'सफाई सेवा मैराथन-2026' अभियान चलाकर एक दिन में 6000 टन कचरा उठाकर शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही 'रंग दे गुलाबी' अभियान के माध्यम से एक दिन में 500 से अधिक दीवारों पर चित्रकारी कर एतिहासिक उपलब्धि भी दर्ज की तथा रात्रिकालीन एक दिवसीय विशेष सफाई अभियान 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के माध्यम से परकोटा क्षेत्र को स्वच्छ व सुन्दर बनाया गया।

मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन से सुदृढ़ हो रही कचरा प्रबंधन व्यवस्था

कचरा प्रबंधन व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए झालाना डूंगरी में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है। यह ट्रांसफर स्टेशन ठोस कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कचरा संग्रहण वाहनों से कचरा इन स्टेशनों पर लाया जाता है और फिर बड़े डंपरों में स्थानांतरित किया जाता है। इससे ईंधन की बचत होती है, समय कम लगता है तथा वाहनों का घिसाव भी कम होता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया परिवहन लागत कम कर कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक है।

दिल्ली रोड पर आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन की शुरुआत

दिल्ली रोड पर स्थापित आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन ने हाल ही में कार्य प्रारंभ किया है। इस स्टेशन की प्रतिदिन 100 टन कचरा निस्तारण क्षमता है। इसके लिए 2 स्टैटिक कॉम्पेक्टर मशीनें, 3 हुक लोडर तथा 6 कंटेनर लगाए गए हैं। कमांड एवं कन्ट्रोल सेंटर के माध्यम से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके साथ ही नवाचार करते हुये नगर निगम ने कबाड़ से भी कमाल किया है और कबाड़ पड़ी हुई वस्तुओं से 3 'वेस्ट-टू वंडर' पार्क बनाये गये है। जिसके अन्तर्गत स्टोन पार्क मानसरोवर, पॉड्रिग पार्क हवामहल, द्वारकादास पार्क मानसरोवर में बेकार लोहे, प्लास्टिक से अनोखी कला-कृतियां बनाई गई है।

वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट से हो रहा ऊर्जा उत्पादन

नगर निगम जयपुर द्वारा 1000 टीपीडी क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी

“ ‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ राजस्थान’ के असली स्तंभ हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, जो दिन-रात निष्ठा, समर्पण और मेहनत से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

प्लांट संचालित किया जा रहा है, जिसका दैनिक विद्युत उत्पादन लगभग 12 मेगावाट है। लांगड़ियावास क्षेत्र में स्थित यह प्लांट जयपुर शहर के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट बन चुका है। यहां प्रतिदिन लगभग 1000 टन मिश्रित कचरे का निस्तारण कर उससे करीब 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जो शहर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है।

सी एंड डी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट

लांगड़ियावास स्थित सेंट्रलाइज्ड सी एंड डी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट द्वारा निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। यह प्लांट निर्माण संबंधी अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) प्लांट

लांगड़ियावास स्थित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) प्लांट सूखे कचरे के पृथक्करण एवं रीसाइक्लिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां प्रतिदिन लगभग 300 टन सूखा कचरा एकत्रित कर उसका वर्गीकरण किया जाता है। इससे पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग कर दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है।

मथुरादासपुरा डंपिंग यार्ड में बायोरेमेडिएशन प्रोजेक्ट

मथुरादासपुरा डंपिंग यार्ड में वर्षों से जमा लीगेसी वेस्ट एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुका था। नगर निगम द्वारा यहां बायोरेमेडिएशन एवं बायोमाइनिंग प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके माध्यम से पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है।

सेवापुरा बायोरेमेडिएशन एवं कम्पोस्ट प्लांट

सेवापुरा में स्थापित बायोरेमेडिएशन एवं कम्पोस्ट प्लांट में प्रतिदिन लगभग 250 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। यहां आधुनिक तकनीक के माध्यम से कचरे को रिसाइकिल कर जैविक खाद तैयार की जाती है, जो कृषि कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो रही है।

कचरे से तैयार हो रहे उपयोगी उत्पाद

इन अत्याधुनिक कचरा निस्तारण प्लांटों में कचरे को पूरी तरह संसाधन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। जो कचरा कभी शहर के लिए समस्या था, वही अब बिजली, जैविक खाद, निर्माण सामग्री, धातु उत्पाद एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित हो रहा है। ■

नवाचारों से सशक्त होती शिक्षा व्यवस्था

आकांक्षा पालावत, जनसम्पर्क अधिकारी
प्रशांत सिंह, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के माध्यम से आधुनिक बनाया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर सक्षम और आत्मविश्वासी बनाने वाली भविष्य उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकसित करना है। इसी दिशा में राजस्थान तकनीक आधारित शिक्षण, डिजिटल मूल्यांकन और डेटा आधारित शैक्षणिक सुधारों में अग्रणी बन रहा है। जोधपुर इसका प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है, जहां तकनीकी नवाचारों के माध्यम से शिक्षा, सुशासन और प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

शिक्षा सुधारों की नई शुरुआत - प्रथम चरण ने रखी मजबूत नींव

जिला प्रशासन द्वारा एआई आधारित शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की वास्तविक क्षमता और विषयगत समझ का आकलन करना था। प्रथम चरण में डिजिटल मूल्यांकन, डेटा विश्लेषण और सीखने की कमियों की पहचान जैसे प्रयोग सफल रहे। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सटीक बनी तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति का बेहतर विश्लेषण संभव हुआ। साथ ही, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जागरूक संवाद बढ़ा। विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग के माध्यम से विद्यार्थियों की चुनौतियां और सुधार की संभावनाएं स्पष्ट हुईं, जिससे यह पहल शिक्षा में गुणात्मक सुधार का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी।

द्वितीय चरण में बना राष्ट्रीय स्तर का मॉडल

प्रथम चरण की सफलता के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में जोधपुर में एआई आधारित मूल्यांकन परियोजना का दूसरा चरण बड़े स्तर पर लागू किया गया। इसे जिले के सभी 15 ब्लॉकों तक विस्तारित किया गया, जहां तीन दिनों में 70 हजार से अधिक विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तीन लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एआई आधारित स्मार्ट पेपर एप्लीकेशन से कुछ ही समय में पूरा हुआ, जबकि पारंपरिक प्रक्रिया में कई सप्ताह लगते थे। इस नवाचार से शिक्षकों का कार्यभार कम हुआ तथा मूल्यांकन अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी बना। इसके परिणामस्वरूप जोधपुर शिक्षा में तकनीकी नवाचार और प्रशासनिक दक्षता का राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली मॉडल बनकर उभरा।

पारदर्शी, निष्पक्ष और विद्यार्थी केंद्रित मूल्यांकन व्यवस्था

इस परियोजना में वस्तुनिष्ठ के साथ-साथ वर्णनात्मक उत्तरों का मूल्यांकन भी एआई आधारित प्रणाली से किया गया। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) द्वारा तैयार किए गए, जबकि पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया मानकीकृत और स्वचालित रही। इससे मूल्यांकन में देरी, अंकन में असमानता और गुणवत्ता संबंधी अंतर जैसी समस्याओं का समाधान हुआ तथा शिक्षा व्यवस्था अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी। इस मॉडल की बड़ी उपलब्धि यह रही कि विद्यार्थियों की विषयवार और अध्यायवार कमजोरियों का सूक्ष्म विश्लेषण संभव हुआ, जिससे शिक्षकों को सुधारात्मक शिक्षण योजनाएं बनाने में सहायता मिल रही है।

विद्यार्थियों की वास्तविक दक्षताओं को मिल रही पहचान

मुख्यमंत्री श्री शर्मा की शिक्षा नीति विद्यार्थियों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसी के तहत जोधपुर मॉडल केवल अंक आधारित मूल्यांकन तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता, विश्लेषण कौशल, अवधारणात्मक समझ और व्यवहारिक दक्षताओं का भी आकलन करता है। विद्यार्थियों को विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कार्ड दिए जा रहे हैं, जिनमें उनकी विषयवार प्रगति और सुधार की आवश्यकताओं का उल्लेख होता है। वैज्ञानिक सोच, सांख्यिकीय समझ, संवैधानिक जागरूकता और संख्यात्मक

विश्लेषण जैसी क्षमताओं के मूल्यांकन से शिक्षा को नई दिशा मिल रही है। साथ ही, शिक्षकों को डेटा आधारित जानकारी मिलने से वे अधिक प्रभावी और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धतियां अपनाने में सक्षम हो रहे हैं।

अभिभावकों की सहभागिता से मजबूत हो रही जवाबदेही

जोधपुर मॉडल में अभिभावकों की सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अभिभावक-शिक्षक बैठकों (PTM) के माध्यम से विद्यार्थियों और विद्यालयों की विस्तृत रिपोर्ट अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों और ग्राम पंचायतों के साथ साझा की जाएगी। एआई आधारित रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों की वास्तविक सीखने की स्थिति और विषयगत दक्षताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जिससे अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को बेहतर ढंग से समझने और विद्यालयों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में सहायता मिलती है। यह पहल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, सामुदायिक सहभागिता और जवाबदेही को मजबूत बना रही है।

समन्वित प्रयासों से मिली ऐतिहासिक सफलता

इस परियोजना की सफलता जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और तकनीकी सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, एडऑप्टिमाइज और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तकनीकी सहयोग से परियोजना को मजबूती मिली। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर यह सुनिश्चित किया गया कि सभी विद्यालयों तक इस नवाचार का लाभ पहुंचे।

राजस्थान की नई पहचान बनता जोधपुर मॉडल

जोधपुर की एआई आधारित शैक्षिक मूल्यांकन पहल आज राजस्थान में तकनीक आधारित सुशासन और शिक्षा सुधारों का मजबूत उदाहरण बन चुकी है। यह मॉडल दर्शाता है कि दूरदर्शी नेतृत्व, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और आधुनिक तकनीक के समन्वय से सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव संभव हैं। अब यह पहल सीखने के परिणामों और विद्यालयीय प्रदर्शन के सार्वजनिक प्रकटीकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक सहभागिता को मजबूती मिलेगी। इन तकनीक आधारित नवाचारों के कारण जोधपुर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है और यह मॉडल भविष्य में देशभर के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है। ■

अब सड़कों पर खौफ नहीं, सुरक्षा है

महिला सुरक्षा की मजबूत ढाल बनी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट

डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट आज महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में स्थापित हो चुकी है। महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, पीछा करने (स्टॉकिंग) जैसी घटनाओं में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह यूनिट सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। 'कालिका' का अर्थ ही शक्ति और न्याय है, जो मनचलों के लिए चेतावनी और सभ्य समाज के लिए सुरक्षा का आश्वासन है।

त्वरित सहायता, हर पल सुरक्षा

राज्य स्तर पर संचालित 1090 महिला हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और आपातकालीन सहायता कॉल पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को सहायता उपलब्ध कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता सुनिश्चित करना है। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद संबंधित जिले की यूनिट को तत्काल डिस्पैच किया जाता है और मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

सुरक्षा का भरोसा, त्वरित कार्रवाई का संकल्प

कालिका यूनिट केवल आपातकालीन सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग कर महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास मजबूत कर रही है। इससे असामाजिक तत्वों में पुलिस की सक्रियता का संदेश जाता है और अपराधों पर अंकुश लगता है।राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत यह यूनिट त्वरित रिस्पॉन्स, काउंसलिंग, शिकायत पंजीकरण और आवश्यक कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जरूरत पड़ने पर संबंधित थाने में सीसीटीएनएस मॉड्यूल के माध्यम से मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाती है। तकनीक और संवेदनशील पुलिसिंग के समन्वय से संचालित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट आज महिलाओं के लिए भरोसे, सुरक्षा और त्वरित सहायता का मजबूत प्रतीक बन चुकी है।

कार्यप्रणाली - सादी वर्दी, पैनी नज़र

इस टीम की विशिष्टता इसकी कार्यशैली में निहित है। कालिका टीम के सदस्य अक्सर सादे कपड़ों में तैनात रहते हैं, जिससे वे भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों के बाहर आम नागरिकों के बीच घुल-मिल जाते हैं। यह 'सरप्राइज एलिमेंट' अपराधियों के लिए काल साबित होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बगल में खड़ा व्यक्ति पुलिस का हिस्सा है। जैसे ही कोई अप्रिय घटना या छेड़छाड़ की कोशिश होती है, टीम तुरंत सक्रिय होकर आरोपी को दबोच लेती है।

हॉटस्पॉट पर निगरानी और त्वरित प्रहार

रणनीतिक रूप से कालिका टीम उन स्थानों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, जिन्हें 'हॉटस्पॉट' माना जाता है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गर्ल्स हॉस्टल के आसपास की गलियां और पार्क इनकी निरंतर निगरानी में रहते हैं। बीट कांस्टेबल और स्थानीय सूचना तंत्र के साथ तालमेल बिठाकर यह टीम समय-समय पर 'एरिया डोमिनेंस' अभियान चलाती है, जिससे मनचलों में कानून का भय पैदा होता है और महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ती है।

काउंसलिंग और सुधारात्मक दृष्टिकोण

कार्रवाई के साथ-साथ यह टीम एक सुधारात्मक भूमिका भी निभाती है। कई बार कम उम्र के युवकों द्वारा की गई छोटी गलतियों पर टीम उन्हें और उनके अभिभावकों को बुलाकर उचित काउंसलिंग करती है। उन्हें कानूनी परिणामों के प्रति सचेत किया जाता है, ताकि वे भविष्य में अपराध की राह पर न बढ़ें। वहीं, गंभीर मामलों में टीम बिना किसी देरी के सख्त कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर त्वरित न्याय सुनिश्चित करती है।

सामाजिक प्रभाव और भविष्य की राह

आज कालिका टीम की सक्रियता का परिणाम है कि राजस्थान के शहरों और कस्बों में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। कोचिंग हब जैसे कोटा और जयपुर में रहने वाली बाहरी छात्राओं के लिए यह टीम अभिभावक की तरह सुरक्षा और भरोसा प्रदान कर रही है। तकनीक और मानवीय संवेदना के समन्वय से चल रही कालिका टीम की यह मुहिम आधुनिक पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो सुरक्षित समाज के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। ■

महिला बीट अधिकारी की भूमिका

महिला बीट अधिकारी महिला सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनका कार्य क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं से नियमित संपर्क बनाए रखना, उनकी समस्याओं को सुनना और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है।

मुख्य जिम्मेदारियां

- क्षेत्र की महिलाओं से संवाद स्थापित करना।
- छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, साइबर उत्पीड़न जैसी समस्याओं पर तत्काल मार्गदर्शन देना।
- संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर निगरानी रखना।
- स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- 1090 हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करना।

महिला बीट अधिकारी का उद्देश्य केवल शिकायत लेना नहीं, बल्कि महिलाओं में सुरक्षा, विश्वास और कानूनी जागरूकता बढ़ाना भी है। यही वजह है कि यह व्यवस्था महिला सुरक्षा अभियान का जमीनी आधार बन रही है।

नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका

से अनूठी बनी राजस्थान विधानसभा

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा, उप निदेशक

राजस्थान विधानसभा में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका का अभिनव सृजन किया गया है। यह वाटिकाएं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, प्राचीन ज्योतिषीय ज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का सजीव उदाहरण हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पहल से यह नवाचार हुआ है। विधानसभा में दोनों वाटिकाओं का उद्घाटन 5 मई को 6 राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) के स्पीकर्स ने किया।

नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्रों के पौधे

नक्षत्र वाटिका की अवधारणा भारतीय ज्योतिष के 27 नक्षत्रों पर आधारित है। ज्योतिष में प्रत्येक नक्षत्र का संबंध एक विशिष्ट वृक्ष से माना गया है। इसके लिए विधानसभा के दक्षिण भाग में दोनों पार्किंग के मध्य 5 हजार वर्ग मीटर अर्ध चन्द्राकार उद्यान विकसित किया गया है। इस वाटिका में 27 नक्षत्रों अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगसिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती से संबंधित प्रमुख वृक्षों क्रमशः कुचला, आंवला. गूलर, जामुन, खैर, शीशम, बांस, पीपल, नागकेसर, बरगद/बट, पलाश, पाकड़, रीठा/चमेली, बेल, अर्जुन, कटारी, मौलश्री, चौड/संभल, साल, जलवेतर/अशोक, कटहल, शमी/आक, मदार/शमी, कदंब, आम, नीम, महुआ का रोपण किया गया है। इन पौधों का नौ ग्रहों, बारह राशियों और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से भी संबंध है।

प्रकृति और खगोल विज्ञान का अदभुत संगम

नक्षत्र वाटिका प्रकृति और खगोल विज्ञान का अद्भुत संगम है। नक्षत्र वाटिका भारतीय ज्योतिष एवं आयुर्वेद की समृद्ध परम्परा को समर्पित एक अनूठी संकल्पना है। यह वाटिका प्रकृति और खगोल विज्ञान के अद्भुत संगम को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है।

हर्बल वाटिका में 38 औषधीय पौधे

विधानसभा परिसर में 850 वर्ग मीटर में हर्बल वाटिका भी विशेष रूप से विकसित की गई है। इसके लिए विधानसभा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 8*13 फीट की सुव्यवस्थित 38 क्यारियों में 38 प्रजातियों के पौधे लगाये गये हैं। प्रत्येक क्यारी में एक प्रजाति के 20 पौधों का रोपण किया गया है। औषधीय पौधों में रोजमेरी, लौंग, समुद्र बेल, अजवाइन, बैजंती, पेपर-मिन्ट, पचोली, इंसुलिन, मेहंदी, पत्थरचट्टा, ओडोमास, केशवर्धनी, अश्वगंधा, सिट्रोनेला, कालमेघ, अग्निमन्थ, हड़जोड, ऐलोविरा (ग्वारपाठा), लेमनग्रास, वेटिवर ग्रास (खस), वेखंड (स्वीट फ्लैग), तुलसी, इलायची, पिपली, कपूर, गुंजा, दन्ती, मरवा, अक्कड़ काडा, स्टीविया, अजावृक्ष, सतावरी, रतनजोत, निरगुंडी, रेड अनुसा (लाल वासा), सर्पगंधा, पान या नागरबेल और ब्राह्मी शामिल है, जो आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

हर्बल वाटिका औषधीय ज्ञान का जीवंत केन्द्र

हर्बल वाटिका का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद के महत्व को रेखांकित करना है। यह औषधीय पौधों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता भी बढ़ाएगी। इस वाटिका में वैज्ञानिक पद्धति से क्यारियां निर्मित की गई हैं। यह वाटिका औषधीय ज्ञान के प्रसार के साथ-साथ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी प्रोत्साहित करेगी।

वाटिकाएं भारतीय ज्ञान परम्परा का प्रतीक

यह वाटिकाएं केवल एक उद्यान नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि लोगों को अपने जन्म नक्षत्र से जुड़े वृक्षों के प्रति जागरूक भी करेगी। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित इन आयुर्वेदिक वृक्षों के संरक्षण से आमजन को समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होगी।

आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और प्रकृति से होंगी परिचित

यह वाटिकाएं जैव विविधता को समृद्ध करने, औषधीय पौधों के संरक्षण और सकारात्मक वातावरण निर्माण में सहायक सिद्ध होंगी। साथ ही यह आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और प्रकृति के गहरे संबंध से परिचित कराने का एक प्रेरणादायक माध्यम भी बनेंगी। ■

श्री राव दूदा जी और पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोंसिंह शेखावत की

प्रतिमाओं का अनावरण

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नागौर जिले के मेड़ता में श्री राव दूदा मेड़तिया जी की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मीरा बाई के पेनोरमा का अवलोकन भी किया। इससे पहले उन्होंने श्री चारभुजा नाथ एवं मीराबाई मंदिर में दर्शन किए एवं देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की भूमि सदैव त्याग और राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा देती रही है। यहां पर घर-घर से फौजी देश की रक्षा के लिए सेना में जाते हैं। राव दूदा जैसे वीर शिरोमणि का जीवन नई पीढ़ी के लिए आदर्श है। उनका पूरा जीवन शौर्य और पराक्रम का जीता-जागता उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महापुरुषों का प्रदेशभर में पेनोरमा बनवाया जा रहा है। श्री महावीर जी पेनोरमा-करौली, श्री विद्यासागर जी महाराजा-अजमेर, भक्त शिरोमणि करमा बाई-डीडवाना, श्री जसनाथजी-बीकानेर, श्री खेमा बाबा-बालोतरा, श्री भामाशाह-चित्तौड़गढ़, श्री राव चंद्रसेन-जोधपुर का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं, बांदीकुई में संत श्री दुर्बलनाथ जी का पेनोरमा, सिवाना में वीर दुर्गादास तथा सलूंबर में हाड़ी रानी और अजमेर में महर्षि दयानन्द सरस्वती पेनोरमा का निर्माण भी किया जाएगा। खरनाल-नागौर में वीर तेजाजी पेनोरमा का विकास कार्य भी करवाया जाएगा।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोंसिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने

कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा की राजनीति के जीवंत प्रतीक थे। उनका सपना था कि राजस्थान के हर घर में खुशहाली हो, हर हाथ को काम मिले और हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। आज देश और राजस्थान दोनों ही विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और पूरा विश्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को स्वीकार कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्व. भैरोंसिंह शेखावत लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रहरी और वंचितों की आवाज तथा राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। उन्होंने जननायक के रूप में सदैव गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को धरातल पर उतारते हुए स्व. शेखावत ने अंत्योदय योजना शुरू की। स्व. भैरोंसिंह की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी, संघर्ष और समर्पण के बल पर महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने की प्रेरणा देगी। हमें उनके जीवन से लोकतंत्र की गरिमा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लेना चाहिए। ■

सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक विरासत एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक

झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय स्वाभिमान और अटूट आस्था का प्रतीक है। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सोमनाथ अमृत महोत्सव में मुख्यमंत्री वीसी के माध्यम से जुड़े और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में 'विकास भी, विरासत भी' की संकल्पना को धरातल पर साकार किया जा रहा है। देशभर में धार्मिक स्थानों के विकास कर सनातन संस्कृति के उत्थान का कार्य किए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारधाम पुनर्विकास, महाकाल लोक तथा धार्मिक स्थलों में विकास कार्यों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं तथा उन्होंने सोमनाथ मंदिर के विकास एवं संरक्षण के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ■

हुनरमंद युवाओं को मिल रहा वैश्विक मंच

विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए हुआ एमओयू

बिड़ला ऑडिटोरियम में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एमओयू कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार तथा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के मध्य विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एवं स्किल इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर जयपुर की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही, नेशनल एन्टरप्रेन्योर एम्पावरमेंट ड्राइव के अन्तर्गत भी विभिन्न एमओयू संपादित हुए। इससे पहले इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी के जर्नल का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कौशल विकास के विज़न को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने इंग्लिश एंव फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद और नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरशन के साथ एमओयू किए हैं। इसके माध्यम से हमारे युवाओं को फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन सीखने का अवसर मिलेगा। आज के युग में विदेशी भाषा सीखना आवश्यकता बन चुका है। विदेशी भाषा का ज्ञान युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेशों में रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। इसी तरह यह विदेशी पर्यटकों, उद्यमियों और प्रदेश के स्थानीय उद्योगों के बीच एक सेतु का कार्य भी करता है।

उन्होंने कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों की वजह से राजस्थान के लिए विदेशी भाषा का विशेष महत्व है। दुनिया भर से यहां सैलानी आते हैं। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश के कई अंचलों में पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। विदेशी भाषाएं जानने वाले गाइड, होटल मैनेजर, ट्रैवल एजेंट और व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में नये महाविद्यालयों के निर्माण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके लिए 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही, 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण किया गया है। ■

कर्नाटक लोकभवन में राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह

अपनी माटी से दूर रहकर भी संस्कृति को सहेजे हुए हैं प्रवासी राजस्थानी

बेंगलुरु स्थित लोक भवन में राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का स्थापना दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की पहचान, लोक परंपरा और अखण्डता का प्रतीक है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से राजस्थान स्थापना दिवस समारोह अंग्रेजी तारीख के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाये जाने की पहल की है।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान का सांस्कृतिक राजदूत बताते हुए कहा कि वे अपनी माटी से दूर रहकर भी प्रदेश की संस्कृति को सहेजे हुए हैं और परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं।वहीं, कर्मभूमि से जन्मभूमि जैसे अभियान में भी प्रवासी राजस्थानी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मातृभूमि के विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर, 2025 को जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से देश-विदेश में निवास करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाने का काम किया गया। ■

ओड समाज संवाद कार्यक्रम

जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ओड समाज संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ओड समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है तथा इसने राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान दिया है। श्रम, संस्कृति और स्वाभिमान इसकी पहचान हैं। इस समाज ने किलों और महलों के निर्माण में अपनी कुशलता दिखाई है तथा जल संरचनाओं के निर्माण की इनमें अद्भुत कला है। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में ओड समाज को बड़ी सौगात देते हुए रामदेवरा में धर्मशाला एवं जयपुर में छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पाक विस्थापित ओड समाज के लोगों की हर संभव सहायता करेगी।

पेयजल, कृषि और जनकल्याण योजनाओं पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं को धरातल पर उतार रही है। वहीं, किसानों को दिन में बिजली दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के लिए जनधन खाता, रसोई गैस सिलेण्डर, हर घर नल से जल, शौचालय निर्माण और

लखपति दीदी जैसी अनेक योजनाएं चलाई हैं। किसानों को सम्मान निधि तथा जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा एवं मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है।

श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने श्रम योगी मान-धन जैसी पेंशन योजना शुरू कर असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में सहारा दिया है। इसमें 27 हजार से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। उन्होंने चार नई श्रम संहिताएं लागू कर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्यस्थल की सुनिश्चितता की है। राज्य सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड के दस्तकारों को 5 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ऋण पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान के आदेश जारी किए हैं। अब तक 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा 53 हजार से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। ■

राजस्थान वीरों एवं रणबांकुरों की धरती

लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण एवं 'शौर्य के साथ संकल्प दिवस' कार्यक्रम चूरू में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण एवं उनकी जीवनी पर आधारित शिलापट्ट का अवलोकन किया। उन्होंने वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान वीरों एवं रणबांकुरों की धरती है। यहां के सपूतों ने अनेक युद्धों में वीरता एवं शौर्य का परिचय दिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ को नमन करते हुए कहा कि वीर भूमि के इस सपूत ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर साहस का अप्रतिम उदाहरण पेश किया। इन युगपुरुषों से युवाओं को दिशा मिलती है तथा इनकी शौर्य गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करेंगी।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा से नौजवानों को नई दिशा मिलेगी एवं आगामी पीढ़ी इससे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी।

सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम माथुर ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के बलिदान एवं साहस का जिक्र करते हुए कहा कि भारत-चीन युद्ध में नाथूला बॉर्डर पर उन्होंने दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने आजाद भारत की सेना में विभिन्न पदों पर अपना कौशल सिद्ध किया। ■

सुजस प्रश्नोत्तरी

प्रश्नोत्तरी नं. - 09

1. **विश्व की पहली मेट्रो सेवा कब प्रारंभ की गई थी?**
   A. 1850 B. 1863
   C. 1875 D. 1880

2. **संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है?**
   A. अंतरराष्ट्रीय कृषि वर्ष B. अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष
   C. अंतरराष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष D. अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण विकास वर्ष

3. **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कब की गई?**
   A. 15 अगस्त 2024 B. 11 अक्टूबर 2025
   C. 26 जनवरी 2025 D. 1 अप्रैल 2026

4. **सोनी जी की नसियां जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है?**
   A. अजीतनाथ जी B. पार्श्वनाथ जी
   C. ऋषभदेव जी D. मल्लिनाथ जी

5. **भारत में मेट्रो रेल का औपचारिक विकास किस वर्ष प्रारंभ हुआ?**
   A. 1975 B. 1984
   C. 1995 D. 2002

6. **विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?**
   A. 10 अक्टूबर B. 12 सितंबर
   C. 26 जून D. 10 दिसंबर

7. **राजस्थान एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2026 कब लागू की गई?**
   A. 15 अप्रैल 2026 B. 12 मार्च 2026
   C. 10 जनवरी 2026 D. 20 फरवरी 2026

8. **जनगणना-2027 के आधिकारिक शुभंकरों (Mascots) के नाम क्या हैं?**
   A. लक्ष्य और सफलता B. प्रगति और विकास
   C. शक्ति और विजय D. उमंग और उत्साह

9. **रिप्स 2024 के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की समय-सीमा को 60 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया गया है?**
   A. 45 दिन B. 15 दिन
   C. 30 दिन D. 20 दिन

10. **सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी (HPV) टीकाकरण के लिए अनिवार्य पंजीकरण हेतु किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है है?**
    A. को-विन (Co-WIN) B. यू-विन (U-Win)
    C. ई-संजीवनी (e-Sanjeevani) D. आरोग्य सेतु (Aarogya Setu)

11. **प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?**
    A. 15 जनवरी B. 10 दिसंबर
    C. 09 जनवरी D. 25 जनवरी

12. **राजस्थान के कितने गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है?**
    A. 32 हजार से अधिक B. 40 हजार से अधिक
    C. 42 हजार से अधिक D. 35 हजार से अधिक

13. **फलकू बाई का संबंध किस नृत्य से है?**
    A. चरी नृत्य B. गवरी नृत्य
    C. पणिहारी नृत्य D. चकरी नृत्य

14. **राजस्थानी चित्रकला की शैली में निम्नलिखित में से कौन-सी उपशैली मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है?**
    A. बूंदी शैली B. किशनगढ़ शैली
    C. अलवर शैली D. उदयपुर शैली

15. **भारत में 'मेट्रो मैन' किसे कहा जाता है?**
    A. ई. श्रीधरन B. बी. सी. रॉय
    C. वेरघीज कुरियन D. सैम पित्रोदा

16. **श्रीयादे पैनोरमा कहां बनाया जाना प्रस्तावित हैं?**
    A. जोधपुर B. जयपुर
    C. पाली D. अजमेर

17. **GOBARdhan योजना का पूरा नाम क्या है?**
    A. ग्रीन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स
    B. गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन
    C. गवर्नमेंट ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चर रिसोर्स
    D. ग्लोबल ऑर्गेनिक बायो एग्रो डेवलपमेंट

18. **देशभर में कितने माध्यमिक विद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है?**
    A. 10 हजार B. 12 हजार
    C. 15 हजार D. 20 हजार

19. **CBG का पूरा नाम क्या है?**
    A. कंबाइंड बायो गैस B. कंप्रेस्ड बायो गैस
    C. क्लीन बायो गैस D. कंट्रोल्ड बायो गैस

20. **Raj-MAMTA कार्यक्रम किससे संबंधित है?**
    A. बाल विकास B. कौशल विकास
    C. महिला सशक्तीकरण D. मानसिक स्वास्थ्य

प्रश्नोत्तरी नं. 08 के उत्तर एवं विजेताओं के नाम

प्रश्नोत्तरी नं. – 08 (उत्तर) 1(B) 2(C) 3(D) 4(C) 5(B) 6(A) 7(C) 8(B) 9(A) 10(C) 11(B) 12(C) 13(A) 14(C) 15(B) 16(C) 17(B) 18(B) 19(C) 20(A) 21(C)

मोनिका चौधरी
डीडवाना-कुचामन

पंकज कुमार
सीकर

लोकेश कुमार
नवलगढ़, झुंझुनूं

राज्य सरकार की प्रमुख गतिविधियों, योजनाओं तथा राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी के उत्तर 20 जून, 2026 तक अपने पूरे पते व मोबाइल नंबर सहित ईमेल द्वारा **sujasconnect@gmail.com** पर प्रेषित करें। प्राप्त प्रविष्टियों में से चयनित प्रतिभागियों के फोटो सहित नाम एवं सही उत्तर आगामी अंक में प्रकाशित कर सम्मान स्वरूप 'राजस्थान सुजस' मासिक पत्रिका नियमित रूप से उन्हें प्रेषित की जाएगी।

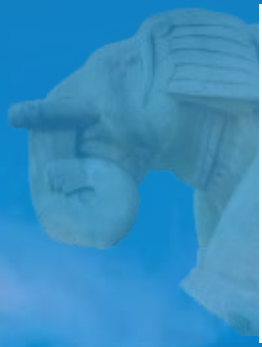

हाथी भाटा

टोंक जिले में ककोड़ के पास स्थित हाथी भाटा एक ही शिला को तराशकर बनाई गई विशाल हाथी की आकृति के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर मार्ग पर स्थित इस अद्भुत स्मारक की विशेषता शिला पर अंकित वह अभिलेख है, जिसमें राजा नल और दमयंती की कथा वर्णित है। कुछ लोक मान्यताओं में इस क्षेत्र को पांडवों के अज्ञातवास और वनगमन कथाओं से भी जोड़ा जाता है। इस स्मारक का निर्माण वर्ष 1200 में रामनाथ सलाट द्वारा सवाई रामसिंह के शासनकाल में कराया गया था।

राष्ट्रीय कृषि बाजार

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का एक दशक

राजस्थान की उपलब्धियां

- ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की शुरुआत 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर किसानों को देशभर के खरीदारों से जोड़ने के उद्देश्य से की गई।
- ई-नाम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नीलामी, पारदर्शी व्यापार, रीयल-टाइम मूल्य जानकारी और सीधे बैंक खातों में डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- ई-नाम 2.0 का नया संस्करण 12 फरवरी, 2026 से लागू किया गया, जिसमें स्वचालित बोली प्रणाली, मांग-आपूर्ति डेटा, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
- राजस्थान की 173 मंडियां ई-नाम से जुड़ी हुई हैं।
- राजस्थान में ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 15.55 लाख से अधिक किसान, 87,509 व्यापारी और 27,989 कमीशन एजेंट पंजीकृत हैं।
- प्रदेश के 546 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी ई-नाम से जुड़े हैं।
- राजस्थान में ई-नाम के जरिए 138 कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 से जनवरी, 2026 तक राजस्थान में 3.16 करोड़ मीट्रिक टन कृषि उपज का व्यापार हुआ, जिसकी कुल कीमत 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही।
- कुल आवक के मामले में राजस्थान देश में दूसरे तथा ई-ट्रेड में प्रथम स्थान पर रहा।
- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 134 ई-नाम मंडियों में एआई और एमएल आधारित गुणवत्ता जांच मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।
- डिजिटल भुगतान के तहत राजस्थान में 44,711 सौदों में 505 करोड़ रुपये से अधिक का ई-भुगतान हुआ, जिससे प्रदेश देश में चौथे स्थान पर रहा।
- ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना से जोड़कर किसानों और व्यापारियों को डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ई-नाम उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18002700224 उपलब्ध है।

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, राकेश शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - अजय कुमार, मैसर्स प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर से मुद्रित, (20,000 प्रतियां) 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 80, मूल्य 1.00 रुपये • अंक प्रतियां 1,00,000